(1100/CP/SR)

1101 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुईं)

...(व्यवधान)

(प्रश्न 101)

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): अध्यक्ष महोदया, महाराष्ट्र में बुलढाणा जिला सबसे पिछड़ा जिला है। बुलढाणा जिले में दो रेलवे स्टेशन हैं, एक शेगांव और दूसरा मलकापुर। इन दोनों स्टेशनों को आदर्श 'ए' ग्रेड मॉडल स्टेशन का दर्जा 2012-13 में दिया गया। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मॉडल स्टेशन के तहत स्टेशन पर कौन सी सुविधा देना वहां पर अपेक्षित था, अभी तक कितनी सुविधाएं वहां पर दी गईं?

अध्यक्ष महोदया, वहां स्टेशन पर कोई सुविधा नहीं है। प्रतीक्षालय के बारे में उत्तर में बताया कि हमने यह सुविधा दी। उत्तर में भी बहुत सारी गलतियां हैं। वहां प्रतीक्षालय ऐसा है कि वहां पर हम लोग बैठ भी नहीं सकते हैं। स्टेशन पर न तो स्वच्छता की कोई सुविधा है, वहां जनसुविधाएं भी बहुत कम हैं। बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट के पिछड़ा जिला होने के नाते मंत्री जी से मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि 2014-15 के बजट में पूंजी निवेश कार्यक्रम के तहत खमगांव और जालना रेलवे के लिए 3000 करोड़ रुपये की प्रशासकीय मान्यता दी गई थी, लेकिन अभी तक वहां कुछ भी काम नहीं हुआ। वह काम कब होने वाला है? पूंजी निवेश कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी है?

माननीय अध्यक्ष : कितने प्रश्न पूछेंगे? बैठिए।

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): अध्यक्ष महोदया, राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी है और केन्द्र सरकार उसमें कौन सी भूमिका निभाने वाली है? रास्ते के लिए वहां सौ साल से लोगों का आंदोलन चल रहा है, अभी भी वहां आंदोलन चल रहा है। ये मॉडल स्टेशंस कब अपग्रेड किए जाएंगे? खमगांव और जालना रेलवे मार्ग का काम कब शुरू होगा? मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा। …(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल: इंडियन रेलवेज ने देश भर के सभी रेलवे स्टेशंस को कैटेगराइज करके, उसमें क्या-क्या सुविधायें बढ़ाई जा सकती हैं, कितने वहां पर पैसेंजर्स हैं, यात्रियों की संख्या, वहां की अर्निंग्स को देखते हुए अलग-अलग मॉडल्स पर रेलवे स्टेशंस को अपग्रेड किया है। मलकापुर एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है। यहां लगभग 74 मेल एक्सप्रेस ट्रेंस और पैसेंजर ट्रेंस रुकती हैं। लगभग 4,967 पैसेंजर्स रोज वहां ट्रेनों पर चढ़ते हैं और लगभग 3 लाख 35 हजार रुपये रोज की वहां पैसेंजर्स अर्निंग है। उस हिसाब से देखें तो यह पहले ‘बी’ कैटेगरी स्टेशन होता था। अर्निंग्स कम होने के कारण अब वह एनएसजी-4, नॉन सबअर्बन ग्रुप में चौथे दर्जे का स्टेशन अर्निंग्स के हिसाब से बना है। इसके बावजूद इसको आदर्श स्टेशन के रूप में चुना गया, चिह्नित किया गया। उसमें *फसाड* को सुधारना, सर्कुलेटिंग एरिया को सुधारना कि आने-जाने के लिए सुविधा हो, एक टॉवर लगाया गया लाइन एल्युमिनेशन के लिए। इसी प्रकार से वाटर बूथ, पे एंड यूज टॉयलेट बनाया गया। रिटायरिंग रूम के बारे में आपने मुझे अभी बताया। अगर उसमें कुछ कमी है, तो मैं डिविजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर से रिपोर्ट लेकर उस पर कार्रवाई करूंगा। प्लेटफार्म सरफेस को ठीक किया गया। बुकिंग आफिस को सुधारा गया। …(व्यवधान) ये सब काम वहां किए गए।

(1105/NK/UB)

अभी मेरे पास दूसरे स्टेशन की जानकारी नहीं है, यह उस प्रश्न में नहीं था। मैं उनको जानकारी पहुंचा दूंगा। जहां तक जालना की लाइन का सवाल है, दुर्भाग्य से पहले रेलवे का राजनीतिकरण ज्यादा होता था। देश में इतनी सारी योजनाओं की घोषणा कर दी गई कि जिसको सफिशिएंट बजट ही नहीं है कि सभी रेलवे की परियोजनाओं पर एक साथ काम चल सके। हमने यह कोशिश की कि जहां-जहां जमीन अधिग्रहण हो चुका है, जमीन एवेलबल है और ज्यादा एसेन्शियल लाइन है जिससे ओवरऑल ट्रैफिक अनक्लॉग होगा और ज्यादा अधिक मात्रा में रेलवे जनता को सुविधा दे पाएगी, उसको प्राथमिकता देते हुए अलग-अलग प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की जानकारी माननीय सदस्य को मेरा दफ्तर भेज देगा।

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने बताया कि वहां की अर्निंग कम है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वहां पर बहुत दिनों से लंबे रूट की ट्रेनों को रोकने के लिए मांग की जा रही है, वहां रेलवे का स्टॉपेज नहीं है। जब वहां ज्यादा ट्रेनें नहीं रुकेंगी तो अर्निंग कैसे बढ़ेगी। सेगाँव स्टेशन पर संत गजानन महाराज जी का बहुत बड़ा मंदिर है। वहां हर रोज रेलवे से पच्चीस से तीस हजार लोग आते हैं लेकिन वहां स्टॉपेज नहीं होने की वजह से लोग अकोला स्टेशन से बैठते हैं नहीं तो भुसावल स्टेशन से बैठते हैं। इसलिए अर्निंग जो दिखनी चाहिए वह नहीं दिखती है। क्या स्टॉपेज की मांग को बढ़ाया जाएगा?

श्री पीयूष गोयल : अध्यक्ष महोदया, मैंने अभी बताया, 74 ट्रेनें मलकापुर में रुकती है। उसमें 86 मेल एक्सप्रेस ट्रेन हैं, 6 पैसेजर्स ट्रेन हैं, उसके बावजूद अगर पांच हजार से कम पैसेजर्स हैं तो ऑल ट्रेन रोकने का सवाल ही नहीं उठता।

दूसरी बात, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं। सभी माननीय सदस्यों की मांग रहती है कि हमारे स्टेशनों पर अधिक गाड़िया रुकें, गाड़ी रोकने का मतलब यह नहीं है कि केवल एक-दो मिनट का स्टॉप है, गाड़ी आहिस्ता होती है, रुकती है फिर आहिस्ता-आहिस्ता चल कर स्पीड पकड़ती है। जब तक गाड़ी स्टेशन से नहीं निकलती, अगले स्टेशन से गाड़ी सेफ्टी की दृष्टि से शुरू नहीं हो सकती। ऐसी परिस्थिति में जितना ज्यादा स्टॉप एड करते जाएंगे, उतना ज्यादा रेलवे की कैपिसिटी कन्सट्रेंट बढ़ रही है। उसके कारण आगे रेलवे में विलंब होगा, पंक्चुअलिटी एक बहुत सीरियस इश्यू है। जब हम इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि लगभग पूरे रूट पर एडिक्वेट कैपिसिटी न बढ़ने के कारण आज किसी-किसी रूट पर सौ परसेंट, कहीं एक सौ तीस, कहीं एक सौ पचास और कुछ जगहों पर एक सौ अस्सी परसेंट लाइन कैपिसिटी यूटिलाइजेशन के आंकड़े हैं। ऐसी परिस्थिति में जितने ज्यादा स्टॉप एड होंगे, उतना ज्यादा रेलवे का सिस्टम क्लॉग होगा, ट्रेनें विलंब होंगी, आगे चलकर उसका परिणाम फ्रेट ट्रैफिक पर भी आएगा, रेलवे की अर्निंग्स और सुविधाओं पर भी आएगा।

मैं सभी माननीय सांसदों से आपके माध्यम से दरख्वास्त करूंगा, जहां-जहां संभव है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि स्टॉपेज दिए जाएं। सभी की इच्छा है कि हमारे

क्षेत्र में हर गाड़ी हर स्टेशन पर रुके लेकिन हमारी कुछ टेक्नीकल और ऑपरेशनल कमियां हैं।

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर): अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आदर्श स्टेशनों का चयन किया, उसमें अहमदनगर को तीन नंबर का पारितोषिक मिला है, इसके लिए उनको बधाई देता हूं। इस स्टेशन के बनने के साथ-साथ उधर सुविधा बढ़ाने की भी आवश्यकता है, जैसे लेडिज और जेन्टस के लिए अलग टॉयलेट चाहिए, विश्राम गृह चाहिए, उसके माध्यम से बढ़ेगा। आदर्श स्टेशन बनने के साथ बाहर कम्पाउंड वाल से कितना टपरी वाले को रोकें, छोटे-छोटे बिजनेस करने वाले लोग हैं। मैं मंत्री जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बहुत सारी लैंड उपलब्ध है, रेलवे की इनकम के दृष्टिकोण से क्या आप वहां कॉमर्शियल कम्पलेक्स बनाएं जिससे छोटे-छोटे लोग भी व्यवसाय कर सकें। उनको खुद एक जगह मिल जाएगी, मुद्रा के माध्यम से उनको लोन मिलने पर अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं, क्या इस दृष्टिकोण से कुछ करेंगे?

(1110/SK/KMR)

श्री पीयूष गोयल: माननीय सदस्य का सुझाव बहुत अच्छा है। देश भर में सभी स्टेशनों पर जहां डैवलपमेंट की कैपेबिलिटी है, उसकी जांच चल रही है। हम अहमद नगर को इसमें जोड़कर देखेंगे और वहां जो संभव होगा] कर लेंगे।

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती): माननीय अध्यक्ष जी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मीरा नाम का आदर्श स्टेशन है। माननीय सुरेश जी जब रेल मंत्री थे, तब उन्होंने इसे आदर्श स्टेशन बनाया था। इस बात को तीन साल हो गए हैं। आदर्श स्टेशन का एग्जैक्ट प्लान

क्या है? आदर्श स्टेशन कब पूरा होगा? वहां शौचालय नहीं बना है और नए प्लेटफार्म की मांग है। मीरा स्टेशन पुरंदर पुणे डिस्ट्रिक्ट में है, यह कब पूरा होगा? आदर्श स्टेशन की एग्जैक्टली क्या स्कीम है क्योंकि हमारे यहां इसके लिए ज्यादा निधि नहीं आई है।

श्री पीयूष गोयल: माननीय अध्यक्ष जी, भारत में कई स्टेशन्स 100 साल पुराने हैं और कई 70-80 साल पुराने में हैं, ये काफी बुरी हालत में थे। मैं अभी आंकड़े देख रहा था कि स्टेशन्स को सुधारने के लिए पहले कितना पैसा खर्च होता था। मैं वर्ष 2009-10 के आंकड़े देख रहा था तब 1000-1100 करोड़ रुपये लगते थे। इससे पहले देखें तो वर्ष 2008-09 में 700-800 करोड़ रुपये लगते थे। इस तरह स्टेशन्स की डैवलपमेंट के लिए छोटे एमाउंट्स एलोकेट होते थे।

सभी माननीय सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि हमने किस प्रकार स्टेशनों को डैवलप करने के लिए बल दिया है, जोर लगाया है और अब लगभग साधारणत: 1500-1700 करोड़ रुपये हर वर्ष अलग-अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल किए जाते हैं। हम चाहते हैं कि इसमें पैसेंजर्स एमेनिटीज़ यानी देश में जो एसेंशियल है, उसे प्रोवाइड करा सकें। इस फिगर के अलावा फुट ओवर ब्रिजिस, अंडर ब्रिजिस हैं, वे अलग हैं, ये सेफ्टी के अंडर आते हैं। ऐसी परिस्थिति में आदर्श स्टेशन की कल्पना है जो बहुत ही एसेंशियल पैंसेजर्स एमेनिटीज़ हैं, स्वाभाविक है कि अच्छा टाएलेट होना ही चाहिए। माननीय सांसद ने पहले कहा था कि लेडीज़ और जैन्ट्स टाएलेट अलग होना चाहिए। इसके लिए हमने देश भर में एक मुहिम चलाई है कि अगले तीन-चार महीने में हर स्टेशन, जो एक्टिव है, वहां उपलब्ध कराएं, हॉल्ट स्टेशन पर तो लोग नहीं रहते हैं, मैंने वहां भी कैम्प की कोशिश की है लेकिन वहां मैन्टेनेंस की प्राब्लम आएगी। हमारी

कोशिश है कि पूरे देश में हर स्टेशन पर महिलाओं और पुरुषों के लिए अच्छा टाएलेट हो, अच्छी फैसिलिटीज़ हों। इसके लिए खर्च होगा ताकि यह मैन्टेन हो सके, पानी की टंकी हो ताकि पानी मिल सके।

माननीय अध्यक्ष जी, हर स्टेशन पर वेटिंग रूम नहीं है, लेकिन देखना है कि जहां है उसे कैसे अपडेट कैसे किया जाए। मेरे मन में प्लेटफार्म के सरफेस के लिए नई कल्पना है कि कुछ रफ स्टोन लगाकर प्लेटफार्म्स बनाया जाए ताकि फिसलने की समस्या से फ्री हो सकें। इसी प्रकार से एसेंशियल्स हर स्टेशन पर हो, जैसे लाइटिंग है। हमने देश के हर स्टेशन पर ब्राइट एलईडी लाइटिंग लगाकर ब्राइटली लिट स्टेशन्स की कल्पना की है।

इसी प्रकार से एंट्री और एग्जिट पर दुकानों आदि के कारण बहुत तकलीफ होती है, इसलिए अधिकारियों को कहा गया है कि एंट्री और एग्जिट को फ्री किया जाए ताकि एन्ट्रेस और आउटरेंस में आसानी हो। शायद कोई भी सरकार पूर्ण रूप से आदर्श स्टेशन बनाने की क्षमता और बजट नहीं दे पाएगी। देश में 8600 स्टेशन्स हैं, लेकिन अपनी पॉकेट के हिसाब से यानी अपनी जेब में जो कमाई आती है, उसमें करें। आप सब जानते हैं कि भारत में 43 परसेंट सब्सिडाइज्ड पैंसेजर्स ट्रैवल है यानी अगर 100 रुपये खर्च होते हैं तो पैसेंजर से टिकट के माध्यम से सिर्फ 57 रुपये लिए जाते हैं। एक प्रकार से 43 परसेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बजट सपोर्ट से रेलवे चलती है। मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार अपने अवेलेबल फंड्स के हिसाब से जितनी अच्छी सुविधा दे सकती है, उसका पूरा प्रयत्न कर रही है।

(इति)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न 102, श्री हेमंत गोडसे।

…. (व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल: कुछ माननीय सदस्य रेलवे जोन के बारे में पूछ रहे हैं। अगर ये लोग बैठ जाएंगे, तो मैं उन्हें भी उत्तर देने के लिए तैयार हूं।…. (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: उनकी अलग डिमांड है, आप क्या जवाब देंगे?

…. (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: वे बैठने वाले नहीं हैं, वे ऐसे ही करेंगे।

…. (व्यवधान)

(Q.102)

SHRI HEMANT TUKARAM GODSE (NASHIK): Madam Speaker, as on date, internet penetration in urban India is about 65 per cent and it is just 20 per cent in rural India. Thus there is a wide gap in internet usage in urban and rural areas.

(1115/GM-RPS)

In urban areas, along with BSNL and MTNL, private ISPs also provide services because there is a volume business. But private ISPs do not provide much service in rural areas. In some sectors, for example in banking, the Government has made presence mandatory in rural areas before it gives permit in urban areas. So, I want to ask the hon. Minister whether the Government has any plan to introduce regulation and incentives for promoting private sector along with BSNL's participation in providing broadband connectivity in rural areas so as to drive rapid penetration of internet services in rural areas to fulfil the gap.

श्री मनोज सिन्हा: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि पिछले चार वर्षों मे देश में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर मोटे तौर पर डबल हो गया है। वर्ष 2014 में जहां 7.9 लाख बीटीएस हुआ करते थे, आज देश में उनकी संख्या 18 लाख हो गई है, जिनमें से लगभग 9 लाख बीटीएस 4जी के हैं।

इंटरनेट पेनेट्रेशन काफी तेज गति से इस देश में बढ़ा है। यह सच है कि अभी देश के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं, जहां हम नहीं पहुंच सके हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए हम जो भारत नेट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट फेज हमने दिसम्बर, 2017 में पूरा किया है। एक लाख ग्राम पंचायतों तक हमने यह सुविधा पहुंचाई है और शेष डेढ़ लाख ग्राम पंचायतों में मार्च, 2019 तक यह काम पूरा करना है। इसके अलावा 25,000 वाई-फाई हॉटस्पॉट बीएसएनएल अपने ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजेज में लगा रहा है। माननीय रविशंकर जी का जो मंत्रालय है, इनके कॉमन सर्विस सेंटर्स में 7,000 वाई-फाई हॉटस्पॉट लगाए गए हैं। इनके मंत्रालय को हमने कहा है कि 34,000 वाई-फाई हॉटस्पॉट और लगाइए। मैं कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में ढाई लाख वाई-फाई हॉटस्पॉट पूरे देश में लगेंगे। एक बार यह परियोजना पूरी हो जाएगी तो देश के 60 करोड़ लोगों को यह ब्रॉडबैंड सुविधा पहुंचाने में हमारी सरकार सफल होगी। …(व्यवधान) मैं मानता हूं कि दुनिया के अन्य किसी देश में इतने बड़े स्केल पर ब्रॉडबैंड प्रॉविजन के लिए कोई परियोजना नहीं ली होगी।

SHRI HEMANT TUKARAM GODSE (NASHIK): The Government has targeted to connect remaining 1.5 lakhs Gram Panchayats till March 2019. I want to know the status of BharatNet project phase-II in Maharashtra. By connecting Gram Panchayats, e-governance facility will be provided. In addition to e-governance, I feel the quality of education and healthcare service in rural areas should also be targeted. By connecting schools in rural areas by high speed

broadband, teaching standards can be improved through the remote teaching over interactive video conferencing. Similarly, by connecting public health sector through broadband, advantages of telemedicine can be harnessed for increasing quality of healthcare. So, I want to ask the hon. Minister whether the Union Government has any plans to connect schools and public health centres for increasing quality of education and healthcare service in rural areas.

श्री मनोज सिन्हा: अध्यक्ष महोदया, महाराष्ट्र में भारत नेट का फेज-2 चल रहा है। हमने सेकण्ड फेज में स्ट्रेटेजी बदली थी और देश के आठ राज्य खुद इस परियोजना को लागू कर रहे हैं और महाराष्ट्र उनमें से एक राज्य है। 'महानेट' नाम की परियोजना महाराष्ट्र सरकार चला रही है। सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स एवं सभी सरकारी संस्थाओं को ब्रॉडबैंड सुविधा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ी योजना बनाई है। भारत सरकार ने भी तय किया है कि देश भर में जितने हाईस्कूल एंड एबव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स हैं, जितने पुलिस स्टेशन्स हैं, जितने पोस्ट ऑफिसेज हैं और जितने पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं, उनको हम भारत सरकार के खर्च पर इससे जोड़ने जा रहे हैं।

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो उनका जनपद है, जहां से वह आते हैं – नासिक, वहां 611 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें 1221 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर हमने डाल दिया है और 607 ग्राम पंचायतों तक हमने यह सुविधा पहुंचा दी है। महाराष्ट्र का काफी हिस्सा फर्स्ट फेज में ही कवर हुआ है। मैं माननीय सदस्य को

अवगत कराना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने 'महानेट' नाम की जो परियोजना बनाई है, वह निश्चित रूप से अत्यंत आधुनिक परियोजना है और उससे सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स जुड़ेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा कि हम पूरे प्रदेश में ई-एजुकेशन, टेलीमेडिसिन आदि सारी सुविधाएं देना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी का डिजिटल इंडिया का जो स्वप्न है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी उसे पूरा कर रहे हैं।

श्री बिष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): अध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले रविशंकर प्रसाद जी एवं मनोज सिन्हा जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि 70 साल में जो काम नहीं हुआ था, उसे आपने कर दिया है।

(1120/asa/rsg)

100 जीबीपीएस का ओएफसी अवार्ड हो चुका है। 1213 करोड़ अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के जिस गांव में दस आबादी है, एक-एक टॉवर में 1.6 करोड़ लगता है। उनके सपने में भी नहीं आया, चिंतन में भी नहीं आया। इस तरह से अंडमान में 214 विलेजेज में 2जी, 4 जी टॉवर लग रहा है। मेरा अनुरोध है कि भारतनेट में सरकार जो काम कर रही है, …(व्यवधान) अरे बन्धु, आ रहा है। हमारे यहां भी काम चल रहा है। मैं आग्रह करूंगा कि अंडमान निकोबार में 70 पंचायत हैं। वर्ष 2019 में जो टार्गेट दिया गया है, मार्च तक यह काम पूरा हो जाएगा तो क्या उसमें अंडमान और निकोबार का भी काम हो जाएगा?

श्री मनोज सिन्हा : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य की जानकारी में भी है कि वह जब व्यक्तिगत रूप से मिले थे तो मैंने उन्हें बताया है, लेकिन मैं उनके ध्यान

में यह बात लाना चाहता हूं कि चेन्नई मेनलैंड से अंडमान निकोबार के 5 आईलैंड्स हैं- चाहे वो कार निकोबार हो, लिटिल अंडमान हो, हैवलॉक हो या ग्रेट निकोबार हो, इन सबको ऑप्टिकल फाइबर यानी सबमेरीन ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का काम हमारी सरकार कर रही है। टेंडर अवार्ड कर दिया गया है, बाकी सारे प्रिलिमिनरी काम शुरू हो गये हैं और निश्चित रूप से अंडमान के हर नागरिक के लिए प्रधान मंत्री जी जो डिजिटल इंडिया की बात कहते हैं तो उसका लाभ अंडमान ही नहीं बल्कि देश के हर कोने के लोगों को मिले, इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Thank you very much, Madam Speaker.

The hon. Minister is speaking about active involvement in connections. First of all, I have to say that he should at least stop the call drops. We are not in a position to speak for 30 seconds. Whenever a BSNL call is started, every minute or even every second, there is a call drop. The then hon. Minister Shri Ravi Shankar Prasad had assured this House that this would be rectified within six months but nothing has happened. We are not in a position to speak.

As far as mobile expansion is concerned, the hon. Minister has informed the House that 4G facility would be provided all over India. Even in the TAC meeting that I had convened in my constituency of Alappuzha, they were saying that there was no clarity from the side

of the Government about 4G installation. I would like to know from the Minister whether the Government has any plan to stop the call drops and for 4G expansion.

श्री मनोज सिन्हा : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सरकार के पास बहुत अच्छा प्लान है। वह जो कह रहे हैं कि कोई प्लान नहीं है, ऐसा नहीं है। 4 जी पूरे देश में रोल-आउट हो रहा है। रिलायेंस जियो का जहां नेटवर्क है, वहां 4जी का है। जिस लाइसेंस एरिया में एयरटेल है, …(व्यवधान) आप जरा शांत रहिए। वहां 4 जी का नेटवर्क भी पूरा रोल-आउट कर दिया है।

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): What about BSNL? …(*Interruptions*)

श्री मनोज सिन्हा : माननीय अध्यक्ष महोदया, 4 जी का नेटवर्क एयरटेल ने पूरा रोल-आउट कर दिया। तीसरा सर्विस प्रोवाइडर और वोडाफोन भी आने वाले दिनों में रोल-आउट कर रहे हैं। जहां तक भारत संचार निगम लिमिटेड का सवाल है तो भारत संचार निगम लिमिटेड के पास स्पैक्ट्रम था, 4जी का स्पैक्ट्रम उनके पास नहीं था। केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में 4जी की सुविधा वे दे रहे हैं लेकिन हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी भारत संचार निगम लिमिटेड को 4जी का स्पैक्ट्रम हम उपलब्ध कराएं ताकि देश भर में 4जी की सुविधा भी भारत संचार निगम लिमिटेड उपलब्ध करा सके।

जहां तक कॉल ड्रॉप का सवाल है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि कॉल ड्रॉप के मीज़रमेंट के जो तरीके इस देश में हैं, वे ट्राई तय करता है। ट्राई की रिपोर्ट

वे देख लें। लगातार तीन क्वार्टर की जो रिपोर्ट है, उसमें हर रिपोर्ट में कहा गया है कि निरन्तर सुधार हो रहा है। यह सच है कि इसमें लगातार मॉनीटरिंग की जरूरत है। दूसरे मंत्रालय में भी हमने आईवीआरएस का सिस्टम लगाया हुआ है। इसे 2016 में स्थापित किया था और प्रतिदिन लगभग 25 लाख टेलीफोन उपभोक्ताओं से बात की जाती है। उनसे हम जानना चाहते हैं कि आपके घर में कॉल ड्रॉप है या किसी निश्चित स्थान पर है और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को निर्देश देकर उसको जल्दी से जल्दी खत्म करने का प्रयास करें। लेकिन एक मौलिक बात उनको मैं बताना चाहता हू कि वॉयरलाइन नेटवर्क रिलायबल नेटवर्क होता है और वॉयरलैस नेटवर्क रिलायबल नहीं होता। हमारे देश में वॉयरलाइन नेटवर्क नहीं बना और मोबाइल आया और देश वॉयरलैस की ओर चला गया। इसके कारण यह कठिनाई रही है। उसको भी मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार दूर कर रही है। 7 लाख कि.मी. ऑप्टिकल फाइबर 2014 तक थी और हमने 14 लाख कि.मी. ऑप्टिकल फाइबर देश में बिछायी है। आने वाले दिनों में हम इसे और बढ़ाएंगे ताकि इसकी रिलायबिल्टी पूरी तरह बनी रहे।

(1125/asa/rk)

श्रीमती अर्पिता घोष (बालूरघाट): माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। ये आंकड़े देखने से मन बहुत खुश हो जाता है परंतु जब हम अपने संसदीय क्षेत्र बालूरघाट में जिला साउथ दिनाजपुर में जाते हैं तो कोई भी 'जी' दिखाई नहीं देता है। 4जी छोड़िए, 2जी तक नहीं है। हमारे वहां पर प्राइवेट पार्टीज का 4जी चलता है। बहुत बढ़िया चलता है। यहां पर मंत्री जी हैं, हम उनको बताते हैं कि बीएसएनएल की कोई भी लाइन नहीं चलती है और एक भी

ऑफिस नहीं है। रायगंज में है, साउथ दिनाजपुर में नहीं है। एक कोई अधिकारी हैं, उनको कभी दिखाई नहीं देता है। 'जी' की तो छोड़िए। आपके आंकड़े बहुत अच्छे हैं, अगर ये आंकड़े हमारे साउथ दिनाजपुर तक आ जाएं तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। सर, कृपया इसका जवाब दीजिएगा। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : अच्छा जवाब दीजिए।

श्री मनोज सिन्हा : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सांसद महोदया का आभारी हूं कि उन्होंने मेरा ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है। केवल आपके संसदीय क्षेत्र तक ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अच्छा नेटवर्क पहुंचे, यह हमारी सरकार की वचनबद्धता है। आप जो विषय मेरे ध्यान में लेकर आई हैं, एक-एक एक्सचेंज और एक-एक ब्लॉक की जानकारी मेरे पास नहीं है। कौन ऑफिसर नहीं जाता, मैं निश्चित रूप से इसकी भी जानकारी लेकर और आपके लोक सभा क्षेत्र के जिस स्थान का आपने जिक्र किया है, वहां का विस्तृत विवरण आपको उपलब्ध करा दूंगा।

श्रीमती रक्षाताई खाडसे (रावेर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि जितने भी प्राइवेट बीटीएस हैं, उनकी कई बार कॉल ड्रॉप्स की समस्या आती है। इंटरनेट सर्विस डाउन रहती है। लेकिन उनकी शिकायत करने के लिए जिला स्तर पर कहीं भी व्यवस्था नहीं है। क्या हम वैसी व्यवस्था कर सकते हैं, जिसके कारण लोगों को सुविधा हो सके?

श्री मनोज सिन्हा : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य महोदया के प्रश्न का उत्तर मैंने पहले ही दिया है। हमारे यहा ऑलरेडी वह सिस्टम है। आप चाहे तो हमारे यहां सीधे खबर करा सकती हैं। हम इसकी चिन्ता करेंगे कि आपकी जो कठिनाई है, वह समाप्त हो जाए।

(इति)

प्रश्न 103

माननीय अध्यक्ष : डॉ. उदित राज - अनुपस्थित।

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी है, लेकिन अभी भी इसमें और सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता है। यह जो सरकार की बीपीओ योजना है;

> "A healthy trend relating to employment of women and persons from marginalised section of society indicating digital empowerment in smaller towns and cities"

यह बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसमें वूमैन एमपॉवरमेंट भी होगा लेकिन इसका दायरा बहुत ही जल्दी बढ़ाकर इसकी एक रिपोर्ट सदन को देनी आवश्यक है जिससे हमें पता चलेगा कि कितनी महिलाओं को इसमें नौकरी मिली है और एमपॉवरमेंट में कितनी वृद्धि हुई है। जो सर्विस है, वह सर्विस कितने लोगों तक हम पहुंचा पाए हैं, यदि इसकी जानकारी मंत्री महोदय देते हैं तो देश के लोगों को इसकी जानकारी उपलब्ध होगी।

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदया, जो प्रश्न माननीय शेट्टी जी ने पूछा है, अभी पूर्व के प्रश्न में आदरणीय मनोज जी ने डिजिटल इंडिया की बात कही। डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम प्रधान मंत्री जी के निर्देश में समावेशी डिजिटल भारत बनाने का है । मैं बहुत ही विनम्रता से सदन को सूचित करना चाहूंगा कि वर्ष 2014 में आई.टी. का मंत्री बनने के बाद मैं बैंगलुरू में गया था। वहां नैसकॉम की मीटिंग बड़ी आई.टी. कंपनी से थी। बाहर बिहार, एम.पी., यू.पी, के बच्चे खड़े थे। उनका कहना था

कि ऐसा कीजिए कि हम अपने शहरों की तरफ लौट सकें। इसलिए छोटे शहरों में बीपीओ योजना बनाई गई। पहले हमने 48000 सीट्स देश के लिए दीं और नॉर्थ-ईस्ट के लिए अलग से 5000 सीट्स दीं।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि वर्ष 2015 में हमने स्कीम बनाई। अभी तक देश में हमने 205 यूनिट्स एप्रूव कर दी हैं जो देश के 101 छोटे शहरों में हैं। 113 यूनिट्स शुरू हो गयी हैं जिसमें 21858 लोगों को नौकरी मिली है। बड़ी संख्या में छोटे गांवों की बच्चियां हैं जो काम कर रही हैं। लेकिन मैं एक बात सदन को बताना चाहूंगा कि जहां-जहां शुरू हुआ है, विशाखापत्तनम भी है, भीमावरम भी है, तिरुपति आन्ध्र प्रदेश में, श्रीनगर जम्मू-सोपोर जम्मू-कश्मीर में है। जो आतंकवाद की बात हम लोग करते हैं, उस जम्मू-कश्मीर में बीपीओ शुरू हो गया है। पटना, मुजफ्फरपुर, कोयम्बटूर, मदुरई में भी यह शुरू है और उत्तर प्रदेश में देवरिया, बरेली, लखनऊ और कानपुर इत्यादि जगहों पर बीपीओ शुरू हो गया है। झारखंड में भी रांची में शुरू हो गया है और आपके क्षेत्र में भी जल्दी आने वाला है। कहने का मतलब यह है कि छोटे शहरों में जो समावेशी भारत है, आज बड़ी संख्या में काम हो रहा है।

(1130/PS/RAJ)

अध्यक्ष महोदया, नॉर्थ-ईस्ट में कोहिमा, इम्फाल और गुवाहाटी जैसे स्थानों पर बीपीओ शुरू हो गया है। इसमें बहुत सारी कंपनियों को विदेश से भी काम मिल रहा है, जिनमें अमेरिका, इंगलैंड और आस्ट्रेलिया जैसे देश हैं। हम एम्पावरमेंट करने की बात करते हैं। शेट्टी जी की एक बात सही है। अभी हमारा फर्स्ट फेज में 48 हजार सीट्स

का टारगेट है। जब वह पूरा हो जाएगा तो इसका और विस्तार होगा, इसके बारे में हमारा दृष्टिकोण बहुत खुला हुआ है।

अध्यक्ष महोदया, मैं एक बात बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि मैं सेंटर में पांच-छ: सीट्स पर गया था। मैंने बच्चियों के चेहरे पर नई आशा देखी है, जिनमें दलित परिवार की बेटियां हैं, मार्जिनलाइज्ड परिवार की बेटियां हैं। अभी प्रधान मंत्री जी ने दिल्ली से ऐसे लाभार्थियों के लिए बात की थी तो बहुत सारी ऐसी बेटियों से भी उनको बात करने का अवसर मिला। यह अच्छा प्रोग्राम है। मैं उम्मीद करूंगा कि सदन इसका अभिनंदन करेगा।

SHRI V. ELUMALAI (ARANI): Thank you, Hon. Speaker Madam.

Today, the BPO is on metro-centric basis. The majority of the population in India resides in metro cities like Mumbai, Delhi, Chennai and Bengaluru, etc. There is a growing trend of people migrating from rural areas to metro cities.

Therefore, I would like to know from the hon. Minister whether the Government has any plan to create more BPOs or ITeS seats in rural areas.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Madam, I wish to inform the hon. Member who I believe comes from Tamil Nadu. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Yes, he is from Tamil Nadu.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I only wish to inform him that in his State, BPOs have started operating in Madurai, Mayiladuthurai, Namakkal, Tiruchirappalli, Tiruppattur, Vellore and all these places. … (*Interruptions*) Metro cities are well-known in the country. But, what is important is that one new city is having 400 BPOs operational constituting mostly women.

Therefore, I take your point that we need to go further below. This is a movement which has started, becoming a kind of a digital inclusion giving job opportunity. We will take note of your concern. We will surely follow it up.

KUMARI SUSHMITA DEV (SILCHAR): Thank you Madam Speaker.

The BPOs actually form an opportunity for employment in many areas, especially in smaller cities which have been mentioned here. The hon. Minister of IT had been to my constituency on one or two occasions. I remember seeing in newspapers a news item regarding opening of BPOs in Silchar, Cachar and Districts of Barak Valley.

Madam, the hon. Minister has mentioned that he has opened one BPO in Guwahati. I thank him for that. The only heavy industry in my constituency namely the Hindustan Paper Corporation is in trouble. Employment is a big challenge. I would request the hon.

Minister to tell me that under the North-East BPO Promotion Scheme whether there is any development or any plan of starting a BPO in any of the districts of Barak Valley in Assam.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Madam, we are very earnestly and sincerely following the concerns of the young people of the North-East. Therefore, when I was finalising the scheme, one scheme came for the creation of 48,000 BPO seats for the rest of the country and one scheme for the North-East for creation of 5000 BPO seats.

I am very happy to announce in this House that two BPOs have started operating in Guwahati; two BPOs in Imphal; and there is also a BPO in Kohima. Yes, I went to the hon. Member's constituency. Young people met me there. I have taken on-board their concerns. The fresh bid is going on. It is very important that people file the bid. The requisite and eligible companies must also file the bid. My officers go on a roadshow. They talk to the people. The hon. Member is the local representative. If a BPO comes in Silchar, beyond the political divide and whosoever is in power, the young people of your constituency are the ones who will win. If we go with that mode and commitment in mind, I am sure, Silchar would have a good opening. I have personally pushed this issue. I had been to her constituency

a number of times. I know that there is a case for opening a BPO in Barak Valley. I will surely look into this. But, I would also urge her to ensure that in the bidding process, the IT companies also apply.

(1135/RC/IND)

SHRI ARJUN CHARAN SETHI (BHADRAK): Madam, I hail from the State of Odisha. Fortunately, with the blessings of my electorate, I have been here since 1971. The way things are moving in the State of Odisha, it is horrible. I should say that. No officers are posted in different strategic positions. Recently, I had to go to my constituency. My constituency people gheraoed me. They pressed me to visit the places where these things are almost in a mess.

So, I would request the hon. Minister, who is a friend of mine, to visit the State of Odisha at least once. As far as I know, during the last four years, no officer has visited the State of Odisha. Therefore, I would request you to take a review meeting in the capital city of Bhubaneswar, Odisha. You will be able to find out how they have made a mess of things. You please visit our State to have a first-hand study of the things. It is because in my constituency, including in my own house, these things are not working. Therefore, I would

once again request you to have a first-hand knowledge of the situation.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Madam before I reply to him, I would like to reply to the hon. lady Member from Silchar. I want to inform her that a fifty-seat BPO has been allotted to Silchar. It is a good news.

As far as hon. Member, Shri Sethi, is concerned, he is a very senior Member. He is entitled to my respect. I have visited his State a minimum of three times. Recently, I went to inaugurate a Data Centre. Before that I went as a Minister of Communications to Puri. Again, I am going to his State on the 4th to inaugurate an STPI.

The Prime Minister's vision is that without the development of Eastern India including his State, India cannot progress. Therefore, we are working beyond political divide. But I want to inform him that in the BPO scheme, six BPOs have come up in Bhubaneswar; one in Cuttack and one in Jalesar. They all have started working under the Government of India scheme. I wish him good luck. However, every problem of the State Government should not be passed on to the Central Government. We are doing our best and will continue to do our best.

(ends)

HON. SPEAKER: We will take up Q. 104 and Q. 111 together.

(Q. 104 and 111)

HON. SPEAKER: Q. 104 – Shrimati M. Vasanthi – Not present.

Q. 111 – Shri K. Ashok Kumar – … (*Interruptions*)

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदया, भविष्य के 20-30 सालों का अभूतपूर्व विचार करते हुए माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो मुम्बई-अहमदाबाद-पूने बुलेट ट्रेन का प्रकल्प शुरू किया है, मैं सबसे पहले उसके लिए प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। पिछले दो साल में मुम्बई की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे मेट्रो रेल हो, बुलेट ट्रेन हो, सैकेंड एयरपोर्ट हो, डी लिंक रोड हो, कोस्टल रोड हो आदि प्रोजेक्ट्स को बहुत गति मिली है।

महोदया, जब मुम्बई-पूने एक्सप्रेस हाईवे गडकरी जी ने शुरू किया था, तब टीका-टिप्पणी हो रही थी। मैं जानना चाहता हूं कि बुलेट ट्रेन के क्या एडवांटेजेज हैं, उसका प्रोजेक्ट कितने करोड़ रुपयों का है, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा और इंडस्ट्रीयलाइजेशन किस प्रकार से होगा? लैंड एक्विजिशन में भी सरकार एक्ट्रेक्टिव प्राइस देने जा रही है, इस संबंध में माननीय मंत्री जी हमें जानकारी दें।

(1140/vb/snb)

श्री पीयूष गोयल: माननीय अध्यक्ष महोदया, वास्तव में माननीय प्रधान मंत्री जी का विज़न है कि भारत एक आधुनिक शक्ति बने। भारत की जनता तथा सभी यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएँ हों, वे तेज़ गति से एक जगह से दूसरी जगहों पर जा सकें, भारत में नयी टेक्नोलॉजी के आने से हमारे इंजीनियर्स की क्षमताएँ बढ़ें, हमारी टेक्निकल एबिलिटीज़ बढ़ें और भारत में बनने वाली वस्तुएँ पूरे विश्व में एक्सपोर्ट हों। जब उनके

समक्ष बुलेट ट्रेन की कल्पना आयी, तो सिर्फ मुम्बई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चलाने का ही सवाल नहीं था, सवाल यह भी था कि इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, कौन-सी टेक्नोलॉजी लेनी है, इसके अन्य लाभ क्या होंगे। जब इन सब बातों पर पूरी तरह से समीक्षा की गयी, तो ध्यान आया कि जापान की 'शिंकनसेन' टेक्नोलॉजी अत्याधुनिक है। लेकिन, यह भी भारत में 50 वर्षों के विलम्ब से आ रही है। जापान में 'शिंकनसेन' टेक्नोलॉजी लगभग मेरे पैदा होने के वर्ष के आसपास 1960 में शुरू हुई। भारत में इसे आने में 50 वर्ष लग गये क्योंकि मोदी जी अभी आये, तो उन्होंने सोचा कि देश में सुविधाएँ लायी जाएँ। इसके लिए जापान से मात्र 0.1 परसेंट पर हमें 50 वर्ष की समयावधि का लोन मिला है। उस पर भी 15 वर्षों तक का मोराटोरियम है। यह इतने समय तक रीपेमेंट नहीं करना पड़ेगा। इसके मद्देनज़र यह प्रोजेक्ट बहुत ही सस्ते खर्चे पर हम लगा पाएंगे। पूरी तरह से एलिवेटेड या 'अंडर सी' होने के कारण जमीन पर सेफ्टी सुनिश्चित हो जाएगी, किसी को कोई क्षति या हानि नहीं पहुँचेगी। इसके साथ ही, हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी सुनिश्चित किया है। जो टेक्नोलॉजी भारत में आकर 'मेक इन इंडिया' के तहत भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगी और इस टेक्नोलॉजी को सस्ती लागत में बनाने के कारण हम आगे विश्व की सभी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि मुम्बई-अहमदाबाद कॉरिडोर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में डेवलप होगा। इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि देश में हाई स्पीड रेल का एक जाल बिछे। अलग-अलग क्षेत्रों में ऐसी हाई स्पीड ट्रेन्स अवेलेबल हों। इससे किसानों को भी सुविधा मिलेगी। उनके पेरिशेबल प्रोडक्ट्स तेज गति से दूसरे

स्थानों पर पहुँच सकेंगे। यात्रियों को बिल्कुल अत्याधुनिक विश्वस्तरीय सुविधाएँ मिलेंगी।

जहाँ तक जमीन का सवाल है, हमने सुनिश्चित किया है कि चार गुना के स्थान पर पाँच गुना पैसे देकर, यदि कंसेंट मिल जाए, तो जमीन के एवज़ में पाँच गुना पैसे देंगे।

माननीय अध्यक्ष : श्री खड़गे जी, आप हाई स्पीड रेल पर प्रकाश डालिएगा।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): माननीय अध्यक्ष महोदया, यह प्रश्न श्री किरीट सोमैया जी द्वारा पूरे सदन को बुलेट ट्रेन के बारे में विस्तार से समझाने के लिए पूछा गया है। लेकिन, मैं कहना चाहता हूँ कि यह आइडिया आपका नहीं है। यह पहले से चलते हुए आया है। आप इससे संबंधित पहले की फाइल्स देखें। एक लाख दस हजार करोड़ रुपये खर्च करके अगर आप 500 किलोमीटर तक का हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बना रहे हैं, इसकी कॉस्ट एक तरफ है। दूसरी बात, कोई साधारण उपभोक्ता या यात्री उसमें नहीं जाएगा। उसे इसके लिए हवाई जहाज से भी ज्यादा किराया देना पड़ेगा।

आप किसानों की बात कह रहे हैं, जब किसान इसे ट्रांसपोर्ट के रूप में इस्तेमाल करेगा, तो क्या उसके प्रोडक्ट्स की लागत उसे मिल पाएगी? इस प्रकार से, किसान अपने सामान को बुलेट ट्रेन में नहीं ले जा पाएगा।

मैं कहना चाहता हूँ कि इसके लिए आज तक जो लैंड मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिली है और इसमें जितने भी ट्रैक्स हैं, अब तक उसके लिए कोई मेनटेनेंस की व्यवस्था नहीं की गयी है। इलैक्ट्रिफिकेशन का जो काम पूरे देश में होना था, वह थोड़ा-बहुत हो रहा है। …(व्यवधान)

(1145/PC/SNB)

माननीय अध्यक्ष : आप अपना प्रश्न तो पूछो।

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम, मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं, क्योंकि इसी पैसे से हम हजारों किलोमीटर के अच्छे रेलवे ट्रैक्स बनाने का काम कर सकते हैं। …(व्यवधान) मेरा एक लास्ट प्रश्न है। …(व्यवधान) चाहे पहले की कोई भी सरकार हो, तीन डिवीजन करने का वादा पहले यहां हुआ था। …(व्यवधान) एक डिवीजन जम्मू और कश्मीर, एक असम और एक गुलबर्गा में होना था। …(व्यवधान) इसके लिए लैण्ड भी दिया गया था, लेकिन अब तक ये तीन डिवीजंस ओपन नहीं हुए हैं। मेरा चौथा प्रश्न, जिसके बारे में टी.डी.पी. और कांग्रेस वाले भी पूछ रहे हैं, यह है कि जो विशाखापट्नम में ज़ोनल डिवीज़न …(व्यवधान) ये सारे वादे हैं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप तो समझदार हैं। फिर मैं आपको टोकती हूं, तो आप गुस्सा होते हैं। अगर आपको बुलेट ट्रेन के बारे में कुछ पूछना है, तो पूछिए।

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम, ये सब वादे हैं। ये कब पूरे किए जाएंगे? …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यस मिनिस्टर?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सब बैठिए।

…(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल : अध्यक्ष महोदया, माननीय लीडर ऑफ दि कांग्रेस पार्टी ने 11 प्रश्न पूछे हैं। …(व्यवधान) मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इन 11 प्रश्नों का जवाब देने का मौका देंगी। …(व्यवधान) चूंकि माननीय खड़गे इतने सीनियर लीडर हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि उनको यह बात ध्यान में आए की सदन की कार्यवाही कैसे चलती है और सरकार कैसे चलती है। …(व्यवधान) शायद वे भी रेल मंत्री रह चुके हैं। …(व्यवधान) इसलिए ज़रूरी है कि इन 11 प्रश्नों के माध्यम से पुरानी सरकार और हमारे बीच का पर्दाफाश हो और बदलाव दिखे।…(व्यवधान) उन्होंने 11 प्रश्न पूछे हैं। …(व्यवधान) मैडम, पहले तो उन्होंने एक माननीय सदस्य - माननीय किरीट सोमैया जी के प्रश्न के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए। …(व्यवधान) मैं समझता हूं कि यह आपत्तिजनक है। …(व्यवधान) किसी भी सदस्य के मन में अगर कोई प्रश्न है, तो वह उसे उठा सकता है। …(व्यवधान) जब कांग्रेस के सदस्य कोई प्रश्न उठाते हैं, तब हमने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया। …(व्यवधान) खड़गे जी का यह कहना कि किरीट जी ने अपना प्रश्न इसलिए उठाया, कि मैं उसका व्याख्यान कर सकूं, यह एकदम आपत्तिजनक विषय है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह प्रश्न किरीट जी का है ही नहीं।

…(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल : इसी का अब मैं इनको व्याख्यान करता हूं। …(व्यवधान) इनका पहला प्रश्न था कि यह बुलेट ट्रेन पहले से आई है। …(व्यवधान) यह बहुत अच्छी बात है। …(व्यवधान) मैं स्वागत करता हूं कि कांग्रेस के समय यह प्रोजेक्ट आया। …(व्यवधान) आज क्यों ये इसके बारे में रो रहे हैं? …(व्यवधान) आज क्यों ये इसकी

आलोचना कर रहे हैं? …(व्यवधान) आपको तो खुश होना चाहिए कि जो काम आप रेल मंत्री के नाते नहीं कर पाए, वह काम इस सरकार ने कर के दिखाया। …(व्यवधान) जिस काम के लिए आप पैसा नहीं ला पाए, हम सस्ते में प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। …(व्यवधान) तो आप रो क्यों रहे हैं? …(व्यवधान) आप तो खुश होइए कि आपका अधूरा काम हमने पूरा किया।…(व्यवधान) आप एक लाख दस हजार करोड़ रुपये के खर्चे की चिंता कर रहे हैं।…(व्यवधान) मैडम, एक लाख दस हजार करोड़ रुपये से देश को जो फायदा होने जा रहा है, जो टैक्नोलॉजी आएगी, जिस मेक इन इंडिया प्रोग्राम का पूरा कॉरिडोर डेवलप हो गया है, जैसा कि मैंने अभी बताया है, ये सब होलेस्टिक थिंकिंग इनकी समझ में तो आ ही नहीं सकती है, क्योंकि इनके मन में तो गुलबर्गा का डिवीज़न है।…(व्यवधान) गुलबर्गा उनकी कॉन्सिटिटुएंसी है। …(व्यवधान) आखिर कब तक रेलवे का राजनीतिकरण होगा? …(व्यवधान) कब तक रेल मंत्री अपने ही विषय के बारे में सोचेंगे कि मेरा डिवीज़न बने, बाकी जाएं भाड़ में।…(व्यवधान) चाहे उसके लिए 250 करोड़ रुपये लग जाएं, पर मेरी कॉन्सिटिटुएंसी में मेरा डिवीज़न बन जाए।…(व्यवधान) यह कोई सोच है? …(व्यवधान) इस तरीके से सरकार चलती है? …(व्यवधान) आप कहते हैं कि ऑर्डिनेरी कंज़्यूमर कैसे बढ़ेगा? …(व्यवधान) इसीलिए तो मात्र प्वाइंट वन परसेंट लोन पर हम पैसा लाए…(व्यवधान) ताकि ऑर्डिनेरी कंज़्यूमर पर बोझ कम हो।…(व्यवधान) ये फ्यूचर में ट्रेन का प्राइस आज के हवाई जहाज के प्राइस से कंपेयर कर रहे हैं।…(व्यवधान) यह कैसा कंपैरिज़न है? …(व्यवधान) फ्यूचर में ट्रेन का प्राइस और प्लेन का प्राइस अपने आप एडजस्ट होगा। …(व्यवधान) इसके बाद ये पूछते हैं कि किसान अपना सामान कैसे लेकर जाएगा?

…(व्यवधान) यही तो इस सरकार की खासियत है।…(व्यवधान) हम किसान के लिए विशेष सुविधाएं बनाते हैं।…(व्यवधान) किसान को अलग रेट दिया जाएगा।…(व्यवधान) उसके लिए अलग ट्रेन चलाई जाएगी।…(व्यवधान) फिर ये कहते हैं कि लैण्ड नहीं मिला।…(व्यवधान) इनके ज़माने के 40 साल पुराने प्रोजेक्ट को आज तक लैण्ड नहीं मिला है।…(व्यवधान) हमारा प्रोजेक्ट तो एक साल पुराना है।…(व्यवधान) लगभग सभी जगह यह तय हो गया है कि लैण्ड मिल जाएगी।…(व्यवधान) इस पर अच्छी बातचीत चल रही है।…(व्यवधान) महाराष्ट्र और गुजरात सरकार पूरे तरीके से हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं।…(व्यवधान) लैण्ड मिलने के बारे में मुझे कोई तकलीफ नहीं लग रही है, क्योंकि हम एक ईमानदार व्यवस्था को लेकर वहां जा रहे हैं।…(व्यवधान) हम इनकी तरह नहीं हैं, जो 40 सालों में लाइन नहीं ले पाते हैं, जिससे प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं और उनकी कॉस्ट्स ओवर रन होती है।…(व्यवधान) इन्होंने कहा कि ट्रैक मेंटिनेंस नहीं हो रहा है।…(व्यवधान) माननीय खड़गे जी शायद नहीं जानते हैं कि जितना ट्रैक मेंटिनेंस आज एक साल में हो रहा है, उतना उनके समय में तीन सालों में नहीं होता था।…(व्यवधान) हमने पिछले वर्ष अकेले लगभग 4500 किलोमीटर रेल ट्रैक्स का रिन्युअल किया है। …(व्यवधान)

(1150/BKS/RU)

यह बतायें, अगर इन्होंने इतने वर्षों में उतना काम किया।…(व्यवधान) इलैक्ट्रिफिकेशन उन्होंने एकनॉलिज किया, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वर्ष 2013-14 में कुल 800 किलोमीटर इलैक्ट्रिफिकेशन होता था। पिछले वर्ष में 4100

किलोमीटर इलैक्ट्रिफिकेशन हुआ। यह होता है काम करने का ढंग। जैसा माननीय प्रधान मंत्री कहते हैं, हम लटकाते, भटकाते नहीं हैं, हम काम करने वालों में से हैं।

यह डबलिंग की बात कर रहे हैं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वह आपके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, मैं इसमें क्या कर सकती हूं?

श्री पीयूष गोयल: इस देश की आजादी को 65 वर्ष हो गए, जिसमें पचास वर्ष कांग्रेस ने शासन किया। आपने 11 प्रश्न पूछे हैं, मैं उन 11 प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं। आपने डबलिंग की बात पूछी, मैं आपको डबलिंग का एक किस्सा सुनाता हूं। आजादी के 65 वर्ष, जिसमें एक पार्टी ने पचास वर्ष और एक परिवार के सदस्य या उनके बैठाए हुए सदस्य ने 48 वर्ष राज किया।

1152 hours

(*At this stage, Shri Naramalli Sivaprasad came and stood near the Table.*)

… (*Interruptions*)

1152 hours

(At this stage, Shri Naramalli Sivaprasad went back to his seat.)

… (*Interruptions*)

श्री पीयूष गोयल : आज भी मुम्बई से बंगलूरू, मुम्बई से चेन्नई, मुम्बई से हैदराबाद ये लोग डबल ट्रैक नहीं बना पाए और वह भी 65 वर्षों के समय में नहीं बना पाए। हमने उस काम को लिया और इसी वर्ष के आखिर तक या मार्च तक पूरे ट्रैक का डबलिंग हो जाएगा।

आखिर में मैं बताना चाहता हूं कि यह जो पैसा है, यह इस प्रोजैक्ट के लिए मिला है, ऐसा नहीं है कि इस पैसे से आप और कुछ कर सकते हैं। It is a project-specific international loan. प्रोजैक्ट स्पेसिफिक लोन उसी के लिए यूज हो सकता है, किसी और मद में यह यूज नहीं हो सकता। लेकिन हमने कभी पैसे की कमी को एक्सक्यूज नहीं बनाया। रेलवे को भारत सरकार से पर्याप्त पैसा मिला है। मोदी जी ने पैसे की कमी के कारण रेलवे का कोई काम रुकने नहीं दिया।

SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): Madam, it has been reported that 80 per cent of the land acquisition for the bullet train shall be completed by December, 2018. However, it has also been reported that so far even an acre of land has not been acquired. Therefore, I would like to know as to how the Railways are planning to acquire such a huge area of land during such a short period of time. … (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam, this is not fair. This is not the way to reply.… (*Interruptions*)

SHRI PIYUSH GOYAL: Well, you ask such questions and I answer you in the same voice. … (*Interruptions*)

Madam, as regards the hon. Member's supplementary, land acquisition does not happen in piece-meal. We have taken up the issue of entire land acquisition of 1485 hectares. Land acquisition

has been done in 12 districts and work is in progress. In regard to some small patches, there are some people who are objecting to it. We will have a healthy dialogue with them. We will have a social impact study done and the entire land will be acquired well in time.

(ends)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 105 - श्री रावसाहेब दानवे पाटील -- उपस्थित नहीं।

श्री वीरेन्द्र कश्यप जी, आप बोलिये।

(प्रश्न 105)

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): अध्यक्ष महोदय, मोदी सरकार के माध्यम से डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया ये तीन चीजें बहुत ही प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं। लेकिन आज यह प्रश्न डिजिटल इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है और हमें खुशी है कि भारतनेट के माध्यम से आज ढाई लाख पंचायतों को जोड़ने का जो कार्य चला हुआ है, वह भी संतोषजनक है। परंतु मैं माननीय मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि जो 25 हजार वाई-फाई हॉट स्पॉट्स हैं, उन्हें आप जल्दी भारतनेट के माध्यम से जोड़ना चाहते हैं। जैसा आपको मालूम है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत सभी सांसदों ने एक-एक गांव गोद लिया था और अभी तक तीन-तीन गांव सभी सांसद गोद ले चुके हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इन हॉट स्पॉट्स को सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत जो गांव गोद लिए गए हैं, उन सभी गांवों में फ्री वाई-फाई की सुविधा प्रदान करेंगे?

इसके साथ ही कहना चाहता हूं कि मैं हिमाचल प्रदेश की शिमला पार्लियामेन्ट्री कांस्टीटुएंसी से आता हूं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पावर ग्रिड के माध्यम से आप जो कनेक्टिविटी दे रहे हैं, वह बहुत स्लो जा रही है। इसलिए मंत्री जी क्या आप उसे एनहांस करने के लिए कोई कार्रवाई करेंगे?

श्री मनोज सिन्हा: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कई सवाल एक साथ पूछे हैं। 25 हजार वाई-फाई हॉट स्पॉट केवल भारत संचार निगम लिमिटेड अपने ग्रामीण एक्सचेंजिज में लगा रहा है। कुल ढाई लाख वाई-फाई हॉट स्पॉट हम पूरे देश में लगाएंगे।

(1155/GG/KSP)

देश की कोई ग्राम पंचायत इस योजना में नहीं छूटेगी। जितने भी आपके सांसद आदर्श ग्राम हैं, सभी उसमें आ जाएंगे, इसलिए उसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ...(व्यवधान) दूसरी बात माननीय सदस्य ने हिमाचल प्रदेश की भारत नेट परियोजना के बारे में कही है। इस परियोजना को तीन सीपीएसयूज़ कर रहे हैं। एक भारत संचार निगम लिमिटिड है। दूसरा पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटिड है और तीसरा रेल-टेल है। जो हिली एरियाज़ हैं, वहां पॉवर ग्रिड को लगाया गया है, क्योंकि ओवर हैड वायर्स के माध्यम से हम ऑप्टिकल ले जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुछ गांव ऐसे हैं, जहां हम ऑप्टिकल फाइबर नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जैसे हम उत्तर-पूर्व में सैटेलाइट के माध्यम से सुविधा दे रहे हैं, वैसे ही वहां भी हम विचार करेंगे। इस परियोजना के लिए जो समय-सीमा निर्धारित है, उसी के अंदर ही इसको पूरा किया जाएगा।

DR. BOORA NARSAIAH GOUD (BHONGIR): Madam Speaker, Digital India is a very important programme, not because it is technologically innovative, but it is important because it is aimed at improving the life of poor people. Our State Telangana is very actively involved in this programme. Even the Prime Minister’s DISHA programme is also running effectively and every district has got a Coordinator. Now, under the Prime Minister’s DISHA programme, in each village 300 people are being educated. They are

made digitally literate and each person is paid Rs. 500. I have got six districts under my parliamentary constituency. I have been personally interacting with all the Coordinators. The biggest problem in villages is lack of proper net connectivity. Now, Broadband is given to villages. But unless and until net connectivity really happens, it will not be helpful. Today, under *Swacch Bharat* programme, if you want to know who has got a toilet in his house, we can check it through the App. But without net connectivity in villages, this programme cannot progress further.

So, I would like to know as to whether the hon. Minister will take it on a Mission mode. In the case of *Swacch Bharat* programme, the Government has declared that entire country will be made Open Defecation Free by 2nd October, 2019. Similarly, we can take up this programme also on a Mission mode and set a deadline. Unless and until we do it on a Mission mode by involving all State Governments and allocate adequate funds, we will not be able to really achieve the target of Digital India programme and also, we will not be able to fulfil the dream of every citizen of our country, including our Prime Minister. Therefore, I would like to know what the Minister is going to do in this direction.

श्री मनोज सिन्हा : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने सही कहा है कि डिजिटल इण्डिया के लिए जो आधारभूत संरचना है, वह हम बनाते हैं। मैं माननीय सदस्य के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि तेलंगाना राज्य के जो प्रोजैक्ट्स हैं, उनको तेलंगाना सरकार खुद ही कर रही है। हमने उनको पूरा पैसा दे दिया है। अब तेलंगाना सरकार पर निर्भर करता है कि कितनी जल्दी वे इस परियोजना को पूरा करेंगे। यदि उनको कोई टैक्निकल असिस्टेंस चाहिए, वह हम पूरी तरह से देने के लिए तैयार हैं। देश के आठ राज्य जो स्वयं इस परियोजना को कर रहे हैं, उनमें तेलंगाना भी एक राज्य है। तेलंगाना के आईटी मंत्री मुझ से मिले थे, उसके साथ कुछ और भी उन्होंने जोड़ा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि तेलंगाना की राज्य सरकार जल्दी से उस परियोजना को पूरा करेगी। हमने जो लक्ष्य रखा है, वह मार्च, 2019 तक का रखा है। हम सदन में विश्वासपूर्वक कहना चाहते हैं कि हमें उम्मीद है कि मार्च, 2019 तक हम इसे पूरा कर लेंगे।

(ends)

(Q. 106)

SHRI PINAKI MISRA (PURI): Madam Speaker, it is very disappointing that the hon. Minister of Defence is not present now. I mean no disrespect to the hon. Minister of State for Defence.

HON. SPEAKER: You should not say this. He is dealing with it and that is why he is present here.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति: आप इस तरह से राज्य मंत्री का अपमान मत कीजिए।

…(व्यवधान)

SHRI PINAKI MISRA (PURI): It is very unfortunate that when such a vital question is being taken up, the hon. Minister of Defence is not here.

HON. SPEAKER: The Minister of State is also capable.

SHRI PINAKI MISRA (PURI): I mean no disrespect to him. But the Minister of Defence should have been here.

माननीय सभापति: वे भी उत्तर देने में सक्षम हैं।

…(व्यवधान)

SHRI PINAKI MISRA (PURI): I meant no disrespect to him. I have already said that.

Anyway, these figures are alarming. These figures show that there is five times disparity in the military expenditure between India and China. We know what China's intentions in the Northeast are. They are encircling us on all sides and in the Northeast, they refuse to acknowledge Arunachal Pradesh till today and we have seen what happened in Doklam. What do we do when there is five times disparity in military expenditure between our two countries? Last year, our military expenditure was 56 billion US dollars and their figure was 216 billion US dollars. This year, our figure is 64 billion US dollars as compared to their expenditure of 228 billion US dollars. So, how long will our soldiers be martyred because of lack of military expenditure? What is the Government's thinking on this?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE): Madam Speaker, through you, I would like to inform the hon. Member as well as the House that with regard to the comparison he is trying to make and the figures that he has given, it is not exactly five times, but then I will come to his point.

(1200/SRG/CS)

Please listen to me. The total defence budgetary estimate for 2018-19 is Rs. 4,04,000 crore, which is Rs. 44,000 crore more than the budgetary estimate of 2017-18. The percentage increase in budgetary estimate for 2018-19 over budgetary estimate of 2017-18 is 12.37. The capital budget of Ministry of Defence for 2018-19 is Rs. 99,563 crore, which is an increase of almost Rs. 8,000 crore. The capital budget of 2017-18 is Rs. 91,000 crore. I would like to bring one issue to the hon. Member's notice that the capital budget of Ministry of Defence for 2018-19 is approximately 33 per cent of the total capital expenditure of the Central Government.

I will give you the comparative figures relating to China and India. There is no official data relating to China's annual defence budget available in this Ministry. However, as per Stockholm International Peace Research Institute database on military expenditure, comparative data of India and China for 2016-17 is as follows: India's military expenditure for 2016-17 in terms of percentage to GDP is 2.5 while China's military expenditure in terms of percentage of GDP is 1.9. … (*Interruptions*). Then, the percentage of government expenditure on military … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You complete the issue.

… (*Interruptions*)

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE: Please listen. As regards percentage share of Government's spending on defence, India is at 9 per cent, while China is at 6 per cent. … (*Interruptions*).

HON. SPEAKER: Thank you.

QUESTION HOUR OVER

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION

1202 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न विषयों पर कुछ सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण हैं तथापि इनके लिए आज की कार्यवाही में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है। इन्हें अन्य अवसरों पर उठाया जा सकता है, इसलिए मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

…(व्यवधान)

RE: QUESTION OF PRIVILEGE
Statements by Prime Minister and Minister of Defence

HON. SPEAKER: Yes Kharge ji… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Under Rule 220 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I hereby give notice to move Privilege Motion against Prime Minister Shri Narendra Modi … (*Interruptions*) for making misleading statement in his speech on the debate of No-Confidence Motion in Lok Sabha on 20th July, 2018. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: It is under my consideration. I will see to it.

… (*Interruptions*)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : महोदया, ये गलत कर रहे हैं।…(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर) : महोदया, हमने भी नोटिस दिया हुआ है।…(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : महोदया, रूल 222 के तथागत हम लोग एक प्रिविलेज मोशन रक्षा मंत्री के विरूद्ध मूव कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से पूरे सदन और पूरे देश को भटकाने की कोशिश की है, वे असत्य वाक्यों के आधार पर राफेल डील के नाम को छुपाने की कोशिश कर रही हैं।…(व्यवधान) क्या सरकार ने भ्रष्टाचार किया है?…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुझे सभी प्रिविलेज मोशंस मिले हैं। It is under my consideration. That's all.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, papers to be laid on the Table.

… (*Interruptions*)

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार) : महोदया, आपने खड़गे जी, ज्योतिरादित्य जी और के.सी.वेणुगोपाल जी को प्रिविलेज मोशन पर मेंशन करने का मौका दिया है।

माननीय अध्यक्ष : दोनों के प्रिविलेज मोशन अलग-अलग हैं। दो अलग-अलग नोटिसेज हैं। कुछ लोगों ने प्रधान मंत्री के खिलाफ दिया है, कुछ लोगों ने रक्षा मंत्री के खिलाफ दिया है।

श्री अनन्तकुमार : महोदया, इन चार लोगों के भी अलग-अलग नोटिसेज हैं। उनको भी एक-एक वाक्य मेंशन करने का मौका दीजिए।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अलग-अलग से मेरा मतलब है कि इनका प्रिविलेज मोशन अलग-अलग व्यक्तियों के खिलाफ है। आप सभी का प्रिविलेज मोशन एक ही व्यक्ति के खिलाफ है। इसलिए मैंने दो लोगों को बोलने की अनुमति दी है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट, आप बैठिए।

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : महोदया, हम सबका अलग-अलग नोटिस है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ज्योतिरादित्य जी, आप बैठिए। मैं आपकी बात कर रही हूँ। आप बैठिए। मैं देख रही हूँ। मैं बोल रही हूँ। आप बैठिए।

(1205/RV/KKD)

श्री अनन्तकुमार: मैडम, विषय अलग है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अनन्तकुमार जी, एक बात समझ लीजिए। मैं भी जो कर रही हूं, वह समझकर कर रही हूं। विपक्ष के पाँच लोगों ने अलग-अलग नोटिसेज दिए हैं। पाँच लोगों ने अलग-अलग प्रिविलेज नोटिसेज, against the Prime Minister दिए हैं। पाँच लोगों ने अलग-अलग प्रिविलेज नोटिसेज, against the Raksha Mantri दिए हैं। पाँच की तरफ से मैंने केवल एक-एक को बोलने की अनुमति दी है। मैंने एक माननीय सदस्य को प्रधान मंत्री के बारे में बोलने की अनुमति दी और दूसरे माननीय सदस्य को रक्षा मंत्री के बारे में बोलने की अनुमति दी।

आपकी तरफ से चार नोटिसेज हैं, but that was against one person only.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: अगर मैं आप सबको बोलने की अनुमति दूंगी तो फिर इधर से भी पाँच लोगों को बोलने की अनुमति देनी पड़ेगी।

…(व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार: मैडम, अनुराग ठाकुर जी का विषय अलग है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अनुराग ठाकुर जी को मैंने कल बोलने दिया था।

…(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): अध्यक्षा जी, कल मैं विषय को कहां रख पाया था? कल मुझे मौका नहीं मिला।…(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना): मैडम।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठिए। जब मैं बात कर रही हूं तो ऐसा नहीं चलेगा। आई-एम-सॉरी।

…(व्यवधान)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA (GUNA): It cannot be changed, now … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: आप मुझे डायरेक्ट नहीं करेंगे। पहली बात तो यह है कि आप बैठिए।

…(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना): मैडम।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, मैं नहीं सुनूंगी।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

…(Interruptions)… (Not recorded)

माननीय अध्यक्ष: मैंने देखा है और मैंने आपकी बात बोली है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अनुराग ठाकुर जी, मैं केवल आपको बोलने की अनुमति दे रही हूं। आप भी उनके जैसा केवल एक वाक्य में बोल सकते हैं।

…(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना): मैडम, उन्होंने कल बोल दिया है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने कल उन्हें उनका पूरा वाक्य बोलने नहीं दिया था।

...(व्यवधान)

RE: QUESTION OF PRIVILEGE
Statement by an Hon. Member

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): अध्यक्ष जी, मुझे आपके ध्यान में केवल इतना लाना है कि जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, उस दिन माननीय राहुल गांधी जी ने सदन को गुमराह करने का प्रयास किया, तथ्यहीन आरोप लगाए।...(व्यवधान) उसके बदले जब रक्षा मंत्री जी ने जवाब दिया और फ्रांस के राष्ट्रपति जी ने भी वहां से उत्तर देकर कहा है कि इन दोनों देशों के बीच में संधि है।...(व्यवधान) इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।...(व्यवधान)

PAPERS LAID ON THE TABLE

1207 hours

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE): On behalf of Shrimati Nirmala Sitharaman, I beg to lay on the Table:

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Aeronautical Development Agency, Bangalore, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Aeronautical Development Agency, Bangalore, for the year 2016-2017.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) यूरेनियम कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(3) इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(4) न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(5) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

(एक) भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

(एक) भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): मैं श्री एस. एस. अहलुवालिया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) (एक) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।।

(दो) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई चौधरी): अध्यक्ष महोदया, मैं खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना सं० का०आ० 2268(अ), जो 4 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जो स्थायी समिति के उप-सभापति के रूप में श्री के.के. सिंह के कार्यकाल को तीन वर्ष के लिए बढ़ाते हुए कोयला मंत्रालय में पुनर्गठित कोयला, लिग्नाइट और बालू की धराई से संबंधित खनन योजना के अनुमोदन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI RAJEN GOHAIN): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions): -

1. Memorandum of Understanding between the IRCON International Limited and the Ministry of Railways for the year 2018-2019.
2. Memorandum of Understanding between the Konkan Railway Corporation Limited and the Ministry of Railways for the year 2018-2019.
3. Memorandum of Understanding between the Mumbai Railway Vikas Corporation Limited and the Ministry of Railways for the year 2018-2019.

4. Memorandum of Understanding between the Braithwaite and Company Limited and the Ministry of Railways for the year 2018-2019.

5. Memorandum of Understanding between the Rail Vikas Nigam Limited and the Ministry of Railways for the year 2018-2019.

6. Memorandum of Understanding between the Railtel Corporation of India Limited and the Ministry of Railways for the year 2018-2019.

7. Memorandum of Understanding between the Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited and the Ministry of Railways for the year 2018-2019.

8. Memorandum of Understanding between the RITES Limited and the Ministry of Railways for the year 2018-2019.

9. Memorandum of Understanding between the Container Corporation of India Limited and the Ministry of Railways for the year 2018-2019.

10. Memorandum of Understanding between the Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited and the Ministry of Railways for the year 2018-2019.

11. Memorandum of Understanding between the Indian Railway Finance Corporation Limited and the Ministry of Railways for the year 2018-2019.

12. Memorandum of Understanding between the Kolkata Metro Rail Corporation Limited and the Ministry of Railways for the year 2018-2019.

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं नेशनल माइनरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कार्पोरेशन तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI P.P. CHAUDHARY): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 21A of the Commercial Courts Act, 2015 inserted by the Commercial Court,

Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts (Amendment) Ordinance, 2018:-

1. The Commercial Courts (Pre-Institution Mediation and Settlement) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.606(E) in Gazette of India dated 3rd July, 2018.
2. The Commercial Courts (Statistical Data) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.607(E) in Gazette of India dated 3rd July, 2018.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

1. Memorandum of Understanding between the Goa Shipyard Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2018-2019.
2. Memorandum of Understanding between the Mazagon Dock Shipbuilders Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence for the year 2018-2019.

3. Memorandum of Understanding between the Hindustan Shipyard Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence for the year 2018-2019.
4. Memorandum of Understanding between the Mishra Dhatu Nigam Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence for the year 2018-2019.
5. Memorandum of Understanding between the Bharat Electronics Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2018-2019.
6. Memorandum of Understanding between the Bharat Electronics Limited and the BEL Optronic Devices Limited for the year 2018-2019.
7. Memorandum of Understanding between the Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence for the year 2018-2019.
8. Memorandum of Understanding between the Bharat Dynamics Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2018-2019.

9. Memorandum of Understanding between the BEML Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2018-2019.

…

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I have to report the following message received from the Secretary-general of Rajya Sabha:-

"In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 23rd July, 2018 agreed without any amendment to the Specific Relief (Amendment) Bill, 2018 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 15th March, 2018."

…

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS
42nd Report

SHRI THANGSO BAITE (OUTER MANIPUR): I beg to present the Forty-second Report (Hindi and English versions) of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

प्राक्कलन समिति
29वां प्रतिवेदन

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (कानपुर): महोदया, मैं रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'सशस्त्र बलों की तैयारी–रक्षा उत्पादन और खरीद' विषय पर प्राक्कलन समिति (2018-19) का 29वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(1210/MY/RP)

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति
की-गई-कार्रवाई संबंधी 29वां प्रतिवेदन

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर): अध्यक्ष महोदया, मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (16वीं लोक सभा) के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर समिति का की-गई-कार्रवाई संबंधी 29वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति 22वां तथा 23वां प्रतिवेदन

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद): अध्यक्ष महोदया, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2018-19) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

(1) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) से संबंधित "अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास में विश्वविद्यालयों, तकनीकी, चिकित्सा और अभियांत्रिकी संस्थाओं सहित शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका-दिल्ली विश्वविद्यालय में आरक्षण नीति का कार्यान्वयन" विषय पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के पांचवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के बारे में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 22वां प्रतिवेदन।

(2) रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) से संबंधित "आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और नियोजन" विषय पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 31वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के बारे में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 23वां प्रतिवेदन।

कृषि संबंधी स्थायी समिति
52वां तथा 53वां प्रतिवेदन

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): अध्यक्ष महोदया, मैं कृषि संबंधी स्थायी समिति (सोलहवीं लोक सभा) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

(1) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित "एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना के लिए स्कीम का क्रियान्वयन" विषय पर 45वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 52वां प्रतिवेदन।

(2) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (पशुपालन, डेरी और मत्स्य पालन विभाग) से संबंधित "अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलकृषि विकास स्कीम-एक विश्लेषण" विषय पर 53वां प्रतिवेदन।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति
24वां प्रतिवेदन

श्री प्रह्लाद जोशी (धारवाड़): अध्यक्ष महोदया, मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के "पेट्रोलियम क्षेत्र में सुरक्षा, संरक्षा और पर्यावरण संबंधी पहलू" विषय पर 24वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति
की-गई-कार्रवाई विवरण

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) खान मंत्रालय से संबंधित "खनन क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/अनुसंधान और विकास" संबंधी 22वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों संबंधी 31वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(2) इस्पात मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2017-18)' के बारे में 29वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों संबंधी 33वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(3) खान मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2017-18), 28वें प्रतिवेदन (16वीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों संबंधी 34वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(4) कोयला मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2017-18)' के बारे में 27वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों संबंधी 35वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-I और 5 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(5) खान मंत्रालय से संबंधित ‘खनन क्षेत्र में कौशल विकास' के बारे में 32वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों संबंधी 41वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-I में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 302nd, 310th AND 315th REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENVIRONMENT AND FORESTS —LAID

1212 hours

THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, MINISTER OF EARTH SCIENCES AND MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (DR. HARSH VARDHAN): I beg to lay the following statement regarding: -

(1) the status of implementation of the recommendations contained in the 302nd Report of the Standing Committee on

Science and Technology, Environment and Forests on action taken by the Government on recommendations/observations contained in the 294th Report of the Committee on Demands for Grants (2017-18) pertaining to the Ministry of Earth Sciences.

(2) the status of implementation of the recommendations contained in the 310th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on Demands for Grants (2018-19) pertaining to the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology.

(3) the status of implementation of the recommendations contained in the 315th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on Demands for Grants (2018-19) pertaining to the Ministry of Earth Sciences.

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 60th REPORT OF STANDING COMMITTEE ON FINANCE —LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE): Hon. Speaker Madam, on behalf of Shri Rao Indrajit Singh, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 60th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2018-19), pertaining to the Ministry of Planning.

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 18th REPORT OF STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI RAJEN GOHAIN): I beg to make a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 18th Report of the Parliamentary Standing Committee on Railways, Sixteenth Lok Sabha.

The 18th Report of the Committee on Tourism on 'Tourism Promotion and Pilgrimage Circuit' presented to the Lok Sabha on 4th

January, 2018, contains 12 recommendations and action taken notes thereon were furnished to the Committee on 19th June, 2018 in English and Hindi.

A statement showing details of all the recommendations contained in the Report and implementation status thereon is enclosed. Since the statement is voluminous, I request that the same may be taken as read.

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 21st REPORT OF STANDING COMMITTEE ON DEFENCE —LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 21st Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants (2016-17) (Miscellaneous, Demand No. 20), pertaining to the Ministry of Defence.

(1215/RCP/CP)

ELECTION TO COMMITTEE

Tea Board

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY AND MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI SURESH PRABHU): I beg to move the following:-

> "That in pursuance of clause (f) of sub-section (3) of the section (4) of the Tea Act, 1953 read with rules 4(1)(b) and 5(1) of the Tea Rules 1954, the members of this House do proceed to elect, in such manner, as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Tea Board, subject to the other provisions of the said Act and Rules made thereunder."

HON. SPEAKER: The question is:

> "That in pursuance of clause (f) of sub-section (3) of the section (4) of the Tea Act, 1953 read with rules 4(1)(b) and 5(1) of the Tea Rules 1954, the members of this House do proceed to elect, in such manner, as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Tea Board, subject to the other provisions of the said Act and Rules made thereunder."

The motion was adopted.

कार्य मंत्रणा समिति
55वें प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> " कि यह सभा 24 जुलाई, 2018 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 55वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

HON. SPEAKER: The question is:

> "That this House do agree with the Fifty-fifth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 24th July, 2018."

The motion was adopted.

… (*Interruptions*)

SPECIAL MENTIONS

1217 hours

HON. SPEAKER: Now, 'Zero Hour'.

… (*Interruptions*)

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): माननीय स्पीकर महोदया, पश्चिम बंगाल में …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं मौका दूंगी। जरा शांति रखिए।

…(व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, I would like to invite the attention of the Government to the massive breach of candidate data who appeared for the NEET examination this year. As per the reports, the data is available in certain websites for a price. It has been pointed out that the data of around two lakh students have been leaked. This is a serious issue of theft of personal data that has compromised the privacy of candidates across the country.

This also highlights the serious lack of safeguard to prevent data breach. This also questions the ability of the CBSE to ensure the sanctity of the examination process. The PTI reported that the names, phone numbers, and email addresses, besides NEET scores and rankings, of over two lakh candidates were available online for a

price. The buyers were willing to pay up to Rs. 2 lakh for this personal data of students. More than 1.3 million candidates appeared for the exam this year out of which data for 2,50,000 students is available for anyone willing to pay lakhs of rupees for access to this data. This is a serious issue of theft of privacy.

At a time when the debate on privacy and data protection is on full stream in the country with a panel headed by Justice Srikrishna set to draft a privacy Bill, the website's use of people's private information comes as a major threat to privacy.

Last year also, CBSE examination paper leaked. With this type of leaking, people are losing credibility of the examinations. Therefore, this is one of the serious issues. The Government should come forward and put up an enquiry on that. These types of things should not be repeated.

HON. SPEAKER: Dr. P.K. Biju, Shri M. B. Rajesh and Adv. Joice George are permitted to associate with the issue raised by Shri K.C. Venugopal.

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): स्पीकर महोदया, पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ में अवमान किया जाता है। जलपाईगुड़ी जिले में चार महिलाओं के साथ मॉब लिंचिंग हुई। उसमें दो महिलाओं का वस्त्रहरण किया गया। बात सिर्फ यहीं पर नहीं

रूकी। उन महिलाओं के ऊपर पुलिस ने आरोप लगाया। …(व्यवधान) उन चार महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से दो का वस्त्रहरण किया गया। …(व्यवधान) यह पश्चिम बंगाल सरकार, जिसकी माननीय मुख्यमंत्री महिला हैं, उनके राज्य में इस प्रकार की घटना हो रही है। …(व्यवधान)

इसी प्रकार से केरल में एक 32 वर्ष का नौजवान, जिसका नाम है मानिक रॉय, उसको मुर्गी चोर कहकर उसकी हत्या कर दी गई। …(व्यवधान) 27 साल का आसिफ और 62 साल के शशिधरा कुरूप …(व्यवधान) केरल में मैं आपको और बताना चाहूंगा। 28 जनवरी को एक प्रेगनेंट वूमेन, यानी जो महिला गर्भवती थी, उस गर्भवती महिला का लिंचिंग किया गया। …(व्यवधान)

(1220/SMN/NK)

इसी प्रकार से 30 जनवरी को एक इन्टेलैक्चुअल डिसेबल महिला थी, उस महिला को कहा गया कि न्यूसन्स क्रिएट कर रही है, …(व्यवधान) वह पागल है, उसके साथ छेड़छाड़ की गई, उसके इज्जत के साथ खेला गया। …(व्यवधान) यह आप लोगों ने क्या लगाया है? …(व्यवधान) पश्चिम बंगाल में चार महिलाओं में दो महिलाओं का वस्त्रहरण किया गया, आपको शर्म आनी चाहिए, महिलाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। केरल में दलितों के साथ …(व्यवधान)।

HON. SPEAKER: Now, Shrimati P.K. Shreemathi Teacher.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : किरीट सोमैया जी हो गया, अब आप बैठ जाइए।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री शरद त्रिपाठी, श्री निशिकान्त दुबे, श्री उदय प्रताप सिंह, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री नारणभाई काछड़िया, डॉ किरिट पी सोलंकी और कुमारी शोभा कारान्दलाजे को डॉ किरीट द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER (KANNUR): Madam Speaker, the House is not in order. … (*Interruptions*) It is a very important subject. How can I speak? … (*Interruptions*)

1221 hours

(*At this stage, Shri Idris Ali and some other hon. Members came and stood near the Table.*)

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER (KANNUR): This is a very important subject.

माननीय अध्यक्ष : बैठ जाइए, किरीट सोमैया जी क्या हो रहा है?

…(व्यवधान)

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER (KANNUR): What is he doing? … (*Interruptions*) He is a Member from Ruling Party. He is creating … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : कोई अपनी सीट से नहीं जाएगा। यह क्या हो रहा है?

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 12.30 p.m.

1221 hours

The Lok Sabha then adjourned till thirty minutes past of the Twelve of the Clock.

(1230/MMN/SK)
1230 hours

The Lok Sabha re-assembled at thirty minutes past Twelve of the Clock.
(Hon. Speaker *in the Chair*)

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठिए।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Now this is very bad. I am sorry.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: आप सब बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): गृह मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यहां कोई नहीं है, देना चाहें तो दे सकते हैं। I cannot say anything.

…(व्यवधान)

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): माननीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी को इस विषय पर जवाब देना चाहिए।…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: No, I cannot say. Please sit down.

Now, Shreemathi Teacher.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: मेरा सबसे निवेदन है, आप ऐसे आकर करना शुरु करेंगे तो मेरे लिए वास्तव में कठिन हो जाएगा। आप सबको गुस्सा आना स्वाभाविक है। एक-दूसरे के खिलाफ आरोप होते हैं। That is what I am saying. Yes, I am not saying anything but please do not cross the limit. That is my only request, please. That is the thing. Otherwise, I am not saying anything.

… (*Interruptions*)

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER (KANNUR): Madam, Speaker, it is a very important subject.… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: He also should not do that. It is not you alone but I mean both of you. मैं किसी एक को नहीं बोल रही हूं। इधर भी बोल रही हूं, उधर भी बोल रही हूं। आप सब कुछ तो ध्यान रखें।

श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर।

…(व्यवधान)

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER (KANNUR): Hon. Madam Speaker, thank you so much for giving me an opportunity to speak about an important subject, that is, on the Women's Reservation Bill.

Madam Speaker, it is with a sense of deep disappointment and sorrow that I bring to your attention yet again the easy-going attitude of the Government towards bringing the Women's Reservation Bill

which provides 33.3 per cent reservation for women, in the agenda of our Lok Sabha. I would like to point out that the present Government had made promise to the women of our country in their election manifesto, expressing their commitment to the passage of this Bill.

Madam, promise is a promise. Promise should be fulfilled. It is not to be broken. It is now four years since it came to power with two-thirds majority. Though public statements of noble intentions for empowerment of women and girls have been made by the Ministers and the Party leadership quite frequently over the years, this has not reflected into action with regard to the Women's Reservation Bill, as a result, presence of women in the Lok Sabha, Parliament, remains at 11.7 per cent, and at the State Legislative Assemblies also, it shows a similar gender imbalance.

Women's rights, as per our Constitution, mainly include dignity and freedom from discrimination. Article 4 of the Constitution guarantees to all the Indian women equality. Article assures no discrimination. Article assures equality for opportunity. Where do we, the Indian women, get equal opportunities? Nowhere. Why? The

Government has the responsibility to assure equal opportunities to the women. Do not deny the minimum rights of Indian women.

Madam, as the Speaker of the Sixteenth Lok Sabha, you have often spoken out in defence of women's rights, including their right to minimum representation in the highest decision-making bodies. Hence, I make an appeal for your intervention on this issue that has been pending, as you know, for over 20 years. I request you, hon. Madam, to interfere with the ruling Government and ensure that 33 per cent reservation giving Women's Reservation Bill, which has already gone through a long process of consultation at all levels, is brought to this Parliament and passed without any further delay before 8th March, 2019. Thank you.… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Yes, you all will support it.

Shrimati Arpita Ghosh, Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Mullappally Ramachandran, Shri Rajeev Satav, Shrimati Supriya Sule, Shri Dhananjay Mahadik, Dr. P.K. Biju, Shri M.B. Rajesh, Adv. Joice George, Dr. A. Sampath, Shri Md. Badaruddoza Khan, Shri Sankar Prasad Datta, Shri Rabindra Kumar Jena, Shri N.K. Premachandran, Shrimati V. Sathyabama, Dr. J. Jayavardhan, Shri

P. Karunakaran and Dr. Kulamani Samal are permitted to associate with the issue raised by Shrimati P.K. Shreemathi Teacher.

(1235/RPS/VR)

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): मैडम, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दिल्ली में लगभग एक लाख लोग, जो अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित हैं और पिछले 50-60 वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं। उन्होंने लेबर क्लास के रूप में काम करना शुरू किया था। जब उन्होंने वहां पर रहना शुरू किया था, वहां उनके पक्के मकान हैं, सब कुछ है, लेकिन भाटी माइन्स के अंदर एक कॉलोनी है – संजय कॉलोनी, इसी प्रकार से लालकुआं, भीम बस्ती, शम्भू बस्ती और नेब सराय हैं। इन सभी जगहों पर अनुसूचित जाति वर्ग के लोग रहते हैं और पिछले चार दशकों मे अनुसूचित जाति वर्ग की दुहाई देने वाली और उनकी ठेकेदार बनने वाली सरकारें और मुख्यमंत्री रहे हैं। वहां वर्ष 1998 में एनजीटी आने के बाद, उस लैण्ड को, जहां वे एक लाख अनुसूचित जाति वर्ग के लोग रह रहे हैं, एनजीटी और सरकारों के माध्यम से, तीन बार कांग्रेस की मुख्यमंत्री रहीं, रिज और फॉरेस्ट एरिया में डाल दिया गया। रिज एरिया में डालने की वजह से उनकी बेसिक अमेनिटीज जैसे पानी सप्लाई, सीवर लाइन, सड़क की मरम्मत आदि कोई काम सरकारें रिज एरिया के नाम पर नहीं करती हैं। वहां वे लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं। ये सरकारें, जो बार-बार अनुसूचित जाति वर्ग की ठेकेदार बनती थीं, पिछले 50 साल में उनके लिए कुछ नहीं किया। आज भी दिल्ली में जो मुख्यमंत्री हैं, वे आरएमबी के चेयरपर्सन हैं।

मैडम, यह एक लाख लोगों का सवाल है, उनको रोज वहां से उठाने की बात होती है और कोई फेसिलिटीज उनको नहीं मिलती हैं। वे बेचारे अपने घर में ईंट नहीं लगा सकते हैं। 50 साल से रह रहे हैं, अगर बेटे की शादी हो गई, अब एक नया कमरा बनाने की सोचें तो वे अपने ही प्रिमाइसेस में उसे नहीं बना सकते हैं। यह मेरा आपसे निवेदन है और यह बात आपके माध्यम से शहरी विकास मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री तक जानी चाहिए कि आरएमबी के अंदर जो चेयरमैन हैं, जो राज्य सरकार में इंचार्ज हैं, वे उन घरों का सर्वे कराकर, उनको रिज एरिया से बाहर निकाला जाए और उसके बदले ग्राम सभा की दूसरी जमीन को रिज डिक्लेयर किया जाए। अनुसूचित जाति वर्ग के उन एक लाख लोगों के साथ न्याय किया जाना चाहिए। यह सरकार 'सबका साथ सबका विकास' करने वाली है, यह इनकी तरह तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली सरकार नहीं है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष **:** श्री भैरों प्रसाद मिश्र, डॉ. कुलमणि सामल और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री मधुकरराव यशवंतराव कुकडे (भंडारा-गोंदिया): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे जीरो आवर में बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं भंडारा जिले से आता हूं, हमारे यहां त्रिवडी से लेकर कटंगी परियोजना वर्ष 1998 में मंजूर की गई थी। आज बीस साल हो गए हैं, लेकिन वह परियोजना अभी तक पूरी नहीं हुई है। यदि यह परियोजना पूरी हो जाएगी तो विदर्भ को न्याय मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र एवं स्टेट की सरकारें अलग विदर्भ राज्य नहीं दे रही हैं। इससे

बालाघाट और मंडला जिले जुड़ जाएंगे और हमारे सामरिक विषयों को निपटाएंगी। सिर्फ 12 किलोमीटर लम्बी इस परियोजना को बनने में 20 साल लग गए। वर्ष 1998 में आदरणीय ममता बनर्जी जी जब रेलवे मंत्री थीं, उन्होंने इसे मंजूर किया था। इसके साथ ही, गोंदिया से लेकर जबलपुर नैरोगेज और ब्रॉडगेज लाइन परियोजना अभी तक पूरी नहीं हुई है। अगर ये दोनों परियोजनाएं पूरी जाएं तो विदर्भ की जनता के साथ न्याय होगा और उनका विकास होगा। भंडारा के अंदर जिला मुख्यालय है, वहां पहले एक गुड्स शेड था, उसे सरकार ने बन्द कर दिया। अगर वह गुड्स शुड शुरू हो जाएगा तो धान के आवागमन के लिए काम आएगा। अगर आप ये काम करेंगे तो विदर्भ की जनता को न्याय मिलेगा। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष **:** श्रीमती सुप्रिया सुले और श्री धनंजय महाडीक को श्री मधुकरराव यशवंतराव कुकडे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री विजय कुमार हांसदाक (राजमहल): मैडम, मैं एक विशेष मुद्दे पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आदिवासी काफी समय से अलग धर्म कोड की मांग कर रहे हैं – सरना धर्म कोड। धर्म कोड नहीं होने की वजह से कई राज्यों में आदिवासियों को हिन्दू धर्म में लिखा जाता है, जो कि वे हैं नहीं। सरना धर्म और सनातन धर्म, दोनों अलग हैं। हम लोग अपनी जाति के रूप में आदिवासी लिखते हैं। कई जगह पर जाति और धर्म के नाम पर कन्फ्यूजन क्रिएट कर जनगणना को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि जाति के आधार पर आदिवासियों की गणना हो। मैं सदन के समक्ष यह बात बोलना चाहता हूं कोर्ट भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी है कि आदिवासी

इस देश के फर्स्ट इंडिविजुअल्स हैं। कई कानून, जो आदिवासियों को बचाने के लिए कई राज्यों में बने हुए हैं जैसे फिफ्थ शिड्यूल, सिक्स्थ शिड्यूल, पीईएसए, सीएनटी एंड एसपीटी एक्ट आदि सभी के साथ लगातार छेड़छाड़ हो रही है, इन्हें कमजोर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हें बचाने की जरूरत है।

आदिवासी, जिनका इतिहास बहुत रिच है। आजादी की पहली लड़ाई, अगर हम अपने देश में ही इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बाहर के लोग इसे कैसे जानेंगे, 1857 की लड़ाई को देश की आज़ादी की पहली लड़ाई मानी जाती है, लेकिन 1855 की सिद्धू-कान्हू जी की 'हुल क्रान्ति' अंग्रेजी के खिलाफ आज़ादी की पहली लड़ाई है। मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज इसे पूरे देश की हिस्ट्री की किताबों में पढ़ाया जाना चाहिए। यही मांग रखकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

(1240/ASA/SAN)

माननीय अध्यक्ष : श्री जितेन्द्र चौधरी, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, शंकर प्रसाद दत्ता, श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान, डॉ. कुलमणि सामल, श्री निशिकान्त दुबे और श्री पी.आर.सुन्दरम को श्री विजय कुमार हांसदाक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : माननीय अध्यक्ष महोदया, वैसे तो पूरे देश में तकरीबन 156 जिले सूखे की चपेट में हैं। बिहार में भयंकर सूखा इस बार पड़ा है। लगभग 36 जिले सूखे की चपेट में हैं जिनमें से 13 जिलों में 60 से 86 प्रतिशत तक बारिश नहीं हुई है। धान की रोप नहीं हुई लेकिन बिचड़े भी सूख रहे हैं और डीजल की कीमतें एक तो आसमान छू रही हैं और दूसरे सब्सिडी लेने में भी उनको पसीने छूट रहे हैं। इनमें

तमाम जिले- सुपौल से लेकर मधेपुरा, पूर्णिया, गोपालगंज, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, अररिया, कटिहार, बक्सर, भभुआ, रोहतास, नवादा, नालंदा, जमुई, लखीसराय, दरभंगा इत्यादि तमाम जिले भीषण सूखे की चपेट में हैं। मैं सरकार से सिर्फ यह आग्रह करना चाहती हूं कि ये पूरे जिले पूरी तरह से सूखे की चपेट में हैं, इसलिए पूरे बिहार को सूखा क्षेत्र घोषित किया जाए और जो स्पेशल मुआवजा किसानों के लिए है, उसका एक विशेष पैकेज बिहार के लिए घोषित किया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. सजय जायसवाल, डॉ. कुलमणि सामल और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

*SHRI THOTA NARASIMHAM (KAKINADA): Madam, I thank you for giving me this opportunity to speak. I will speak in my mother tongue, Telugu.

Madam Speaker, the issue of special category status and other provisions of Andhra Pradesh Re-organization Act, pertaining to Andhra Pradesh, were discussed in a day long debate of Motion of No Confidence and also in short duration discussion on this subject in Rajya Sabha.

Our MPs from Andhra Pradesh are questioning Central Government over injustice meted out to our state, but we are not getting proper reply from the Government. People of Andhra Pradesh are raising their voice against injustice meted out by Central Government to our state. There are protests and agitations throughout the state. We passed Andhra Pradesh Re-organisation Bill in 2014.

---

*Original in Telugu

It is the responsibility of the present Government to implement provisions of the Act. At the time of passage of that bill, present Government was sitting in opposition. Yesterday Dr. Manmohan Singh stated that Special Category Status to Andhra Pradesh was discussed with opposition parties before giving assurance. But till date, there is no reference to that assurance by the present Government. We pass bills in the Parliament with the spirit of our constitution framed by Dr. BR Ambedkar. It is the responsibility of all members to implement laws passed by the Parliament.

But the Central Government is insensitive to Andhra Pradesh and it is not referring to problems due to bifurcation, faced by people of Andhra Pradesh. Shri Narendra Modi, while replying to Motion of No Confidence spoke for one & half hour and made a political speech, but not mentioned about the assistance that the Government would offer to AP.

Yesterday also while replying to debate in Rajya Sabha, there was similar approach. As Mr. Modi represent Varanasi which is also known as Kasi, we have a tradition of give up our favourite thing in holy river Ganga. It seems Shri Narendra Modi sacrificed assurances & promises given to Andhra Pradesh in river Ganga. They are referring to 14th Finance Commission and citing other reasons. I demand this Government to show, where it is mentioned by 14th Finance Commission that Andhra Pradesh should not be accorded with special category status. We don't get any answers. They come out with new argument every day. They referred to 14th Finance Commission, they promised special package. Now they are talking about SPV (Special Purpose Vehicle). For that also there is no action.

Central Government is cheating people of Andhra Pradesh by spreading lies; we on behalf of TDP highlight this attitude of the Government through Motion of No Confidence

and Short duration discussion. The demands of people of Andhra Pradesh should be met in all circumstances. We are reflecting the sentiments and emotions of Andhra Pradesh but Central Government is ignoring concerns of Andhra Pradesh. There are many issues throughout the country that are being discussed here, and I demand reply for issues pertaining to Andhra Pradesh.

(1245/RBN/RAJ)

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Shri Thota Narasimham has expressed his anguish and pain over the division of Andhra Pradesh. At the same time, the hon. Prime Minister, while replying to No Confidence Motion often said what we have done for Andhra Pradesh and refuted the politically motivated allegations. Not only that, he also said that the Government of India is for the welfare of Andhra Pradesh.

HON. SPEAKER: Thank you.

SHRI SANKAR PRASAD DATTA (TRIPURA WEST): Madam Speaker, thank you for giving me this opportunity to speak.

The people of Tripura are passing through hard days in the last four months of BJP-IPFT alliance Government. Most of the workers do not have any work to do. Agricultural workers have nothing to do in the agricultural field. The petty shopkeepers have to wait the whole day to sell a little portion of their stock. Even the *chaiwala* is selling only a few cups of tea. Earlier, workers used to have work and were earning minimum of Rs. 600 to Rs. 800 per day. As there were plenty of job opportunities in the State, workers from other States were

interested to come and engage themselves in Tripura to earn their proper livelihood. Now-a-days they are leaving Tripura and the workers of Tripura are getting only Rs. 300 to Rs. 400 only.

Why, in these four months, are people not in a position either to do work or to sell their commodities for their daily earning? Earlier, at the time of the Left Front Government in the State of Tripura, people used to get 80 to 90 days of MGNREGA work. Not only that, Forest, Agriculture and Horticulture Departments used to engage people to do development work. Maximum number of tribal, dalit, OBC and poor people of other sections used to earn plenty of money to maintain their daily food and lodging requirements. Enough money was in circulation throughout the State which made their lives proper.

As there is no money in the hands of hilly and village people, today in the Fair Price Shops also dealers are waiting for selling rice and flour for so many days. Rotten food is being distributed in the Fair Price Shops of the State. I am having some sample of rotten flour collected from a hilly Fair Price Shop of Khamting ADC village of Sinaicamipara. Now, I am having this sample with me. This is rotten flour. Insects are loitering hither and thither. If you want I can give you the sample.

HON. SPEAKER: This is not proper.

SHRI SANKAR PRASAD DATTA (TRIPURA WEST): Please see whether this can be eaten by people or not. Even animals are not eating this type of rotten flour and rice.

I strongly urge upon the Central Government that the Centre should allocate adequate money to the State of Tripura for MGNREGA and other Department works and supply good quality food to the State of Tripura. Otherwise, starvation will ruin the people and the State of Tripura. Thank you.

HON. SPEAKER: Dr. Kulmani Samal, Shri Jitendra Chaudhury, and Shri Md. Badaruddoza Khan are allowed to associate with the matter raised by Shri Sankar Prasad Datta.

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD): Hon. Speaker Madam, I would like to raise an important issue regarding the construction of border road along with barbed wire fencing in Madhugari Gram Panchayat area under Karimpur – I Development Block in the district of Nadia, West Bengal which comes under my parliamentary constituency.

(1250/AK/IND)

Madam, the River Padma was flowing inside the Indian territory before 1996, but suddenly, it has changed its course between the years 1996 and 2003 and started flowing through Bangladesh territory engulfing the river Mathabhanga. As a result, there was erosion and re-alignment of Indo-Bangladesh demarcation line.

Nearly, 3,500 acres of Indian cultivable land -- falling within the limits of Madhugari Gram Panchayat -- have been found to have emerged as the 'Fertile Charland' to the north of River Padma within India. The Indian cultivators, belonging to this sector, had so far been earning their livelihood by cultivating this huge area. But now, through reliable sources, I have come to know that the Government is going to undertake re-construction work of the Border Road along the southern side of the present course of the River Padma far from the Indo-Bangladesh demarcation line.

I would like to request the hon. Minister, through you, Madam that the construction work should take place at a distance of 150 metres from the Indo-Bangladesh Radcliffe Line of demarcation. I am saying this because if the Border Road and barbed wire fencing are constructed far from the demarcation line, then 3,500 acres of the

Indian cultivable land will go to the Bangladesh goons and the Indian cultivators will face huge difficulty in accessing their land for cultivation.

So, I would request the Government to look into the matter on humanitarian grounds, and construct the Border Road and barbed wire fencing within 150 metres from the Indo-Bangladesh Radcliffe Line.

माननीय अध्यक्ष : श्री शंकर प्रसाद दत्ता और श्री जितेन्द्र चौधरी को श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Yes, but the 'Zero Hour' submissions should always be short.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): माननीय अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण मानिकपुर जंक्शन स्टेशन है। यहां से सैकड़ों गावों के लोग रोज आते-जाते हैं। यहां से जबलपुर से लखनऊ तक चित्रकूट एक्सप्रेस के नाम से ट्रेन चलती है। 25 तारीख से इस ट्रेन का रूट बदला जा रहा है और उसे बायपास से निकाला जा रहा है। इसके पहले भी जबलपुर से दिल्ली के लिए महाकौशल एक्सप्रेस चलती थी, उसका भी रूट बदल दिया गया। इस वजह से लोगों को बहुत असुविधा हो रही है। ऐसे ही दुर्ग से लखनऊ तक गरीब रथ ट्रेन चलती थी, उसका भी रूट मानिकपुर से बदल दिया गया।

ऐसे ही दुर्ग-कानपुर ट्रेन का रूट बदला गया। इस वजह से लोगों में बहुत आक्रोश है। चित्रकूट ट्रेन का रूट बदलने से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। मैंने इसके अस्थायी समाधान के लिए रेल मंत्रालय में अनुरोध किया था कि यदि बायपास से ट्रेनें मानिकपुर जाने में लेट होती हैं, तो जहां से बायपास ट्रेन का रूट कर रहे हैं, वहां एक हॉल्ट स्टेशन बना दिया जाए। इसका सर्वे भी हो चुका है, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है।

महोदया, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से और सरकार से अनुरोध है कि जब तक हॉल्ट स्टेशन नहीं बन जाता है, तब तक चित्रकूट ट्रेन का रूट न बदला जाए। जो ट्रेनें पहले से बायपास से जा रही हैं, उन्हें भी मानिकपुर से ही भेजा जाए। जब हॉल्ट स्टेशन बन जाए, तभी इन ट्रेनों का रूट बदला जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री नव कुमार सरनीया (कोकराझार) : महोदया, आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। असम के आदिवासी विशेषकर मुंडा, गौरा, संथाल, औराव, खरिया, किसान बहुत पहले से जनजाति में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। चुनाव के दौरान भी माननीय प्रधान मंत्री जी हमारे क्षेत्र में आये थे और उन्होंने कहा था कि 'राजबंगशी' को जनजाति का दर्जा दिया जाएगा। असम के चुनाव में यह एक बड़ा मुद्दा था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

वर्ष 1996 में एक अध्यादेश के जरिए 'राजबंगशी' जाति को जनजाति का दर्जा प्राप्त करने का एक मौका मिला था, लेकिन वह संविधान में जोड़ी नहीं गई। मौरान, मोटक, सुतिया, अहम भी जनजाति के तहत आने के लिए मांग कर रहे हैं और हमारे

संसदीय क्षेत्र में तीन डिस्ट्रिक्ट बक्सा, सीरान, कोकराझाड़ सिक्स्थ शेड्यूल में आते हैं। यदि वे जनजाति में शामिल नहीं किए जाते हैं तो उन्हें जमीन का अधिकार नहीं मिलता है, उन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं मिलता है और न कोई आर्थिक सहायता मिलती है। प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत उन्हें जो घर भी मिले हैं, उसका फायदा भी उन्हें नहीं मिल रहा है। कलिता और नाजुकी भी मांग कर रहे हैं। यदि इन्हें जनजाति में शामिल नहीं किया जाता है, तो इन्हें कोई अधिकार नहीं मिलता है। प्रधान मंत्री और असम सरकार ने जो वायदा किया था, वह वायदा पूरा होना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि यह जल्दी ही इस मुद्दे का समाधान किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री जितेन्द्र चौधरी, श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान और श्री शंकर प्रसाद दत्ता श्री नव कुमार सरनीया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(1255/vb/spr)

श्री हरीश मीना (दौसा): माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे एक महत्त्वपूर्ण मुद्दे, जिससे देश के युवाओं के भविष्य का सवाल जुड़ा हुआ है, पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

सरकार की जो नीति है, उसके तहत सरकारी सेवाओं का निजीकरण हो रहा है और इसके कारण युवाओं का बहुत नुकसान हो रहा है। निजीकरण के कारण ठेकेदार काम करने वाले युवाओं को कम तनख्वाह देते हैं और उनसे ज्यादा काम लेते हैं। इस प्रकार से ठेकेदार युवाओं का शोषण करते हैं।

गरीबों और दलितों के लिए सरकारी सेवाओं में जो आरक्षण की व्यवस्था हुई थी, वह बिल्कुल समाप्त हो गयी है। इन्हीं नीतियों के कारण, महाराष्ट्र में मराठाओं के आंदोलन, गुजरात में पाटीदारों के आंदोलन और हरियाणा में जाटों के आंदोलन हो रहे हैं।

मेरे संसदीय क्षेत्र दौसा में न कृषि योग्य जमीन है, न कोई उद्योग है, वहाँ के युवा नौकरी के लिए कहाँ जाएंगे? इसलिए आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि सरकारी सेवाओं में कमी न की जाए और निजीकरण को बंद किया जाए ताकि हमारे युवाओं को सरकारी नौकरियाँ मिल सकें।

माननीय अध्यक्ष : सर्वश्री भैंरो प्रसाद मिश्र, राहुल शेवाले, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, अरविंद सावंत, विनायक भाऊराव राऊत, डॉ. हिना विजयकुमार और गावीत कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री हरीश मीना द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Madam, I would like to urge upon the Government to sanction financial assistance to Endosulfan victims of the Kasargod district of Kerala, and also to the victims in some places of Karnataka.

Endosulfan is a highly toxic pesticide. It has been used for a long time in the cashew plantations by companies. As a result about 600 people have lost their lives. Madam, 10,000 people are taking treatment. I have been raising this issue in the House many times in

the past. The Government of Kerala has taken a number of measures. Pension scheme is implemented; free ration is given; medical facilities are given.

In the recent times, the Supreme Court has given a verdict to the effect that compensation should be paid to these victims. It is also stated in the verdict that the Central Government also has to give its share. The State Government has requested for Rs.483 crore to meet the expenses in this regard. But the Central Government has not yet extended any assistance. This issue should be taken as a humanitarian grounds as it is considered as a very big issue affecting women, children and others. Hence, I would request the Government to sanction financial assistance of Rs.483 crore to Kerala.

माननीय अध्यक्ष : सर्वश्री पी.के. बिजू, श्री एम.बी. राजेश, एडवोकेट जोएस जॉर्ज, डॉ. ए. सम्पत, श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर को श्री पी. करुणाकरन द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): माननीय अध्यक्ष महोदया, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नगर के सुपुत्र स्वर्गीय दादा साहेब फाल्के जी, जिन्हें भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का पितामह कहा जाता है, को 'भारत रत्न' देकर सम्मानित करने की माँग मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से करता हूँ।

आप जानते हैं कि उन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को देश और विश्व में एक अच्छे स्थान पर पहुँचाया है। आज भारतीय फिल्म इंडस्ट्री करोड़ों रुपये का व्यापार कर रही है। लाखों लोग उससे अपना गुजारा कर रहे हैं। श्री अमिताभ बच्चन जी जैसा महान् अभिनेता भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने दिया। लेकिन, इसकी शुरुआत आज से 105 वर्ष पहले स्वर्गीय दादा साहेब फाल्के ने वर्ष 1913 में शुरू की। कठिन परिस्थितियों के बावजूद समस्याओं का सामना करते हुए उन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में 'राजा हरिश्चन्द्र' नामक फिल्म का निर्माण किया था। उसके बाद 'भस्मासुर मोहिनी' जैसी 125 फिल्में उन्होंने बनायीं और फिल्म जगत् में कला के क्षेत्र में भविष्य-निर्माण के लिए एक नया दरवाज़ा खोला।

74 वर्ष की आयु में 125 फिल्मों का निर्माण करने के बाद वे गुजर गये। उन्होंने जो कार्य किये, यदि उनकी तरफ देखें, तो उनका उचित सम्मान केन्द्र सरकार की ओर से करने की जरूरत है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से माँग करता हूँ कि स्वर्गीय दादा साहेब फाल्के जी को 'भारत रत्न' देकर उनका सम्मान किया जाए ताकि पूरे फिल्म इंडस्ट्री का सम्मान हो सके।

माननीय अध्यक्ष : सर्वश्री भैंरो प्रसाद मिश्र, अरविंद सावंत, राहुल शेवाले, श्रीरंग आप्पा बारणे और हिना विजयकुमार गावीत को श्री विनायक भाऊराव राऊत द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(1300/SR/PC)

SHRI RAHUL SHEWALE (MUMBAI SOUTH CENTRAL): Thank you Madam Speaker for allowing me to raise an important issue on fee hike for non-DAE students at BARC schools of my parliamentary constituency of South Central Mumbai. I have received several representations from many non-DAE parents whose children are studying in AEES school in BARC, Mumbai. Previously, the fee for boys was Rs.20,000 and Rs.2000 for girl students. Now the fee is instantly increased to Rs.40,000 for boys as well as for girl students.

It is learnt that recently the Union Minister of Finance had told the Department of Atomic Energy that the fees charged in AEES school were very low. So, the fees were hiked just double to the previous fee structure.

The Union Government is promoting education to all under the Right to Education Scheme. But, due to instant fee hike, how is it possible for poor students to afford the present fee structures at AEES schools? I would like to highlight some of the points raised by the parents of such students. The parents were not given any prior information about the fee hike. There is a Central Government scheme for girls' education which was operational till last year. Now,

they have been charged the same fees as is being charged for boys from this year. Those parents who have two children will have to pay twice or thrice the fees. The management is putting pressure on the students to pay their fees in the class room itself. Due to this, it is affecting the students mentally. Like the DAE staff, non-DAE people do not get any special grants for the education of their children. It is the responsibility of the BARC to provide education to the people staying in the nearby areas also.

I would request, through you, the hon. Minister of Atomic Energy to stop this fee hike immediately.

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री राहुल शेवाले द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र भागलपुर से गुज़रने वाले मात्र दो लेन की एन.एच. 80 की स्थिति कई वर्षों से दयनीय बनी हुई है। एन.एच. 80 की दुर्दशा पर तत्काल संज्ञान लेने की आवश्यकता है।

महोदया, यह भागलपुर की सब से बड़ी समस्या है। सड़क की बर्बाद स्थिति की वजह से भागलपुर में जाम की समस्या नासूर बन गई है। खासकर, शहर से लेकर कहलगांव, पूरी तरह इसकी चपेट में है। सड़कों पर ट्रकों का आतंक मचा हुआ है। प्रतिदिन लगातार लगभग पांच हजार ट्रक्स स्टोन चिप्स लेकर जाते हैं, जिसने लोगों

को तबाह और बर्बाद कर के रखा हुआ है। इस कारण सड़क पूरी तरह जाम रहती है। आज भागलपुर पूरी तरह जाम की चपेट में है।

महोदया, इस मामले को एन.डी.टी.वी. प्राइम टाइम में दिखाया गया था। विभिन्न संगठनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किए गए। लेकिन इसके बावजूद भी जब सुधार नहीं हुआ, तो मैंने 24 किलोमीटर पैदल चलकर इसके बारे में शासन और प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन इसके बावूजद भी आज तक पूरा शहर जाम की स्थिति में है। वह सड़क लगभग चार-चार दिनों तक जाम में रहती है। निशिकान्त भाई साहब यहां पर हैं। इनकी माता जी जब बीमार पड़ गईं, तो ये चार घंटे के बाद डॉक्टर के यहां भागलपुर पहुंच पाए।

महोदया, मैं आपके माध्यम से एन.एच. 80 की दुर्दशा के बारे में पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा। मैं चाहूंगा कि सब से पहले दो लेन की यह जो सड़क है, इसको बढ़िया तरीके से जाम से मुक्ति दिलाई जाए और मुंगेर से लेकर मिर्ज़ा चौकी तक इसे फोर लेन की सड़क बनवाने का काम किया जाए। यह सड़क बहुत बुरी स्थिति में है। यह नासूर बन गई है।

महोदया, एन.एच. 106 पर भी 36 किलोमीटर की प्रॉब्लम फंसी हुई है। मैं उसकी ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री निशिकान्त दुबे, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री शरद त्रिपाठी, एवं डॉ. कुलमणि सामल को श्री शैलेश कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI S.R. VIJAYA KUMAR (CHENNAI CENTRAL): Thank you hon. Speaker Madam. The proposed draft Dam Safety Bill contains clauses which violate the rights of Tamil Nadu especially with respect to the dams constructed and owned by the Government of Tamil Nadu in the neighbouring States. It would cause various problems in its maintenance and operation.

(1305/UB/BKS)

Tamil Nadu Assembly adopted a special Resolution demanding that the Centre keep the Dam Safety Bill in abeyance. The Resolution mentioned that the Bill contains clauses that violate the rights of Tamil Nadu with respect to the dams and would cause problems in the operation and maintenance of the dams which are owned by Tamil Nadu but built in other States. The Central Government must act to resolve the issues before it passes the Bill.

When the Centre had sought inputs from the States in 2016, our beloved Leader, Puratchi Thalaivi, Amma, raised some questions about the clause allowing the National Dams Safety Authority to inspect dams situated across intra-state rivers. The hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Shri Edappadi Palaniswami, had

written to the hon. Prime Minister on 15th June, 2018 saying that the Bill was against the interests of the State.

Tamil owns dams in Mullaperiyar, Parambikulam, Thunakadavu and Peruvaripallam in Kerala. The two States have engaged in dispute over the Mullaperiyar Dam. When Tamil Nadu wanted to increase the storage of the Dam, Kerala opposed it citing safety threats. Eventually, a Supreme Court team inspected the Dam and confirmed in November 2014 that the Dam was safe.

The latest move by the Centre has made Tamil Nadu cautious about its authority and assets. Most dams in India are owned and operated by the State Governments. Maintenance is mostly done by the State Public Works Departments except in bigger dams that are managed by autonomous bodies. The Government of Tamil Nadu has demanded consultation with States before finalising the Bill.

Therefore, I urge the Central Government to take up the legislation on Dam Safety only after consulting the States and after arriving at a consensus and till then, keep in abeyance the process of legislation on Dam Safety.

HON. SPEAKER: Shri K. Ashok Kumar, Shrimati V. Sathyabama and Dr. J. Jayavardhan are permitted to associate with the issue raised by Shri S. R. Vijaya Kumar.

श्री कमल भान सिंह मराबी (सरगुजा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ी समस्या को लेकर मैं इस सदन में आया हूं। आपने मुझे सदन में इस समस्या पर बोलने के लिए जो समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सरगुजा एक अति पिछड़ा एवं आदिवासी बाहुल्य संसदीय क्षेत्र है, जहां खनिज सम्पदा की भरमार है। खनिजों के निकासी हेतु सरकार के द्वारा बहुत से कार्य कराए जा रहे हैं। यदि केवल कोयले की मात्रा पर ध्यान दिया जाए तो भारत में हमारे राज्य का 18 प्रतिशत कोयले का योगदान है। हमारे क्षेत्र में निरंतर हर वर्ष रेल यात्रियों की तादाद में वृद्धि हो रही है। मेरे क्षेत्रवासियों के लिए मैंने अम्बिकापुर से नई दिल्ली के लिए सीधी रेल सेवा प्रारम्भ करने हेतु कई बार आग्रह किया है। मेरे द्वारा पिछले दो वर्ष से लगातार रेल मंत्री जी एवं प्रधान मंत्री जी को पत्रों के माध्यम से इस बारे में अवगत भी कराया जा रहा है। रेल मंत्री जी मेरे इस आग्रह के संदर्भ में अम्बिकापुर से नई दिल्ली तक रेल नहीं चलाये जाने के कारण से अवगत कराने की कृपा करेंगे।

बजट सत्र 2015-16 में चिरिमिरी-बरवाडीह रेल लाइन के लिए राशि स्वीकृति होने के बाद भी रेल लाइन का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। मेरा आग्रह है कि सरकार द्वारा इस लाइन हेतु कब तक कार्य प्रारम्भ करने की योजना है, मैं इससे अवगत होना चाहता हूं।

मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि वहां से दिल्ली आने के लिए और कोई साधन नहीं है। यदि यहां से रेल चालू होती है तो यू.पी., बिहार और झारखंड तीनों राज्यों को विशेष रूप से फायदा होगा। अतः कृपया उपरोक्त कार्य को शीघ्र कराने का कष्ट करें। धन्यवाद।

HON. SPEAKER: Shri Sunil Kumar Singh is permitted to associate with the issue raised by Shri Kamal Bhan Singh Marabi.

SHRI BHEEMRAO B. PATIL (ZAHEERABAD): Madam, today, I would like to raise an issue regarding Eklavya Model Residential School in my Parliamentary Constituency, Zaheerabad in the State of Telangana.

The basic criteria, as per the guidelines of Tribal Affairs Ministry, Government of India, is: 50 per cent population or minimum 20,000 population in a block. In the States of Telangana and Andhra Pradesh, the blocks in the year 1982 were divided in two *Mandals* for administrative convenience. Almost seven to eight *Mandals* both in Telangana and Andhra Pradhesh constitute a block but proposals are still being rejected barely on the ground that the tribal population is below 20,000 in the *Mandals* in Telangana State.

(1310/KMR/GG)

I would also like to mention here that as per Census 2011, ST population in Narayankhed Block is 40,483, in Yellareddy it is 33,863, and in Banswada it is 27,599. All the above-mentioned blocks have more than 20,000 ST population. I request the hon. Minister for Tribal Affairs to change the word Block to Assembly segment, especially in the States of Telangana and Andhra Pradesh; and consider the proposals regarding opening up of Ekalavya Model Residential Schools.

*SHRI DHARAM VIRA GANDHI (PATIALA): Thank you, Hon. Madam Speaker, for giving me the opportunity to speak on an important subject pertaining to Punjab.

I want to draw the attention of the House towards NH64 that passes from Amritsar to Bathinda and from Chandigarh to Bathinda. No uniformity in technical parametres has been followed as far as construction of this road in concerned. One side of this road has been constructed by using cement, iron and concrete. However, the other side of the road has been constructed by using only coaltar.

---

*Original in Punjabi

Why both sides of this road were not constructed using the same materials is a million-dollar question. Whether it was the safety standard or the cost of construction that was responsible for it, same parametres should have been followed in the construction of the road.

Hon. Madam Speaker, this dubious decision has led to a compromise in the quality of the road. It also raises a question-mark as far as safety of travellers on this road is concerned. The people of Punjab have to pay toll-tax for utilizing the services of this road. So, they are entitled to standard and safe roads. However, in this case, safety has become a casualty. This is sheer injustice that has been meted out to the people of Punjab. When Punjabis are paying taxes to the Central Government, they are entitled to the best roads.

So, I urge upon the Central Government to rectify the error and do away with this anomaly in the road construction of NH 64. Safety of travellers must be kept in mind while constructing roads. It is the responsibility of the Central Government. The burden of toll-taxes should also be done away with.

DR. J. JAYAVARDHAN (CHENNAI SOUTH): Madam Speaker, Chennai is already recognised as India’s leading audio, video

production centre with several postproduction processing activities like digital recording, mastering, dubbing and animation being undertaken for several films produced in our country. It is understood that the Central Government in collaboration with FICCI has sought to set up a National Centre for Visual Effects, Animation and Graphics in our country. Madam Speaker, in keeping with the developed countries where they have invested so much in regard to visual effects, animation and graphics, it is necessary that our country raises capital in this field, creates adequate workforce in this field, and also provide job opportunities for youngsters in this field. Therefore, I urge upon the Central Government to make sure that a National Centre for Visual Effects, Animation and Graphics is established in our great city Chennai. Thank you.

HON. SPEAKER: Shrimati V. Sathyabama, Shri P.R. Sundaram, and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Dr. J. Jayavardhan.

HON. SPEAKER: Now I will allow a few persons for one minute each.

Shri K. Suresh, we have a Discussion under 193 and you can speak then.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): I will be very brief, Madam.

Madam Speaker, living conditions of Dalit Christians are very poor in India. They live in large numbers in Southern States but they are not getting the benefit of reservation in government employment, educational institutions and in other government schemes. They are demanding reservation for SCs and STs but unfortunately they are not getting it. Therefore, I would like to request the Government to create a National Welfare Corporation for Dalit Christians. It is a very urgent matter because their living conditions are bad. Hon. Minister is sitting here. He may kindly respond because it is a very genuine matter.

SHRI K. N. RAMACHANDRAN (SRIPERUMBUDUR): A pathetic railway accident happened yesterday in my Constituency at St. Thomas Mount station. The accident was caused purely because of the mistake of railway technicians and officials. Poor people died in that accident, six people were injured, and two of them are in serious condition. The train going towards Tambaram was to come on Platform 2 of St. Thomas Mount Station in the normal course. All of a sudden, without intimation the train was diverted to Platform 4. If

the train had come on to Platform 2 as it usually does, this accident would not have happened.

(1315/GM-CS)

Human loss cannot be compensated. However, I request you to kindly make an inquiry into the matter and give a compensation of Rs. 30 lakh for lost lives and Rs. 5 lakh for injured persons.

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती) : महोदया, पिछले दो दिन से महाराष्ट्र में बहुत अव्यस्तता हो रही है। दो साल पहले महाराष्ट्र में मराठा आन्दोलन शुरू हुआ और उन्होंने बहुत सारे आन्दोलन किए, लेकिन वे आन्दोलन बहुत शान्तिपूर्वक हुए। सरकार से भी बात हुई और सरकार ने कमिटमेंट भी दिया था कि जल्द से जल्द मराठा समाज को हम आरक्षण देंगे। अभी दो दिन पहले काका साहब शिंदे ने जल समाधि ली और उसके बाद आज महाराष्ट्र के हर जिले में अव्यस्तता है। पुलिस और बच्चों में बड़ा कान्फ्रन्टेशन हो रहा है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करती हूँ कि सरकार महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री जी से बात करे। मराठा आरक्षण के दोनों शब्द धनगर, मराठा बीजेपी के मेनिफेस्टो में है कि वे इनको आरक्षण देंगे। बहुत अच्छी तरह से आज तक बातचीत हो रही थी, लेकिन दो-तीन दिन से लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा इश्यू हो चुका है। आज महाराष्ट्र में बंद है। नासिक, रायगढ़, ठाणे आदि सभी जगहों पर बंद पुकारा गया है, लेकिन यह बंद शान्तिपूर्वक हो रहा है। उन्होंने कहा है कि स्कूल, कॉलेजेज़, एम्बुलेंसेज़, अस्पताल अच्छी तरह से रहें। मराठा मोर्चा कोशिश कर रहा है कि कुछ बातचीत हो।

कोई जिम्मेदार व्यक्ति इनसे बातचीत करे। माननीय मुख्य मंत्री जी इनसे बात तो करें कि इश्यू क्या है? इश्यू सबको पता है। आज महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री और अन्य मंत्रियों के द्वारा गलत बातें मीडिया में आ रही हैं और उससे गलतफहमी बढ़ रही है। आज महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर का बहुत क्राइसिस चल रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इस मराठा और धनगर समाज को जो न्याय मिलना चाहिए, वह आप इन्हें दे दें।

श्री ओम बिरला (कोटा) : महोदया, बाड़मेर जिले के अंदर जनजाति के एक युवक खेताराम की एक समुदाय विशेष के द्वारा लाठियों से पीट-पीटकर नृशंस हत्या कर दी गई। सरकार कार्रवाई कर रही है। अलवर की घटना की भी सरकार ने न्यायिक जाँच आयोग बिठाकर जाँच की है। जिस तरह से कांग्रेस जाति और धर्म के आधार पर देश को बाँटना चाहती है, हमारा आपसे निवेदन है कि नृशंस हत्या बाड़मेर में भी हुई है, हत्या अलवर में भी हुई है, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से संवेदनहीन हो चुकी है, यह देश के हित में नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी, श्री सुमेधानन्द सरस्वती, श्री हरिओम सिंह राठौड़, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, डॉ. मनोज रजोरिया और श्री भैंरो प्रसाद मिश्र को श्री ओम बिरला जी के विषय के साथ समबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार) : महोदया, जगह-जगह पर यानी बंगाल में, केरल में, राजस्थान में जो ऐसी लिंचिंग और नरसंहार की घटनाएं हुई हैं, सामूहिक हत्या की घटनाएं हुई हैं, जो विषय किरीट सोमैया जी और

माननीय ओम बिरला जी ने उठाया है, इन सारे इश्यूज को मैं माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के संज्ञान में लेकर आऊँगा।…(व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): It is absolutely bogus, Mr. Minister.The Minister is actually misleading the House. Hon. Speaker Madam, don’t look to him; look to our side. ऐसा नहीं बोलना चाहिए।

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: He has not said anything. He will tell it to the Minister of Home Affairs; that is all.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Speaker Madam, in June this year, the Kerala Government found formaldehyde-contaminated fish being transported into the State. Soon after, a study revealed presence of around 5 to 20 times of the chemical in freshwater and marine fish in two of the cities of Chennai. Goa also reported similar findings and presence of around 5 to 20 ppm of chemical in freshwater and marine fish. However, Food and Drugs Administration of Goa later said that the level in Goan samples were on par with naturally occurring formaldehyde in marine fish. This triggered suspicion among consumers who accused the Government of playing down the health risk as the Food Safety and Standards Authority of India has already banned formaldehyde in

fresh fish. While the International Agency for Research on Cancer labelled the chemical a carcinogen in 2004, in Odisha also adequate steps have been taken because most of the coastal States are fish-eating States. But the fish that are being imported from Europe and other parts contain this chemical which is hazardous for health and leads to cancer.

(1320/RSG/RV)

There is an urgent need to address the concerns of consumers scientifically over formaldehyde contamination of fish. Therefore, I urge upon the Government to take immediate steps to draw a line between safe and unsafe consumption in a transparent manner with the help of experts.

HON. SPEAKER: Dr. P.K. Biju, Shrimati P.K. Shreemathi Teacher, Shri Shrirang Appa Barne, Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shri Sharad Tripathi are permitted to associate with the issue raised by Shri Bhartruhari Mahtab.

डॉ. करण सिंह यादव (अलवर): मैडम, मेरे लोक सभा क्षेत्र अलवर की तहसील बहरोड़ के लगभग तीन दर्जन गांवों में कपास व भिंडी की फसल पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है। दरअसल, बहरोड़ के पास सोतानाला व केशवाना औद्योगिक क्षेत्र में कुछ फैक्ट्रियां खर-पतवार को नष्ट करने वाली 2-4-डी नामक केमिकल मैन्यूफैक्चर करते

हैं। 2-4-डी बनाने वाली फैक्ट्रियों से ऐसी प्रदूषित वायु निकलती है कि आस-पास के गांव गूंती, काँकरछाजा, नालोता, शेरपुर, खेड़की, गोकुलपुर, तलवाड़, मोहम्मद, जागूवास, बहरोड़ समेत लगभग तीन दर्जन गांवों में कपास व भिंडी की फसल 100 प्रतिशत बर्बाद हो चुकी है। बहरोड़ तहसीलदार ने भी इसमें 70 प्रतिशत से अधिक की खराबी बताई है। वहां के किसानों ने कपास और भिंडी को उखाड़ कर वहां पर बाजरा बो दिया है। किसानों को भारी नुकसान हुआ है।

वन एवं पर्यावरण मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि 24-डी बनाने वाली जय अम्बे व धानुका फैक्ट्रियों को बंद करें। माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि इसका परीक्षण करवाकर किसानों को समुचित मुआवजा दी जाए। वहां के किसान बर्बाद हैं। वे बहुत भारी नुकसान में हैं। वे बहुत घाटे में हैं।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री धनंजय महाडीक (कोल्हापुर): अध्यक्ष महोदया, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

अध्यक्षा जी, पूरे देश में ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट का बंद चल रहा है। सभी कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां बंद हैं। उन्होंने बंद का एलान किया हुआ है। तकरीबन 90 लाख ट्रांसपोर्ट की कॉमर्शियल गाड़ियां बंद हैं। इससे आवागमन का कोई भी काम नहीं हो रहा है। सिर्फ अभी स्कूल बसों का काम चल रहा है।

अध्यक्षा जी, ट्रांसपोर्ट के बंद होने की वजह से जो रोज नुकसान हो रहा है, वह ट्रांसपोर्ट बिजनेस 4,000 करोड़ रुपये का हो रहा है। इंडस्ट्री की अपेक्स बॉडी ने यह घोषणा की है कि उनका 33,000 करोड़ रुपये का नुकसान रोज हो रहा है।

नो-कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने अपने इस ट्रांसपोर्ट लाइन को सराहा था। इससे बढ़त हो रही है, उन्होंने ऐसी घोषणा की थी। उनके हड़ताल का आज छठा दिन है। उनकी बस दो-तीन मांगें हैं। डीजल और फ्यूल के जो प्राइसेस बढ़ाए जाते हैं, वे तीन महीने में एक बार बढ़ाए जाएं क्योंकि छ: महीने में यह 12 बार बढ़ाई गयी है। टोल बैरियर-फ्री होना चाहिए। वे सब पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन टोल पर जाम लगा होता है। थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस, जिसे हर साल तीस प्रतिशत बढ़ाया जाता है, उसे रद्द किया जाए। इन्कम टैक्स सालाना एवरेज किया जाता है। इसे उनके काम के हिसाब से दिया जाए। आरटीओ और पुलिस से जो उन्हें परेशानी होती है, उससे उन्हें जो नुकसान होता है, उसे बंद किया जाए। ई-वे बिल का जो क्लैरिकल एरियर होता है, जिसकी वजह से लाखों रुपये का दंड दिया जाता है, उसे भी बंद कर दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया, यह बहुत गम्भीर मसला है। इसमें सरकार को तुरन्त हस्तक्षेप करने की जरूरत है।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे एवं श्रीमती सुप्रिया सुले को श्री धनंजय महाडीक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

The House stands adjourned to meet again at 2.25 p.m.
1323 hours

The Lok Sabha then adjourned till twenty-five minutes past Fourteen of the Clock.

(1425/RK/MY)
1425 hours

The Lok Sabha re-assembled at twenty-five minutes past Fourteen of the Clock.

(Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): I would request the hon. Deputy Speaker, Sir, that instead of taking up the Bills, as agreed to by all Parties in the House, the House may take up Discussion under Rule 193 on recent flood and drought situation in the country listed at Item No.33.

HON. DEPUTY SPEAKER: If the House agrees, we can take up Discussion under Rule 193.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, it was discussed in the Business Advisory Committee and actually I moved a notice on this. My constituency, Alappuzha is badly affected.… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: We are taking up the discussion.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): I would, therefore, say that I should be given a chance to initiate the discussion.… (*Interruptions*)

I have requested the hon. Minister, Shri Ananthkumar also as my constituency is badly affected.

HON. DEPUTY SPEAKER: I can understand that. I will give more time to discuss that matter. Let me go as per the list of the speakers. In whosoever name the discussion has been admitted may be allowed to initiate the discussion. I will give you sufficient time to speak.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Actually, the whole of the district has been devastated.… (*Interruptions*)

1427 hours

MATTERS UNDER RULE 377 – LAID

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, the matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which the text of the matter has been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

Re: Need to start helicopter service from Jabalpur, Madhya Pradesh to various tourist places in the State

श्री राकेश सिंह (जबलपुर):

Re: Need to withdraw draft notification declaring Palamu Tiger Reserve in Jharkhand as a Eco-Sensitive Zone

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा):

Re: Need to address water-shortage problem in Bundelkhand region

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर):

Re: Need to set up a head post office in Sheohar district, Bihar

श्रीमती रमा देवी (शिवहर):

Re: Need to open branches of nationalized banks in rural areas

श्री लक्ष्मी नारायण यादव (सागर):

Re: Need to provide stoppage of Shakti Punj Express and Triveni Express at Meral Railway station, Garhwa district, Jharkhand

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू):

Re:Need to establish Agriculture College in Rajgarh district, Madhya Pradesh

श्री रोड़मल नागर (राजगढ़):

Re:Need to rollback the increase in school fee for students of non-employee category in Kendriya Vidyalaya run by Atomic Energy Education Society in Jadugoda, Jharkhand

श्री विद्युत वरण महतो (जमशेदपुर):

Re: Need to upgrade the post office in Maharajganj district headquarters, Uttar Pradesh as Head Post Office and also set up a Post Office Passport Seva Kendra there

श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज):

Re: Need to declare Rohtasgarh Fort in Bihar as a tourist place of national importance

श्री छेदी पासवान (सासाराम):

Re: Need to set up an agriculture based industry in B*hupalsagar, Chittorgarh* district in Rajasthan

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़):

Re: Need to run a local train from Chhatrapati Shivaji Terminus Railway station to Bhiwandi Road Railway Station in Mumbai

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी):

Re: Regarding including villages under Municipal body to ensure their better management

श्री राजीव सातव (हिंगोली):

Re: Peace talk with NSCN-IM

DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): Even after almost three years of Government of India and NSCN-IM signing a Framework Agreement nobody knows its content. Hon'ble Prime Minister declared in an election meeting at Langjing that the territory of Manipur is not at all mentioned in this agreement Muivah says that the agreement contains the integration of the Naga inhabited areas of Manipur, Assam and Arunachal Pradesh. Now Interlocutor RN Ravi talks of Autonomous Naga Territorial Councils in Manipur and Arunachal Pradesh and also of a Pan Naga Cultural Body. These are absolutely unacceptable to the people of Manipur. Prime Minister's Version about the Agreement is contradictory to those of Muivah and Ravi. People are very anxious about the contents of the agreement. I demand and urge upon Hon. Prime Minister to make a statement on the status of Government of India and peach talk in order to clarify the position in the ongoing Lok Sabha Monsoon Session.

(ends)

Re: Crash in Cocoon prices

SHRI D.K. SURESH (BANGALORE RURAL): Sericulture is a main source of income for lakhs of farmers in the state of Karnataka. Sericulture farmers have been facing problems due to the crash in Cocoon prices triggered by the Centre slashing import duty on raw silk. Large number of farmers committed suicide in recent months. The Govt had earned sufficient revenue by exporting silk goods particularly from Karnataka in recent years. The cross breed (CB) cocoon, which was selling at Rs 400 per kg till April, is finding no takers even at Rs 210 per kg. The prices of bivoltine cocoon too has dipped from Rs 600 to Rs 320 per kg over a couple of months .

It is the duty of the Government to help farmers in the times of distress. Therefore, I urge upon the Government to declare a suitable MSP for Cocoon at the earliest to help the farmers.

(ends)

Re: Need to resolve problematic provisions in the proposed National Medical Commission Bill.

SHRIMATI R. VANAROJA (TIRUVANNAMALAI): Medical education is at the core of the access to quality healthcare in any country. The Hon'ble Supreme Court in its judgment dated 2nd May, 2016 had directed the Government to consider and take appropriate action on the recommendations of the Rai Choudhary Committee. Accordingly, it is proposed to introduce the National Medical Commission Bill with certain amendments to the draft bill.

Sir, Government doctors in the country, Tamil Nadu in particular are opposing certain clauses in the proposed bill and showed their opposition through protest against the National Medical Commission Bill.

The Government has incorporated the spirit of the Standing Committee report on Medical Council of India, but there are far too "many problematic" provisions in the proposed bill which "go against" the committee report.

The Indian Medical Association is against the provision that allows alternative medicine practitioners take up modern medicine after attending a short course and feels that the Bridge course provision in National Medical Commission Bill will 'sanction quackery'. This provision is totally

unacceptable as it will lead to an army of half-baked doctors in the country. Almost 2.7 lakh Indian doctors had protested across the country and are against this provision of the proposed bill.

Therefore, I urge upon the Union Government to desist from including such problematic provisions in the proposed National Medical Commission Bill.

(ends)

Re: Curtailment of frequency of Rajdhani Express from Bhubaneswar to Delhi.

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): From 10th February 2018, the frequency of Rajdhani Express from Bhubaneswar to Delhi via my constituency Balasore has been reduced due to introduction of a new service of Rajdhani Express via Sambalpur City. The frequency of Rajdhani to Delhi running via Bhadrak and Adra, has been brought down to twice in a week, from the earlier 3 times. Although it is commendable that the railways is heeding to long standing demands of a Sambalpur line, this move has deprived thousands of passengers of my constituency from accessing railway services. With 3 days a week service, there was intense scramble for tickets, and it was difficult for the common man to get a reserved seat. Now with reduced operations, it will further deteriorate the situation. I urge the minister to consider genuine demands of Odisha regarding connectivity to main metro cities of India.

(ends)

Re: Acquisition of land under the Maharashtra Private Forest (Acquisition) Act, 1975.

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): Around 2,58,797 hectares of land has been acquired under the 'The Maharashtra Private Forest (Acquisition) Act, 1975'. As per section 22(A) of the Act, the whole or part of the land can be restored to the original owner, if due to the acquisition under the Act, his land holding has become less than 12 hectares, 87,006.74 ha. land have thus been restored. In the Bombay Govt. Notification (29.03.1956), notices under sec 35 (3) and/or notification under sec 35(1) of Indian Forest Act, 1927 were issued by Maharashtra government almost 60 years ago but the land was never taken over. Now, these areas have been recorded as forest and all activities stopped. Lakhs of residents are living under constant fear. Therefore, I request to resolve the matter expeditiously, considering the future of lakhs of residents from Mumbai, Thane, Raigad and Pune.

(ends)

Re: Spread of fake news/messages on social media.

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Owing to false rumours on social media about child-lifters and thieves, persons were lynched by mob in Maharashtra in June-July, 2018. In a recent incident in Dhule district of Maharashtra, five persons from nomadic community who had gone to ask for food, were beaten to death on suspicion of being child-lifters. Such incidents of mob lynching are rampant across the country. In such cases of fake news proliferation, I request the Government to respond immediately and clarify the truth to its citizens. As a preventive measure, I also urge the Government to immediately undertake measures to curb rapid spread of fake news/ messages on social media.

(ends)

Re: Need to include 'Thathera' caste of Bihar in the list of most backward Classes

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा):

Re: Need to provide special incentives and package to Punjab

SHRI PREM SINGH CHANDUMAJRA (ANANDPUR SAHIB): Sometime ago, Government of India had announced special incentives for investment in Hilly States and Backward States. Such a decision badly affected Punjab due to neighbouring Hilly State. Punjab faces same problems due to border area and many parts of Punjab specially my constituency, a semi-hilly area called Kandi area faces same problems as that of hilly area.

I would urge upon the attention of Government of India to provide same incentives to such areas of Punjab State and Punjab being border state special package should be announced for it. Plain parts of hilly areas face the menace of damaging standing crops. Hence, there should be subsidy for fencing the fields. Such subsidy can be shared by the Centre, State and the farmers in a proportionate manner.

(ends)

Re: The safety of Mullperiyar Dam in Kerala

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): The Mullaperiyar dam is situated in a seismic prone area as pointed out by various agencies including IIT Roorkee. The Government should consider the agonies of the people living downstream of the dam due to the socio economic and psychological trauma arising out of unsafe the Darn being unsafe due to its age and the century back technology used for constructing the same. Now due to heavy rain in the catchmcnt area of the dam, the water level is increasing day by day and the people living in the downstream of the dam are in trouble, if any disaster happens it will be one of the biggest calamities in the world. So I urge for urgent intervention by the Government in this regard.

(ends)

Re: Need to provide reservation to Maratha community of Maharashtra

श्री राजू शेट्टी (हातकणंगले):

DISCUSSION RE: FLOOD AND DROUGHT SITUATION IN VARIOUS PARTS OF THE COUNTRY

1428 hours

HON. DEPUTY SPEAKER: The House shall now take up Item No.33

Hon. Members, discussion on the recent flood and drought situation in various parts of the country has been admitted in the names of Shri Jitendra Chaudhury and Shri Kalikesh Narayan Singh Deo. Shri Chaudhury has since requested the hon. Speaker to allow Shri P. Karunakaran to raise the discussion on his behalf. Hon. Speaker has acceded to his request.

Now, Shri P. Karunakaran.

(1430/PS/CP)

1430 hours

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Thank you, hon. Deputy Speaker, Sir.

With deep sorrow and pain, I would like to participate in a discussion under Rule 193, that is, ‘Flood Situation in Various Parts of the Country’.

Sir, at the very outset, I would pay my homage to the innocent people who have lost their lives due to flood and heavy rainfall throughout the country. The flood has affected mainly Kerala. Other States including Maharashtra, Assam and some parts of Tamil Nadu are also affected by flood. But, I would like to confine to my State only because other Members may raise issues pertaining to their States. I would like to thank our hon. Minister of State in the Ministry of Home Affairs, Shri Kiren Rijiju. He has visited the place; has witnessed the issues being faced by the State and by the people; and has also taken up the issue. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: No comments please. Please continue.

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, we have witnessed an immense calamity. Maybe this is a rare occasion in Kerala. This time,

the monsoon season started off with an unimaginable and uncountable loss to the various sections. Though there is a widespread effect on the State, we have witnessed severe damage in two districts namely, Alleppey and Kottayam. Other districts are also severely affected. I would like to thank Shri Venugopal and others who had visited the place. I think that he may narrate other issues.

Sir, the monsoon forecast stated that the rainfall is likely to be 97 per cent for the long period. The forecast also suggests that the maximum probability of the normal monsoon rainfall would be from 96 per cent to 104 per cent, that is, a long period average. Sir, since Alleppey and Kottayam have peculiar geographical features and are surrounded by sea and rivers, the land level is really below the water level in many places. So, any change in the monsoon may adversely affect these two districts. It is the peculiarity or the speciality.

Sir, the intense rainfall has caused a significant damage to life and property. The State Government has given a detailed report with regard to the loss caused by flood to various sections.

Sir, a large area of the district has been flooded due to heavy rainfall. In Alleppey district, around 21,799 acres of the land is under

flood; around 12,301 acres of the land is under flood in Kottayam district; around 13,688 acres of the land is under flood in Thrissur; around 2,056 acres of the land is under flood in Ernakulam; around 2,322 acres of the land is under flood in Pathanamthitta; around 1,338 acres of the land is under flood Malappuram; and around 1,503 acres of the land is under flood in Vallam. A total of 55,700 acres of the land is under flood in the district. Imagine, if such a huge land is under flood and rain, what would be the damage that the State has to face?

Sir, eight districts of the total 37 locations were affected by landslides. 14 lives were lost in landslides. That has happened especially in the hilly areas of Idukki district. Sir, out of 1033 villages, 965 villages have been affected, either by flood, landslides, rainfall or by wind. The heavy rains and the floods have been causing a very serious impact from 29.05.2018 to 24.07.2018. The data of 24.07.2018 shows that about 119 persons have lost their lives.

Hon. Deputy Speaker, Sir, the total crop loss is around 21,197.76 (in hectares). A large number of houses were damaged. Over 413 houses have been fully damaged and around 11,403 houses have been partially damaged. There are about 323 relief

camps set up by the Government. Sir, in Alappuzha and Kuttanad, about 50,000 animals are in various relief camps. The total estimated damage caused is about Rs. 1,384 crore. According to the report that we have got, though it is stated that 119 people have lost their lives, the number may be increased because of the rainfall, which is still continuing.

(1435/RC/NK)

As regards houses, a large number of houses were completely and severely damaged. There are about 389 houses which are fully damaged and 1040 houses were partially damaged. The total loss comes to about Rs.5511.771 lakhs.

With regard to fisheries sector, as far as Alappuzha and Kottayam are concerned, there are a large number of fish workers who live there. Due to the cyclonic storms, wind and rainfall have caused huge damage to the fisheries sector of the State. There are about 50 boats which are fully damaged; 47 boats partially damaged; 83 nets are fully damaged; and 61 nets are partially damaged. The total loss comes to about Rs.14.146 lakh. About 2600 acres of fish farms have been fully lost.

Sir, as you know, agriculture is the main source of income and especially the people of Kerala depend on agriculture. Agriculture is the main source of livelihood for the State, in general, and especially for these two districts.

Heavy rainfall, floods and cyclonic thunderstorms have caused severe damage to the crops in the affected areas of the State. Around 33 per cent crop loss is there over an area of 21704.78 hectares. You can think about the magnitude of loss. The cost of this loss, as per the norms, comes to about Rs.22073.67 lakh. We have to spend a lot of amount for bund and sand protection.

With regard to animal husbandry, intense rainfall and wind have caused severe damage to the animal husbandry and dairy development sector of the State. There are 173.3 lakh animal and poultry casualties. The total damaged cattle sheds are 16.87 lakh. The cost of provision for feed and concentrate comes to about Rs.30.63 lakh and for water supply, it comes to about Rs.0.022 lakh. In this sector alone, the total comes to about Rs.22.07 lakh.

As regards infrastructure facilities, they are completely damaged in both the districts as also in many other parts of Idukki, Mallapuram, Kozhikode, and Thrissur. Due to heavy rains, the

infrastructure facilities like roads, irrigation canals, water supply channels, open wells, electrical posts, telephone posts, etc. are totally damaged. There is a big financial burden for repairing and reconstruction of these infrastructural facilities in the affected areas of the State.

There are about 2000 major irrigation sectors which are in danger and the repairing cost would be Rs.2487.30 crore. Water supply infrastructure has also been widely affected. The repairing and construction cost would be around Rs.4834.99 lakhs. With regard to the power sector, it is widely affected. The repairing and construction cost would be Rs.2573.88 lakhs.

People are unable to use the roads because they are damaged fully. It is not possible for the people to go from one place to another. The Minister is well aware of that. He has visited the Kuttanad and Alleppey. He has seen all these things. So, without our explanation, the hon. Minister can give full details to the Government with regard to the damage. Around 196.689 kilometres of road have been lost in PWD section alone. The loss comes to about Rs.19668.96 lakh for the PWD roads which we have lost. The same is the case in

almost all the sectors like infrastructure facilities, roads, canals, electrical polls and hospitals.

I do not want to go into other details. Fourteen Anganwadi buildings are fully damaged; 27 Primary Health Centres – fully damaged; 69 panchayat buildings – fully damaged; and about 4017 kilometres of panchayat roads have been lost. It is estimated that Rs.24.10 crore would be total cost on this sector alone.

(1440/SNB/SK)

Sir, I would now turn to the issues of my State. Our State is facing some of the most serious issues. It is true that the State and the Central Government have to come together to deal with these issues. The State Government of Kerala has implemented the highest rate of relief assistance in India. But the Government of India is not ready to go beyond the laid down norms under the NDRF. So, the State is not getting the actual amount of compensation when it is faced with natural disasters of such magnitude. The State Government has to bear a huge financial burden for providing relief to disaster victims. The Government has to set up a National Disaster Mitigation Fund, but I think, the Government of India has not taken any initiative in this regard so far. I do not know whether such a Fund

at the Central level exists or not. But the State Government of Kerala has already set up such a Fund and is utilising it effectively. I would like to request the Central Government to take the initiative to set up such a Fund.

The Government of Kerala has requested for a comprehensive special package of Rs. 7340. 40 crore for the victims of the Ockhi cyclone. This request was made four months ago keeping in view the magnitude of the Ockhi disaster but the State got a very meagre amount and the State had to bear the maximum financial burden.

There was a suggestion from Shri Swaminathan for a special package to Kuttanad. This district falls under the Parliamentary constituency of Shri Suresh and he will speak about it. We have been talking about the Swaminathan Commission since the first session of this Lok Sabha. There was a mention of a special package for Alleppy, particularly Kuttanad district in the recommendations of the Swaminathan Commission. That recommendation has only partially been implemented.

At times of such natural calamities, the Army and the Air Force has a vital role to play. But in the State of Kerala the Army unit does not possess sufficient number of boats for rescue of the affected

persons during flood situation. This is a very serious issue. It is not an isolated case of this time alone because monsoon in Kerala may come at any time. So, the role of the Army and other agencies are very important. Though there is an Army unit, yet they do not have sufficient number of boats and no proper mechanism in place to provide effective relief to the flood affected people. This has become a major issue. Indian Air Force does not have heavy lifting aircrafts. How is it possible then for the Air Force to carry out effective relief work if they are not equipped with modern equipment for relief operations?

The functioning of the Indian Meteorological Department is not at all satisfactory. It is this Department which is entrusted with the task of giving warning of an impending calamity. But on a closer scrutiny of its functioning it was found to be totally unsatisfactory. The Government has to take note of this issue also. The Cyclone Warning Dissemination System is not functioning in the State. Even at the time of Ockhi it was not functioning properly. This is not the time to blame the Central Government or the Opposition, but at the same time we have to take stock of the things and find out as to what are

our deficiencies, what more we have to do to tackle such a situation when it comes in the future.

Sir, the State Government has made some demands from the Central Government. It has already given representation to the Centre. An all-Party delegation met the hon. Prime Minister to discuss various issues of the State in connection with this. Concrete proposals to deal with natural calamities were submitted to the hon. Prime Minister for implementation.

Sir, when we met the hon. Prime Minister we submitted seven demands. Myself, Shri E.T. Mohammad Bashir and Shri N. K. Premachandran were members of that delegation. Though we placed our demand before the hon. Prime Minister, I am sorry to say that we did not get any positive reply from him. Not only that, when the Chief Minister of the State and others had come at a time when the State faced another disaster, we reiterated those demands also but hon. Prime Minister did not give any response. We told him that a special team has to be sent to visit the State.

(1445/RU/RPS)

But when we went there, we got a reply from the other Minister. I am glad that you have given a reply. At the same time, the Chief

Minister of the State, other Ministers, Members from all Parties including Shri Radhakrishnan who is the State BJP President came together considering the seriousness of the issue but I am sorry to say that the approach of the Prime Minister was not at all satisfactory and it was a negative approach. … (*Interruptions*)

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Sir, it is not fair to say like this about the hon. Prime Minister…. (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Karunakaran, you may continue your speech.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Sir, since he has taken the name of hon. Prime Minister, I would like to say that after the all-Party delegation met the hon. Prime Minister, he had instructed me to visit the affected areas in Kerala. We, including the PWD Minister, the Minister for Agriculture, the Chief Secretary and the Additional Chief Secretary of the Government of Kerala and some Members of Parliament, had a combined visit. So, the hon. Prime Minister has taken up the issue

so seriously and had instructed me clearly to do whatever is possible from the Central Government side. What else do you want?

Regarding the rest of your points, I will reply later on… (*Interruptions*)

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, I appreciate your visit there. What I say is that, when the all-Party delegation had come there and when we explained the seven points – I do not want to go into those details as a copy is with you – my impression and the impression of the BJP leader was that there was no positive reply. That is only what I said. I appreciate that you have visited the area and the initiative which you have taken.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): We went there only on the instruction of the hon. Prime Minister.

… (*Interruptions*)

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): You saw that the Chief Minister and other Ministers were there. At the same time, we requested you to please send a team there … (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, if he is yielding, we met the hon. Prime Minister.… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: You may speak when your turn comes. Nothing will go on record.

… (*Interruptions*)… *(Not recorded)*

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, if he may yield for half a minute, I would say that here is a Prime Minister who means action. He sends the team. Do they want action or assurance? I fail to understand this point. If the PM takes action, they have a problem with it. This is not fair. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: You may speak during your turn. The hon. Minister can intervene at any time. Shri Karunakaran, you may continue now.

… (*Interruptions*)

कृषि और किसान कल्याण मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह): सर, वे स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के निर्देश के बाद ही गृह राज्य मंत्री जी वहां गए थे। फिर आप गृह राज्य मंत्री जी को बधाई भी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को बधाई दीजिए कि उनसे आप मिले, उसके बाद ही उन्होंने मंत्री जी को वहां भेजा। प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर ही गृह राज्य मंत्री जी वहां गए थे।…(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: There are many hon. Members who are yet to speak on the subject. So, try to wind up up now, Shri Karunakaran.

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): I can respond to the points which you have raised but I do not want to take the time of the House for this purpose.

At present, the State Government has already given a representation to the Centre and all-Party delegation has met the Prime Minister. In connection with the natural calamities, we are placing some of the most important demands before you.

(1450/KSP/ASA)

I hope the Government would take it very seriously. First of all, our demand is that this situation should be declared as a calamity of severe nature and the Government of India should consider the Memorandum submitted by the Government of Kerala. If the Government is going to treat it as a routine matter, we are not going to get enough fund for relief. So, this has to be declared as a natural calamity of severe nature.

HON. DEPUTY SPEAKER: Please conclude.

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, this is a very important matter. Ministers and others have taken my time. So, kindly give me some more time. I will conclude quickly.

Sir, considering the fact that it is the second consecutive disaster in continuous seasons - first Ockhi cyclone and now floods during the Monsoon – the Government of India should permit Kerala to exercise the provision of second consecutive disaster where the relief assistance can be increased. This is because within six months, we faced two natural disasters namely, Ockhi cyclone and now flood during the Monsoon. There is a provision that the Government can increase the amount of compensation. So, that should be done.

Thirdly, the Government of India should take immediate action for effective use of the National Mitigation Fund. As far as Ockhi cyclone relief is concerned, we gave a representation asking for the Central assistance of Rs. 7,340 crore, but we got only Rs. 4,000 crore. So, how is it possible for the State Government to meet all the expenditure relating to relief? I am not blaming the Government. But I would request that the norms have to be changed. Otherwise, it is not possible to meet this expenditure. On the one side, Ockhi cyclone

have devastated our State and on the other side, floods have occurred during this year's Monsoon. In the morning, I raised the issue regarding Endosulphan. Then, in Kozhikode, we are facing the NIPHA virus issue. We are facing all these problems. So, the Government of India has to take all these things very seriously.

Fourthly, the Defence Service Corps in Kannur, the Army in Thiruvananthapuram and the ITBP in Alappuzha are to be provided with at least six Motor Boats each and other equipment, because of lack of enough Motor Boats is a major issue that they have to face when they go for rescue operations. Then, Indian Air Force may be directed to be stationed permanently at any of the districts which I have mentioned earlier. There is no such arrangement now. As a result, they have to approach Air Headquarters at Delhi and then only they can take up rescue operations.

There is no Flood Warning Centre in Kerala now. The Government of India should take immediate steps to set up a Flood Warning Centre in Kerala. The Government of Kerala has taken a number of steps. When the Government of Kerala got the warning, they have immediately alerted all the District Collectors and also, all the political representatives were engaged and consultations were

held with them. I appreciate the Minister for visiting the affected areas. When he came, the Agriculture Minister of Kerala and other Ministers were there. Now, one of the Cabinet Ministers of Kerala Shri V. Sudhakaran is staying in Kuttanad itself and supervising the relief operations. Though the flood situation has improved now, the aftermath of the situation is very severe. Even though the flood waters have receded, there are a number of issues which we have to face like issues of infrastructure, health problems, rehabilitation of houses etc. As I have already mentioned, a large number of houses have to be repaired.

Sir, I am not blaming anyone. But as far as Kerala is concerned, this is a very big burden that we have to bear. With very limited resources at our disposal, we are taking up relief measures on a massive scale. But it is not possible for our State to meet all these expenses. So, I request the Minister and also the Government of India to take it very seriously. They should not treat it as giving some assistance. What we need is, long-term measures especially in Kuttanad, Alleppey and Kottayam areas. In Idukki also, people are suffering because of landslides. Already 14 persons have lost their lives due to landslide there. Considering the geographical features of

these places, long-term measures should be taken up. In Kuttanad area, the land level is below the water level. So, any change that may happen during the Monsoon period, it may affect this area. Therefore, I think the Government should send a Special Team and discuss with the Government of Kerala. We are fully cooperating with the Government of India. This is not a question of politics. This is a question of the saving the life and property of the people of Alleppey and Kottayam. This is also a question of giving due importance to the State of Kerala.

With regard to Centre-State relations, I think the Government of India must take up this matter seriously and not mix up with other issues. With these words, I conclude. Thank you.

(ends)

(1455/RAJ/SRG)

1455 बजे

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने का मौका दिया। मैं अपने और बीएसी के सभी साथियों का आभारी हूं कि उन्होंने यह महत्वपूर्ण मुद्दा चर्चा के लिए लिया है। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। यह केवल सांस्कृतिक रूप से ही नहीं झलकता है, बल्कि इसकी अपनी भौगोलिक स्थिति है। अभी करुणाकरन जी बाढ़ की विभिषिकाओं के बारे में बोल रहे थे। मैं बिहार से चुन कर आया हूं। आज मेरे यहां पूरी तरह से सुखाड़ की स्थिति है। भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हमें कहीं बाढ़ तो कहीं सुखाड़ झेलने को मिलता है। आज भी मुझे याद है कि बचपन में किसान बोलते थे कि अगले हफ्ते बारिश होगी। मुझे यह सुन कर आश्चर्य होता था कि ये पढ़े-लिखे लोग नहीं है, फिर भी ये बारिश के बारे में कैसे बता सकते हैं। जब वे बोलते थे कि हथिया नक्षत्र में इतने दिन बारिश होगी तो ठीक उतने दिन तक बारिश होती थी। पहले किसानों को बिना किसी एक्यूवेदर और बिना किसी सेटेलाइट के यह पता होता था कि उन्हें कब खेतों में बीज डालना है, कब बीजड़ा होगा और कब बीजड़े की रोपनी करेंगे। आज पूरा समीकरण बदल गया है। इसके लिए कहीं न कहीं हम सभी दोषी हैं और पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है, उस पर भी हमें ख्याल रखने की जरूरत है। आज जब हम भारत में मानसून की बात करते हैं तो मानसून सामान्य है, लेकिन इसका वितरण इतना असामान्य है कि राजस्थान जैसी जगह पर बाढ़ की स्थिति हो गई है।

हिमालय की तराई के क्षेत्रों में आज भी दस फुट गडढ़ा खोदने पर पानी मिल जाता है, लेकिन उस जगह भी आज हम लोग सुखाड़ की स्थिति का सामना कर रहे हैं।

मैं पिछले चार वर्षों से देख रहा हूं कि हर बार मानसून सेशन में ही बाढ़-सुखाड़ पर चर्चा की जाती हैं। यह एक ऐसी स्थिति है कि जब हमें प्यास लगी तो हम गडढ़े खोदने जा रहे हैं। बाढ़-सुखाड़ पर शीतकालीन सत्र में एक सीरियस चर्चा होनी चाहिए कि हम अगले वर्ष बाढ़-सुखाड़ के लिए क्या-क्या तैयारी कर रहे हैं। हमारा काम कानून बनाना और पॉलिसी बनाना है। अभी बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति है तो हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई पॉलिसी नहीं बना सकते हैं।

मैं अपने माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, श्री नितिन गडकरी का आभारी हूं कि उन्होंने नदी के गाद से सड़क बनाने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना बनाई है। यह एक वाटर-शेड प्वाइंट हो सकता है। हिमालय की तराई वाले इलाके जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड हैं, वहां नदियों की गहराई कम होने के कारण, हमें हर वर्ष बाढ़ की बहुत ज्यादा विभिषिका देखने को मिलती है। इसका एक उदाहरण है। महाराष्ट्र में एक नदी मृत पड़ी थी। महाराष्ट्र सरकार ने और गडकरी जी के विभाग ने उस नदी को भी जीवित कर दिया और मुफ्त में सड़क के लिए मिट्टी की भी व्यवस्था हो गई। हम लोगों को पॉलिसी मेकिंग में इस तरह का काम करना पड़ेगा।

इसका एक दु:खद पहलू भी है – ग्रीन ट्रिब्यूनल और हमारे ब्यूरोक्रेट्स, जो कभी क्षेत्र में नहीं गए हैं, क्षेत्रों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन एनजीटी में ऐसे-ऐसे फैसले हो जाते हैं, जिन्हें हम लोग समझने में असमर्थ हो जाते हैं कि यह फैसला कैसे हुआ।

मैं इसके दो उदाहरण दूंगा। मैं पश्चिम चंपारण से चुन कर आया हूं। हमारे यहां वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। वह बहुत ही खूबसूरत जंगल है। हमारे यहां हिमालय से नदियां निकल कर आती थीं। उनके साथ जो पत्थर बह कर आते थे, उन सभी पत्थरों को हाथों से उठा कर ट्रकों में लादा जाता था और पूरे इलाके में गिट्टी सप्लाई का काम होता था। वहां कोई क्वैरी नहीं होती थी, कभी वहां जेसीबी नहीं जाती थी। हिमालय से जो पत्थर नदियों में बह कर आते थे, थारू आदिवासी हाथों से उठा कर पत्थर को गाड़ियों में रखते थे और उनको वे गिट्टी के रूप में उपयोग करते थे। अचानक वर्ष 2001 में एक रूल आ गया कि किसी टाइगर रिजर्व से कोई चीज नहीं उठाई जाएगी।

(1500/IND/KKD)

हर साल लाखों-करोड़ों टन पत्थर हिमालय से बह कर आता है और एनजीटी द्वारा उसे उठाने के लिए मना कर दिया गया। उसका नतीजा यह हुआ कि जिन नदियों में घुटने भर भी पानी नहीं रहता था, वहां सारा पत्थर भर गया और जब बाढ़ आई तो पूरा वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में मिल गया और हजारों एकड़ जंगल खत्म हो गया। जहां-जहां कम गहराई थी, वहां सारा पानी-पानी हो गया और एनजीटी ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया।

महोदय, यह सभी जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है। दिल्ली से एनजीटी देश के दूसरे भागों का फैसला कर देती है कि नागालैंड में क्या होगा, हिमाचल में क्या होगा, केरल में क्या होगा, लेकिन वे जमीनी स्तर पर नहीं सोचते हैं कि उस इलाके में क्या किया जाना चाहिए।

1502 बजे (श्री हुक्मदेव नारायण यादव पीठासीन हुए)

महोदय, मैं एक मामला बिहार का उठाना चाहता हूं। पिछले वर्ष बिहार में सबसे खराब बाढ़ हमने झेली है। हमारे यहां स्वतंत्रा सेनानी श्री शिवनाथ तिवारी जी थे, उनका स्वर्गवास हो गया है। उनकी 95 वर्ष की आयु थी। पिछले वर्ष बाढ़ के समय हम उनके घर पर बैठे थे। वे कह रहे थे कि हम लोगों ने जीवन में कभी इतनी बाढ़ नहीं देखी है और इसका एक बहुत बड़ा कारण नदियों में गाद भरना है। पिछली बार नीतिश कुमार जी ने दिल्ली में इस मुद्दे को प्रमुख तौर पर उठाया था और प्रधान मंत्री जी से मिले थे कि नदियों में गाद भरा हुआ है। फरक्का डैम के बारे में भी उन्होंने कहा था। एनजीटी ने कहा है कि 1 जुलाई से 1 अक्तूबर तक आप मिट्टी का एक कण भी नदियों से नहीं

निकाल सकते हैं। यदि वहां से प्रतिदिन दस हजार ट्रक बालू के निकलते थे, तो उसका फायदा होता था, वहां पानी के लिए जगह बन जाती थी। उत्तराखंड में जो बाढ़ आई है, उसका यही कारण है कि वहां नदियों में बहुत ज्यादा गाद है। हमारे यहां बारिश रिटर्निंग मानसून में होती है, इसलिए यहां हालत ज्यादा खराब होगी।

मैं करुणाकरण जी से कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी बहुत-बहुत संसिटिव हैं। मैंने स्वयं इस बात को देखा है। पिछले साल मैं लगातार एक महीने तक बाढ़ से ग्रसित इलाके में था। मैं वर्ष 1993 से बाढ़ को देख रहा हूं। मैं डाक्टर होने के नाते बाढ़ से प्रभावित इलाकों में जाता रहता था। मैंने पहली बार देखा कि 24 घंटों के अंदर हर जगह एनडीआरएफ की टीम पहुंच जाती है। कहां-कहां कौन फंसा है, कहां बोट्स ले जानी हैं, खाना कैसे पहुंचाना है, कितनी जल्दी काम हो रहा है, इसे मैंने स्वयं पिछली बार देखा है और इसके लिए मैं मोदी जी का आभारी हूं। आप फंड्स की बात कह रहे थे। आप याद रखिए कि यह राजीव गांधी जी का समय नहीं है, जहां एक रुपये में से केवल 16 पैसे ही लोगों तक पहुंचते थे। यह नरेन्द्र मोदी जी का समय है। हमारे यहां के लिए छह हजार रुपये दिल्ली से भेजे गए और छह हजार रुपये ही लगभग सवा लाख लोगों के बैंक एकाउंट में पहुंचे। ये नरेन्द्र मोदी जी का समय है। केंद्र सरकार की तरफ से बहुत अच्छी तरह मदद की जाती है। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की बात है। मेरे यहां जिन लोगों ने फसल बीमा योजना ली है, उन्हें बाढ़ में 48 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर मिले। यह इतनी ज्यादा रकम है कि बाढ़ की विभीषिका को किसान भूल गए। जिन किसानों ने इंश्योरेंस नहीं कराई थी, उन्हें भी 18000 रुपये प्रधान मंत्री जी द्वारा उनके खातों में दिए गए, यह नरेन्द्र मोदी जी की खासियत है। मैंने जीवन में पहली

बार देखा कि 24 घंटे के भीतर प्रधान मंत्री सड़क योजना की जितनी सड़कें थीं, वे सारी की सारी मोटरेबल हो गईं। मैं लोक सभा में जिम्मेदार सांसद होने के नाते यह बात कह रहा हूं और मेरे क्षेत्र के लोग भी यह सुन रहे होंगे। यह इस बात का सबूत है कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के काम करने का तरीका कितना बढ़िया है। पहले छह-छह महीने सड़कें टूटी रहती थीं, लेकिन आज 24 घंटे में टूटी सड़कों को मोटरेबल कर दिया है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आपके इलाके केरल, ओडिशा आदि राज्यों में बाढ़ आई है, वहां भी उनकी समस्याओं का त्वरित निदान होगा।

(1505/vb/rcp)

अभी हम लोग बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे हैं, हमारे यहाँ जमीन के नीचे 10 फीट पर पानी है। सुखाड़ का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम लोग हिन्दुस्तान के विभिन्न क्षेत्रों को उनकी दृष्टि से नहीं देखते हैं। बिहार सरकार ने बहुत अच्छा काम करते हुए डीज़ल पर 50 रुपये प्रति लीटर अनुदान राशि दी है। श्री नीतीश कुमार जी ने बिजली का शुल्क भी 96 पैसे से घटाकर 75 पैसे कर दिया है। लेकिन, ये सब तात्कालिक उपाय हैं।

जब हम लोग को-ऑपरेटिव फेड्रलिज्म की बात करते हैं, तो हमें एक देश के रूप में सोचना होगा। जैसे सोलर पम्प की बात करें, तो सभापति जी, आपके इलाके में या हमारे इलाके में, यह लगाया जाता है, तो 40 फीट पर ही पानी मिल जाता है। हमारे यहाँ सोलर पम्प का उपयोग जितनी अच्छी तरह से हो सकता है, उतनी अच्छी तरह से महाराष्ट्र में नहीं हो सकता है, मध्य प्रदेश में नहीं हो सकता है, जहाँ दो हजार फीट

पर पानी है। इसीलिए सरकार को जो पॉलिसी बनानी चाहिए, वह एरियावाइज़ बनानी चाहिए।

हमारे यहाँ जितनी सब्सिडी सोलर पम्प के लिए दी जाती है, उतनी ही सब्सिडी माइक्रो इरिगेशन के लिए भी दी जाती है। हमारे यहाँ पानी की कमी नहीं है, इसलिए वहाँ माइक्रो इरिगेशन की ज्यादा जरूरत नहीं है। माइक्रो इरिगेशन की जरूरत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में है। लेकिन, सब्सिडी एलॉटमेंट का ऐसा नियम है कि प्रत्येक जिले को सब्सिडी मिल जाती है। हमारे क्षेत्र में कोई व्यक्ति माइक्रो इरिगेशन क्यों करेगा?

यहाँ पर कृषि मंत्री जी भी मौजूद हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि जो पॉलिसी बने, उसमें रीजनवाइज़ एलॉटमेंट हो। कहाँ पर सोलर पम्प ज्यादा चाहिए, कहाँ पर नहरों का योगदान ज्यादा होना चाहिए, कहाँ पर माइक्रो इरिगेशन और माइनर इरिगेशन की जरूरत है, इस पर विचार करते हुए भारत के विभिन्न क्षेत्रों को उसी हिसाब से डिवाइड करना होगा। मोटे तौर पर, राज्यवार ऊपर से नीचे तक बांट दिया जाता है कि प्रत्येक राज्य को इतना परसेंट इस चीज के लिए देंगे, मुझे लगता है कि इसके लिए को-ऑपरेटिव फेड्रलिज्म पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

मैं अपनी बात को संक्षेप करते हुए कहना चाहूँगा कि नदियों की गहराई बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जो तैयारियाँ की हैं, उसके लिए मैं इस सदन के माध्यम से एनजीटी से अनुरोध करूँगा कि इन सब मामलों में उसे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

बिहार की नदियों को गाद की समस्या से मुक्ति दिलाने का एकमात्र उपाय है कि उनमें से बालू को निकाला जाए। आज बालू की कीमत गिट्टी से ज्यादा हो गयी है।

दक्षिण बिहार से गिट्टी लायी जा रही है। दक्षिण बिहार में मृत पहाड़ हैं, जिनके पत्थर की क्वालिटी समाप्त हो रही है। हिमालयी क्षेत्रों से लाखों टन पत्थर देश की विभिन्न नदियों द्वारा बहाकर लाए जा रहे हैं। हम उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ऐसा एनजीटी का कानून है। इसीलिए सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ कि वह इस समस्या के निदान के लिए एनजीटी से माँग करे।

नदियों से गाद निकालने से बहुत फायदा होगा। हमारे यहाँ उपजाऊ मिट्टी को काटकर उसका उपयोग किया जाता है, जिससे किसानों को तकलीफ होती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नेशनल पॉलिसी बनानी चाहिए। एक बार दिसम्बर के महीने में भी हम लोग इस बात पर चर्चा करें कि बाढ़ और सुखाड़ को आने से कैसे रोका जा सकता है। इसकी भी तैयारी होनी चाहिए।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय किरेन रिजिजू जी तथा एनडीआरएफ की पूरी टीम का बहुत ही आभारी हूँ। हम लोगों ने लगातार 35 दिनों तक बाढ़ की विभीषिका झेली है। पिछले साल सुबह नौ बजे से नौ बजे रात तक हम लोग अपने क्षेत्र के बाढ़-प्रभावित इलाके में रहते थे। जितना सहयोग श्री किरेन रिजिजू जी और एनडीआरएफ टीम का मिला है, शायद 10 परसेंट मदद भी इससे पहले नहीं मिली थी। इसलिए श्री करुणाकरन जी, आप आश्वस्त रहें, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपको पूरा न्याय मिलेगा।

आप मछली पालन की बात कर रहे थे। आज तक कभी भी मत्स्य पालन में इंश्योरेंस नहीं होता था। यह सरकार है, जिसने बैंकों को कहा कि किसानों के खेतों की तरह ही मत्स्य पालकों को भी इंश्योरेंस दिया जाए। ऐसा करने का काम किसी ने किया

है, तो वह श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने आपके इलाके के मत्स्य पालकों के लिए किया है।

(इति)

1509 hours

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Thank you, Chairman Sir, for giving me an opportunity to participate in a very important discussion on recent flood and drought situation in various parts of the country.

Last Thursday and day before yesterday, on both days, I raised the same issue before the House. I would like to sincerely thank the hon. MoS who visited Kerala. He has, I think, first-hand information about the entire calamity. First of all, I would like to pay homage to the 120 people who have lost their lives during this calamity.

(1510/SMN/PC)

Earlier also, four months back, we lost around 100 people. Some of them are still missing. They are alive or not is still a question. Within these four months, we have lost more than 250 people because of these calamities.

Chairman Sir, I would like to tell specifically about two people who are from Matrubhoomi news channel. Their names are Saji and Bipin. Those two people went to that area to report the calamity. Actually, they have gone there for adventurous reporting. While

going to that area, they lost their valuable lives. I want to place on record about their adventurous journalism. One of them was a journalist and the other person was a driver. The Government should take care of these persons' families also along with others.

Chairman Sir, here Karunakaran Ji mentioned about the calamity. It is in my constituency – Alappuzha. I am representing the Parliamentary constituency. My colleague Shri Kodikunnil Suresh is representing the Kuttanad constituency. Day before yesterday and yesterday, we visited the maximum number of camps and flooded areas. Day before yesterday, I was hospitalized because of food poisoning. But I got voluntarily discharged from the hospital. I came here to participate in this discussion. In my constituency, we cannot imagine their sorrows, we cannot imagine their agonies. When I visited the Kuttanad area, I saw many people residing on bund without any protection. How can they live there? I cannot describe it. That is the pathetic condition. The entire paddy fields have been damaged. There is no livelihood income. Even the fishermen are not in a position to go for fishing. They are all in a very difficult position. That is why, we are asking for a discussion. Something has to be given to them. I am not blaming any Government. The Government

should promise something to them but nothing is going to happen. Only a meagre amount is given to them.

Shri Karunakaran Ji told about the Ockhi cyclone. In my constituency, four people went for fishing. They have lost their boats and everything which are needed for fishing. Finally, they have come back by losing their boats and entire machinery meant for fishing. So far, nothing has been given to them. So many promises were made to Ockhi victims but so far there is no foolproof fulfilment. That is why, we are asking this. The Parliament should consider this very seriously and the Government should also consider this seriously. Kuttanad is the rice bowl of Kerala. This is a low level land. Whenever floods come, those people will be in the flood only. This is the unprecedented thing which has happened.

So, I am urging upon the Government to intervene in it in a faster way. Hon. MoS has come there. I appreciate him for that. But you have to send an official team now. By the time, the official team visits the flooded region, there will be no flood. They report that nothing has happened. That is why, I am asking the Government to constitute an official team immediately and send them to Kerala so as to have an estimate. Hectares of paddy fields and cash crops

were damaged due to the devastating floods and rains. The economic loss is yet to be estimated. There is a serious lack of proper medical facilities. Temporary arranged camps are unable to provide proper care, shelter and drinking water for the suffering people. I had visited some of the camps in my constituency and also in Kuttanad. The condition of the people is very pathetic. They are living in a temporary arranged high mounted places in the flooded area and not in shelters. They do not have safe drinking water. The schools are also in water. The students who are studying in the school are staying as refugees in the same school. That is what is happening there. The living condition of the people is beyond imagination. The flood and heavy rains have brought venomous snakes to the camps. That is very dangerous. All the dangerous snakes are coming into the camps.

(1515/MMN-GG)

The children and the senior citizens are suffering the worst. The people above 70 years of age are in a very, very difficult situation. The houses are under water. As you know, after a period of time, the flooded water will create a serious safety issue to the houses. All the houses are broken. Their walls are breaking.

The farmers are not only suffering from mental agony but also from financial losses. They have lost their crops. They are already suffering with heavy burden of debt and crop loss. The Government should consider it.

In addition to this, the poor fishermen are the worst affected. They have not recovered from the loss caused by Ockhi cyclone so far. The sea water has entered into their inhabitation and their inhabitations were lost. They are the people belonging to the socially and economically marginalised section. You know about the state of affairs of the fishermen community. Therefore, the fishermen also need special care and protection.

Then regarding CRZ norms, several times we asked the Government to change the CRZ norms. They are not in a position to alter their houses. The hon. Minister is there. I know he is taking interest in that. But it has to be decided early.

As you know, any kind of natural calamities will have a serious impact on a State like Kerala. Kerala is the third most densely populated in the country. It has got the third largest population. So, it has a high degree of vulnerability. Sir, 14.5 per cent of the State is flood-prone; 14.4 per cent of the State is landslide-prone; and 55.5

per cent of coastline is prone to coastal hazards. This is the geographical condition of our State.

This year the monsoon season started off with immense calamities. The Indian Meteorological Department declared the start of monsoon over Kerala on 29th May, 2018. Quantitatively, the monsoon seasonal rainfall is likely to be 97 per cent of the Long Period Average.

The National Remote Sensing Centre of ISRO has informed that 50,007 hectares of land area of Kerala has been affected by flood.

There is a district-wise data. In Alappuzha, the flood affected area is 21799 hectares; Ernakulam--2056 hectares; Kottayam—12301 hectares; Pathanamthitta—2322 hectares; Malappuram—1338 hectares; Kollam—1503 hectares; Thrissur--13688 hectares; and the total area affected badly has been 55007 hectares.

Sir, 14 lives were lost in landslides one month before. Over 965 villages out of 1033 villages have been affected by floods, landslides, extremely heavy rainfall or strong winds. Thus, Kerala is facing a historic calamity due to monsoon rainfall of 2018.

As I told you, 21,197 hectares of crop has been lost. Totally, 11,304 houses were damaged. Around 88,000 people are in the camps. The statistics are unable to express the sufferings and the sad plight of the common people living in the camps. I have already told you that along with Kodikunnil Suresh, MP, I had visited some flood-affected areas. Both in his constituency and also in my constituency, the people are lacking basic amenities in the camps. Due to the water logging situation there, they are even facing problems to cremate the dead bodies also. That is also a very important point.

The flooding has raised the groundwater level of the low-lying parts of Alappuzha and Kottayam making most of the toilets in the area non-usable. That is one dangerous issue. When flood will be over, the epidemic will come fast because the situation is like that.

Coming to the Central Government's approach, however, even after this very severe flood, and human casualties, the Central Government is unwilling to go beyond the laid down NDRF norms. You have given Rs.80 crore. That is under NDRF norms. Every State has the right to have funds under the NDRF norms. You have given Rs.80 crore. I am not criticizing that. But it should be beyond the

NDRF norms. Then only, Kerala will be benefitted. Otherwise, it will not benefit Kerala.

As per Section 47 of the Disaster Management Act, 2005, it is the obligation of the Central Government to create a National Disaster Mitigation Fund. While Kerala notified the Mitigation Fund and is utilizing it effectively, the Central Government is yet to notify the NDMF and provide funds to the Government of Kerala for undertaking long-term disaster mitigation works.

(1520/VR/CS)

I would also like to point out that after the Ockhi cyclone happened in Kerala, the Government of Kerala requested for a comprehensive package of Rs.7340 crore. This is what Shri P. Karunakaran has also mentioned. But what you have given is almost nothing. Fishermen are not getting anything. That needs to be taken care of by the Union Government.

Sir, the fund available in the State Disaster Response Fund (SDRF) is Rs.203 crore, which is very insufficient to meet the requirement of current crisis. I would also like to point out the details of funds demanded by the State Government and the total amount released by the Central Government so far. The State of Kerala has

received an amount of Rs. 203 crore from State Disaster Relief Fund (SDRF) and a meagre amount of Rs.80 crore from National Disaster Response Fund (NDRF), whereas the Government of Kerala has itself spent more than that. Therefore, there is an immediate need of a relief package from the Central Government. I hope that while replying the hon. Minister would give some clarification in this regard.

In Alappuzha and Kottayam districts, the severe flood has badly affected the life of the people of Kuttanad region. The Kuttanad region is situated below sea line and is highly vulnerable to floods. However, the well-known report of MS Swaminathan, which led to creation of Kuttanad Package received only partial assistance from the Government of India. The Government has stopped that assistance package. This is at a standstill now due to lack of assistance from the Central Government. Therefore, I request the Government to revamp this assistance package as early as possible.

Hon. Chairman, Sir, I fully support the view expressed by Shri P. Karunakaran that for disaster management and rescue missions our Army, Navy and Coast Guard should be equipped because we want to save the lives of common people. Therefore, these Forces should be well-equipped to deal with such situations.

Hon. Chairman, Sir, I had pointed out the problems and failures of weather forecasting in the context of Ockhi cyclone when it hit the State of Kerala last year. I raised this very issue in this august House. The accuracy of district-wise rainfall prediction of India Meteorological Department (IMD) is no where near to reality. The IMD operates with just 56 rain gauges. It hardly has about seven temperature measurement stations and only one solar radiation measurement station. No real time rainfall data is made available to the disaster management authorities.

The Cyclone Warning Dissemination System of IMD in the State is not operational even after Cyclone Ockhi tragedy. The Central Water Commission has not yet created even one flood warning centre in the State even though the State is prone to floods and rain-related calamities.

Therefore, hon. Chairman, Sir, I would request the hon. Prime Minister and the hon. Home Minister to declare the prevailing flood situation in Kerala as 'a calamity of severe nature'. I am totally supporting this point. I also request the hon. Minister of State for Home Affairs to consider the memorandum dated 21.5.2018

submitted by the Government of Kerala for an amount of Rs.831.1 crore favourably.

Considering the fact that it is the second consecutive disaster in consecutive seasons, Ockhi in November-December and monsoon calamity starting May 2018, the Government should permit Kerala to exercise the provisions of second consecutive disaster and to provide relief assistance accordingly. It can be raised at least marginally within the NDRF norms.

There is an immediate need to consider Rs.7340 crore Ockhi Package requested by the Government of Kerala and provide assistance under the major heads of assistance requested therein.

I would also demand to provide continued assistance to complete the implementation of the Swaminathan Commission Report in terms of Kuttanad Package as I have already mentioned that Kuttanad is the rice bowl of Kerala and if Kuttanad is in crisis, the entire State of Kerala will be in a very difficult situation.

As I have already requested that our Army, Navy and Coast Guard should be well equipped, I would also insist that Para Military Forces should also be equipped to deal with such situations. I also

request the Government to provide a heavy lift helicopter in Thiruvananthapuram for emergency use in the State.

Regarding strengthening of IMD and make the organization provide real time rainfall data and accurate predictions to the State, the organisation should ideally have at least 300 rain gauges in the State at the rate of one rain gauge per square kilometre.

I also request that IMD should post at least one meteorologist in each district of Kerala. Only then the services of the Department could be fruitful. I would also request the Government to immediately set up at least one automated weather station in each *taluk* for monitoring and issuing of accurate localised weather predictions.

Chairman, Sir, there is an urgency for immediately setting up of five Digital Cyclone Warning Dissemination Systems each in Thiruvananthapuram, Alappuzha, Ernakulam, Kozhikode and Kasaragod districts of Kerala.

(1525/SAN/RV)

Sir, I would also request the Central Government to order immediately the Central Water Commission to set up flood warning centres in Karamana, Killiyar, Manimala, Meenachil, Pamba, Bharathapuzha and Periyar rivers of the State.

In addition to this, the flooded regions are highly vulnerable to infection and other seasonal epidemics. The spread of Nipah virus, as Shri Karunakaranji told, also created a very alarming situation in Kerala. Therefore, there is a need to upgrade the virology institute. In my constituency, there is National Institute of Virology, Alappuzha. It should be equipped in a larger way. When Nipah virus broke out in the State, we found that there was lack of sufficient equipment in the laboratory to establish the disease. Therefore, there is a need to strengthen this virology institute. I would request the hon. Health Minister to take measures to improve facilities at the Virology Institute in Alappuzha Medical College.

In this context, I would request the Prime Minister to declare the flood and casualties caused by rain as a 'natural calamity' and take measures to declare an inclusive financial package beyond the norms. We need an inclusive financial package beyond the norms in this time of grief and agony.

I would also request the Government to adopt a comprehensive mechanism to estimate the financial loss in order to ensure adequate compensation to the State as early as possible because the people there are in a very critical and vulnerable condition. Therefore,

through this august House, I am requesting the hon. Minister and the Government to come forward with some concrete assistance proposals. Otherwise, if it is treated like Ockhi Cyclone, then there is no meaning for us of discussing this in the House.

With great pain and with folded hands, Hon. Chairperson, Sir, I am requesting the Minister and the Government to immediately provide some relief to Kerala and to take immediate steps to address such calamities in future.

Thank you.

(ends)

1527 hours

*SHRI C. MAHENDRAN (POLLACHI): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. I extend my respects and heartfelt regards to our beloved leader Puratchi Thalaivi Amma who have given me an identity and an address. I thank you for allowing me to take part in the discussion under Rule 193 on recent flood and drought situation in several parts of the country.

Farmers are the backbone of our country leading to its development. They have to be encouraged and their income has to be increased. There was an assurance in the current Budget about doubling the income of farmers. I wish that this assurance should be implemented by the Union Government in true spirit. The Union Government has decided that the Minimum Support Price (MSP) of a produce will be fixed at least 1.5 times of its production cost. It should be assured that this decision of the Union Government should be benefitting the farmers of the country. Tamil Nadu faces different climatic conditions. On one side, it is affected by severe drought and

---

* Original in Tamil

on the other hand it faces devastating floods. Be it any type of natural disaster, farmers are the affected lot. Union Government should devise better schemes for protecting and uplifting the lives of our farmers. During December 2015, Tamil Nadu faced unprecedented rains and floods, which was followed by hard hitting Cyclones like Vardah and Ockhi. The State of Tamil Nadu was completed devastated by these natural calamities. The State Government of Tamil Nadu sought a relief from the Union Government after these disasters had struck the State in a severe manner. Union Government had not only delayed the release of funds but only a meager amount was released to the State of Tamil Nadu as flood relief. The farmers of Tamil Nadu faced untold miseries and remained very much affected. Due to severe drought conditions that prevailed during the last two years in Tamil Nadu, all the 32 districts had been declared as drought affected. Out of the 16,682 revenue villages, 13,305 villages have been declared as drought-affected in the State. The State Government of Tamil Nadu had sought Rs39,565 Crore from the Union Government as drought relief. But as on date, not even a single rupee has been released as drought relief to the State. I therefore urge upon the Union Government to

immediately release the drought relief to Tamil Nadu on war-footing basis. I urge upon the Hon. Union Minister for Agriculture and Hon Union Minister for Finance to immediately release all the pending dues including the flood relief, drought relief etc., to the State of Tamil Nadu. In order to benefit the farmers of Tamil Nadu, this relief is very much needed. The farmers of Tamil Nadu remain continuously affected. They are unable to repay the loans that they have taken from banks. The loans taken by farmers should be waived off by the Union Government. Moreover, the children of farmers have also taken education loans from banks for continuing their studies. Such educational loans should also be waived off. It is apt to mention that some of the students coming from families of farmers also reside in urban areas. I urge upon the Union Government through Hon Chairman that all such loans should be waived off. I want to stress and explain that what are all the measures that are to be undertaken by the Union Government to mitigate the sorrows faced by the farming community, especially of Tamil Nadu. In the Kongu region of Tamil Nadu especially in my Pollachi parliamentary constituency, coconut farming is the primary occupation and source of income for farmers. Farmers are very much dependent on coconut farming for

their livelihood. It should be ensured that coconut farmers get proper Minimum Support Price for their produce. MSP should be fixed at the maximum and that is the long pending demand of the farmers of our Kongu region. Compared to Palmolein, Coconut oil is good for health. But there is a rumour and misconception that coconut oil is not good for health. The amount spent by the Union Government for importing Palmolein should be utilize in the promotion of coconut farming in the country. So that coconut production can be increased. Union Government should engage coconut farmers in increasing the coconut production. This can also lead to the well-being and prosperity of our coconut growing farmers. We can produce quality coconut oil in the country. Tamil Nadu remains the pioneering State in the production of coconut and milling copra. On behalf of the coconut growing farmers, I extend my heartfelt thanks to the Union Government for increasing the MSP per kilo of the Milling Copra from Rs 52.50 to Rs.75. My demand to the Union Government is that the MSP for Milling Copra should be increased to Rs.140 per kilo. Another long pending demand of my Pollachi parliamentary constituency is regarding the early completion of construction of Aanaimalaiar-Nallar dams. Kongu region of Tamil Nadu has been

very much affected by severe drought continuously for several years. A permanent solution to this pertinent issue is the early completion of construction of Aanaimalaiar and Nallar dams. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Shri Edappadi K. Palaniswami has set up an expert committee in this regard.

Sir, please allow me to speak for a minute, I have an important issue to be raised. An expert committee consisting of Officers has been constituted. This Committee will look into the ways and means of ensuring the early construction of Aanamalaiar and Nallar dams. I sincerely thank Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Shri Edappadi K. Palaniswami for this thoughtful decision. An amount of Rs.1500 Crore is required for implementation of this Scheme. I therefore urge upon the Union Government to immediately release an amount of Rs.1500 Crore without any further delay for early execution of construction of Aanamalaiar and Nallar dams. Since Tamil Nadu is severely affected by drought, linking of rivers has become the need of the hour. Union Government should give importance to linking of rivers in the first instance. I thank you for this wonderful opportunity, Thank you.

(ends)

(1530-1535/AK/CP)

1535 hours

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Hon. Chairman, Sir, I thank you for giving me a chance to speak on this subject.

Sir, according to the Government data, India accounts for one-fifth of global deaths due to floods that lends perspective to a new World Bank study that says : “Climate change will lower the standards of living of nearly half of India’s population by 2050.”.

According to the Central Water Commission’s data presented to the Rajya Sabha, as many as 1,07,487 people died due to heavy rains and floods across India over 64 years between 1953 and 2017. Floods have caused considerable damage across India in this season. Nearly, 91 districts in the Indian States have been affected since the beginning of this monsoon, and a total of 511 people have lost their lives. Many States have been affected like Assam, Kerala, Maharashtra, Gujarat, etc., and their figures are there. As regards Kerala, their issues have already been mentioned here. We all have sympathy for all the States where people have been affected, and all

cooperation should be extended by the Central Government to all these States.

As far as West Bengal is concerned, 19 districts have been affected; lives lost is 72; five people have been injured; houses damaged partially and fully are 6,910; animals affected are 12; and crop area affected is 47,679 hectares. Other States have also been affected, and those figures are also with me. As far as Maharashtra is concerned, 123 persons have died, and 128 persons have died in Karnataka. So, those figures are there.

Now, I want to point out that the State of West Bengal, being the lower-most riparian State, received most of the storm water generated in the catchments of inter-State and trans-boundary rivers like Damodar, Kangsabati, Subarnarekha, Mayurakhi, etc. in the Southern parts, and Ganga, Padma, Mahananda, Atreye, Tangon, Teesta, Torsa, Jaldhaka and Sankosh in the Northern parts. Apart from passing of heavy flood discharge, a huge amount of silt is also carried by these rivers, which gets deposited in the river beds leading to decrease of water carrying capacity in the rivers and drainage channels. This accounts for perpetual river erosion and inundation in almost 43 per cent of the State.

The flood situation is aggravated when they release water from the dams of neighbouring State of Jharkhand coupled with unfavourable outfall condition due to the high tidal congestion. As a result of the release of water by the Damodar Valley Corporation (DVC) from Durgapur Dam, three Districts, namely, Hoogly, Howrah, and West Midnapore are affected every year. DVC, in a high-handed manner, takes the decision to release water and people of Bengal are affected due to it, and every time the Control Room is being opened by the State Government. This year, the hon. Chief Minister, Madam Mamata Banerjee, has taken charge of the Control Room, and she is looking after everything. She is sitting in the Control Room to look after the steps being taken to extend help to all the affected people.

The State faced an unprecedented flood during the monsoon of 2017 in different spells. The Southern part was seriously affected during the heavy downpour during 18 July 2017 to 28 July 2017 coupled with a maximum release of 2,50,000 cusecs of water from DVC Dams. The seven Districts of Northern part of the State were also affected due to heavy river discharge coming from Sikkim, Bhutan, Bangladesh and Bihar, and around 87.23 lakh people were

affected. The estimated cost of damages was to the tune of Rs. 18,193 crore. However, the Central Government only granted an assistance of Rs. 838.95 crore under the National Disaster Relief Fund, which is barely 4.6 per cent of the estimated cost of flood damages.

(1540/SR/NK)

In order to have an understanding about the position of West Bengal in regard to getting assistance under NDRF vis-à-vis Gujarat, it is stated that as per media reports published during the end of July 2017, 3.50 lakh people were affected in Gujarat during 15th to 26th July of 2017, which prompted the hon. Prime Minister to make a quick aerial visit and to announce *ex gratia* as well as interim grant of Rs.500 crore. Subsequently, the High-Level Committee, headed by the hon. Finance Minister granted Rs.1055.06 crore for Gujarat and Rs.1711.66 crore for Bihar and even Rs.836.09 crore for Madhya Pradesh under NDRF, whereas the share of West Bengal was only restricted to Rs.838.85 crore.

Construction of new embankments, resuscitation of drainage channels and rivers, rehabilitation of dams and barrages etc., are not possible with the State's own resources only. The State Government

has formulated and is implementing three comprehensive flood management projects with Central assistance under FMP. Pursuant to the accordance of techno-economic clearance to the first phase, work of Ghatal Master Plan at an estimated cost of Rs.1214.92 crore by the Advisory Committee of MoWR, RD&GR, Government of India on 25th May, 2015, specific proposal for obtaining investment clearance on the said project was submitted. But, in this regard, the hon. Chief Minister of West Bengal also wrote several letters. But the issue of accordance of investment clearance is still lying pending with MoWR, RD&GR of the Government of India. The hon. Chief Minister of West Bengal also wrote to the hon. Prime Minister on 19th June, 2015 and to the hon. Minister of Road Transport and Highways and Shipping on 22nd September, 2017 for accordance of investment clearance and inclusion under FMP to avail the Central grant. The revised estimated cost of the project is now Rs.12,38.95 crore and it has also been approved by the Advisory Committee of the Ministry of Water Resources, Government of India during its 136th meeting. But, the money has not reached West Bengal at all.

Fund release proposals for two ongoing projects under FMP namely, Kaliaghai-Kapaleswari-Baghai Basin Drainage Scheme

were submitted on 31st August, 2017 for release of Rs.80 crore. But, it has not yet been released. More importantly, the Ministry of Water Resources, Government of India *vide* letter dated 19th January, 2005 agreed to take up anti-erosion works on the banks of the Ganga for a total stretch of 120 kilometres. The Farakka Barrage Project Authority did not address the erosion problem in their defined jurisdiction. The State Government raised the urgency for taking up such works on several occasions through Farakka Barrage Project Authority. The hon. Minister, in-charge of Irrigation and Waterways Department highlight the issue *vide* his letter dated 3rd February, 2015. The hon. Chief Minister of the State wrote to the hon. Prime Minister on 10th August, 2017 to take up immediate restoration of eroded vulnerable zones of length 28.80 kilometres consequent to the decision of the MoWR, RD&GR to retrieve to its original jurisdiction communicated through the letter dated 11th July, 2017. A preliminary project report was prepared. That preliminary project report identified 28.80 kilometres at an estimated cost of Rs.1000 crore in the districts of Malda, Murshidabad and Nadia to take up anti-erosion works on those vulnerable stretches of the bank of the River Ganga which are thickly populated. Almost 2,800 hectares of

fertile land has been engulfed by the river and damages to the public and private properties is to the tune of Rs.1000 crore during the last 12 years.

(1545/UB/SK)

The Central Government should immediately provide adequate funds.

Sir, erosion of the banks of the Bhagirathi River is due to movement of coal carrying barges. We are repeatedly writing letters to the MoS (Home Affairs), Mr. Rijiju. He is aware of all these facts but no response has come from him yet. The last letter was written on 29th March, 2017 but no response came from him.

The anti-erosion work was taken up by the Department in 2013-14 at the international border with Bangladesh to protect the border outposts of BSF and adjacent roads, pursuant to the decision taken in technical level meeting between India and Bangladesh. The schemes were in place and 100 per cent funding from Central Government of Rs. 96.56 crore under River Management Activities and Works Related to Border Areas was approved. Only Rs. 25.34 crore had been released by the Central Government in 2015-16.

Now, the State Government submitted the proposal for the release of due funds of Rs. 71.21 crore in 2016-17 but nothing has come.

Today, we are all sympathetic to all the States which are affected. I have given the figures of affected States also. Our West Bengal is also seriously affected but why you are treating us as a step-brother! When there is flood in Gujarat, you raise funds. When there is flood in Bihar, you have joined with JD(U), you raise funds. You are raising funds for Maharashtra also. Where there is BJP, you raise funds. But why not in West Bengal! Why are you treating us as a step-brother? Why are you not releasing funds for West Bengal? After all, we are also the people of this country. The Prime Minister and your leaders are expecting that, in 2019, they will get 20 seats. You have got 22 seats. When the Prime Minister addressed the meeting at Midnapore, the tent collapsed and 26 persons got admitted into the Midnapore hospital itself.

Sir, it is a national calamity, a national problem, all the people of the nation have to be addressed. They should take care of every State and release funds, which you had promised in the meetings.

(ends)

1548 hours

SHRI KALIKESH N. SINGH DEO (BOLANGIR): Sir, I just came back yesterday from my Constituency. I saw the devastating effects of simultaneous drought over the last two or three years and, recently, in the last five-seven days of heavy rainfall. There is flood in the areas of Odisha.

Sir, natural calamities are not new, they have been occurring and will be occurring. What is new in this entire situation is the apathy and the negligence of the Central Government towards the State of Odisha and towards the situation.

Last year, in 2017, as per the IMD Report, India received 59 per cent deficit rainfall. The livelihood of over 33 crore people was adversely affected by drought in 2017 and in 2016 also. Yet, the Prime Minister says that he wishes to double the income of farmers. For that, he has raised the MSP on rice by a mere Rs. 80 to begin with and further by another Rs. 200, with the idea of giving 50 per cent profit to farmers. I can tell you with authority that this particular hike in the price of MSP does not give 50 per cent profit to the farmers of Odisha or to the farmers of eastern India.

(1550/KMR/RPS)

I am sure the hon. Agriculture Minister will explain this process. It has been discussed before in Parliament also. When you talk of doubling farmers' income, when you talk of giving 50 per cent profits to the farmers of India, it is to the farmers of the whole of India. Why leave Eastern India out of it; why leave the States of Bihar, West Bengal, Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh? These are all States which will be affected. The reason is, in the 1960s when the first Green Revolution happened, it happened in Northern India, it happened in Western India. Regional imbalance of Eastern India can be demonstrated purely by the hardships that the farmers of Eastern India face.

The Prime Minister has repeatedly talked about the second Green Revolution. But where is the second Green Revolution? It remains just another empty rhetoric of the current Government at the Centre.

Sir, Odisha has had 30 per cent deficit rainfall till today; 27 per cent deficit rainfall for the month of June. The problem is not the total quantity of rainfall in a year but the problem is the erratic nature of rainfall, the non-predictability of the kind of rainfall that we have in

the country as a result of climate change. Yet, the Government of India and especially the Agriculture Ministry have been unable to devise a concrete plan to tackle the adverse impact of climate change on agriculture.

It is a well-known fact that the largest impact of that will be on the States of central and coastal India. However, I have not seen a single statement which talks about the adverse impact of climate change on agriculture, especially on the livelihoods of more than 60 per cent of people who live in this area, and the steps that will be taken by the Ministry of Agriculture in this case.

Sir, we have seen the apathy of the Central Government not only in the major allocations towards this sector but even in the release of funds. Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana has a fund sharing of 60 per cent by the Centre and 40 per cent by the State, yet it is called Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. We have no objection. Call it what you like but out of the Rs.2,340 crore budget for irrigation in Odisha, a mere Rs.47 crore has been released so far. We are already three or four months into the budget year. अगर आप पैसा नहीं देंगे तो हम खर्च कब करेंगे और अगर हम खर्च नहीं कर पाएंगे तो किसानों को लाभ कैसे देंगे, मुनाफा कैसे देंगे? Is this another example of doubling

farmers income? Is this another example of the second Green Revolution that we talk of?

Sir, simultaneously we have got the flood situation. While in the last seven days we have had heavy rainfall, the illegal dam built by Chhattisgarh Government on Mahanadi which dries out the river in summer season and when the fllodgates are open during heavy rainfall indundates parts of coastal Odisha with water, the Central Government has not taken a single step against that. In fact, the Central Government, by choosing to remain a mute spectator, has actually encouraged the amount of difficulty on the people of Odisha.

Sir, the Central Government is now constructing National Highways in the cities of Bhubaneswar and Cuttack. Not recent, for the last 20 years they have been constructing. However, it is the lack of drainage facilities on these highways which is now causing a flood like situation in urban areas of Bhubaneswar and Cuttack.

SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR): Poor planning of the UPA.

SHRI KALIKESH N. SINGH DEO (BOLANGIR): Yes, it is poor planning of the UPA and poor implementation of the NDA. I am glad

my friend Anurag Thakur agrees that both the UPA and the NDA have been poor in their outlook towards Odisha.

(1555/GM-ASA)

The hon. Finance Minister says, “we will double the income of farmers.” Yet, the average growth rate of agriculture remained at below 1.5 per cent. The share of agriculture in aggregate GDP is likely to decline to less than 10 per cent by 2019-20. This is a sector on which 60 per cent of India’s population depends. They will only contribute 10 per cent or even less to the GDP. Can you imagine the per capita income of farmers or those who depend on agriculture? Yet the Government chooses to remain a mute spectator. This, coupled with demonetisation, which effectively removed liquidity from farming community or rural community, has crippled the farmers and landless labourers of Odisha. I am sure the same impact is there across the country. Yet the Government has refused to increase credit to the amount required to the farming community. I am sure the hon. Minister will explain in his statement as to how much credit has been actually deployed in the agriculture sector.

With due respect Sir, I was the mover of the Motion. *… (Not recorded)* removed me from no. 1 position to no. 2. I would request you to give me some time.

माननीय सभापति (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : हमारे पास समय निर्धारित है। उसी में काम चलाना है।

श्री कलिकेश एन.सिंह देव (बोलंगीर) : सर, ठीक है। उसके बदले में दाम वृद्धि जो हुई है, जो डीजल और पैट्रोल के दाम बढ़ाये गये हैं, since 2014. पहले धान का दाम दस प्रतिशत बढ़ाएंगे लेकिन इनपुट का दाम 50 प्रतिशत बढ़ाओगे तो किसानों की इन्कम आप क्या डबल करेंगे? जो सूखा और बाढ़ होता है, उस पर आप रिएक्ट नहीं करेंगे। जिस किस्म से आपको रिएक्ट करना चाहिए, वह अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे ओडिशा की तरफ देखें। We had cyclone Phailin when 10 lakh people were evacuated over three days. That is a record attempt and the hon. Minister and the hon. Prime Minister complimented the State of Odisha when that happened. We are happy to extend whatever support the NDRF requires to teach them how these matters are dealt with. The fact is that instead of increasing allocation for farmers of Odisha keeping in view the drought and flood situation which have occurred in Odisha, the Government is blocking the rightful waters of Odisha, constructing the Polavaram dam next to the State of Odisha where

thousands of acres of tribal land are going to be inundated in an area which is naxal-prone and Maoist-prone, thereby creating landless labourers of thousands of tribal people.

माननीय सभापति : अब आप समाप्त करिए। आप समय से दो मिनट ज्यादा बोल चुके हैं।

श्री कलिकेश एन.सिंह देव (बोलंगीर) : सर, ठीक है, समाप्त करने वाले हैं। मैं दो चीजें रखूंगा। There are some low-hanging fruits; very easy tasks. There are 30 railway stations in Odisha where you have to announce rake points to help the farmers of Odisha. It has been languishing in the Ministry of Railways for years but not one step has been taken towards that. Lastly, जो प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना है, जिसका 50 प्रतिशत पैसा केन्द्र सरकार से आता है और 50 per cent is contributed by the State Government. It is called Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रधान मंत्री का नाम आप लेते रहिए लेकिन पैसा तो रिलीज कीजिए। जो क्रॉप इंश्योरेंस का पैसा इस साल का 4-6 महीने डिले हो रखा है, आज तक ओडिशा राज्य में नहीं आया है। The rains have started; farmers don't have access to it.

माननीय सभापति : अब आप समाप्त करिए। श्री प्रतापराव जाधव जी, आप प्रारम्भ करिए।

SHRI KALIKESH N. SINGH DEO (BOLANGIR): The Government of India must impress upon those insurance companies to ensure that this money is released in a timely manner. I am not saying that you should double the farmers' income, but at least there should be a semblance of giving some benefit to the farmers of India, especially to those of my State of Odisha.

(ends)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, मेरे पास इस विषय पर बोलने वालों की लम्बी सूची है। जो भी सदस्य अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं, उनको अनुमति दी जाती है कि वे अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रख दें। प्रतापराव जाघव जी, अब आप बोलिए।

(1600/RAJ/RSG)

1600 बजे

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): सभापति महोदय, हम लोग सदन में नियम 193 के तहत बाढ़ और सूखे की स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस पर कई बार सदन में चर्चा हो चुकी है। जब हम इसका कारण ढूढ़ने जाते हैं तो एक कारण यह सामने आता है कि पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है।

1600 बजे (श्री आनंदराव अडसुल पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री एवं संबंधित मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि पर्यावरण के हिसाब से अच्छे दिन लाने के लिए हम पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सामाजिक संस्थाएं और व्यक्तिगत रूप से कई लोगों ने सालों से कई पेड़ लगाए हैं। अगर हम उन पेड़ों की गिनती करेंगे, जमीन पर लगने वाले पेड़ों की जमीन का हिसाब लगाएंगे तो हम देश से ज्यादा पेड़ अपने प्रदेश में लगा चुके हैं, लेकिन कभी इसकी एकाउंटिंग नहीं हुई कि हमने कितने पेड़ लगाए और उनमें से आज कितने पेड़ जिंदा हैं। आज किस वजह से यहां पर यह स्थिति बन रही है।

सभापति महोदय, हम कोई योजना लाते हैं तो उसकी निगरानी भी होनी चाहिए। जो लोग योजना के हिसाब से सही ढंग से काम नहीं करते हैं, उनको दंडित भी किया जाना चाहिए। पिछले तीन-चार सालों से महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और बुलढ़ाणा जैसे जिलों में सूखे की स्थिति रही। वहां की छोटी फसलें सूखे से खत्म हो गईं, लेकिन जो

हमारी बागयती खेती थी, वहां पर हमने फलों के पेड़, जैसे वहां पर संतरा, मौसमी और आम के पेड़ लगे हुए थे, जिन्हें किसानों ने 10-15 साल मेहनत करके बड़े किए थे, वे भी सूखे की स्थिति के कारण सूख गए। सरकार के माध्यम से प्रति हेक्टेयर चार-पांच हजार रुपये की मदद मिलती है। एक पेड़ में फल आने में किसानों के पांच-साल तक का समय चला जाता है लेकिन वहां पर सरकार की तरफ से बहुत कम पैसों की मदद की जाती है।

सभापति महोदय, हमारी सरकार ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना जैसी एक अच्छी योजना शुरू की है, लेकिन उसका जो असर गांवों के किसानों तक दिखना चाहिए था, मैं कृषि मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि अभी तक उसका वैसा प्रभाव नहीं दिख रहा है। पिछले साल महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के कुछ जिलों में सूखा पड़ा था। वहां पर लोगों ने बीमा कराया था और बहुत सारे इंस्टॉलमेंट्स बीमा कंपनी को दिए थे। बीड जिले के कम से कम पांच सौ किसानों को बीमा कंपनियों ने एक रुपया दिया। यह बीमा कंपनी के लिए भी शर्म की बात है। सरकार को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि जब करोड़ों रुपये का इंस्टॉलमेंट किसान और सरकार मिल कर बीमा कंपनी को देते हैं तो बीमा कंपनियों से हमारे किसानों को क्या मिल रहा है?

मैं आज की चर्चा के माध्यम से कृषि मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे अपने जवाब में बताएं कि हर साल किसानों का 50 प्रतिशत इंस्टॉलमेंट और सरकार की तरफ से भरे जाने वाले इंस्टॉलमेंट की कितनी रकम बीमा कंपनियों को जाती है। हर साल बीमा कंपनी नुकसान भरपाई के माध्यम से किसानों को कितना पैसा देती है? अगर इसका हिसाब देखा जाए तो फसल बीमा योजना किसानों के लिए कम और बीमा कंपनियों

के मुनाफे के लिए ज्यादा चलाई जा रही है, ऐसा वहां के सभी लोगों को भ्रम पैदा हो रहा है।

सभापति महोदय, जब हमारे यहां पर कहीं सूखा पड़ता है तो कहीं बाढ़ आती है। इससे किसानों का ज्यादा नुकसान होता है। यह कृषि प्रधान देश है। हमारा देश किसानों के देश के रूप में पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, लेकिन किसान सभी तरह की विपदा और नुकसान झेलते हैं। किसान सरकार की तरफ बहुत आशा के साथ देखते हैं कि सरकार की तरफ से हमारी मदद होनी चाहिए। सरकार के द्वारा बहुत उन्हें कम मदद मिलती है। मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस क्षेत्र में बाढ़ आती है या जिस क्षेत्र में सूखा पड़ता है, उसके कारण वहां फसल बर्बाद हो जाती है। जिस फसल को किसानों ने बैंक से कर्ज लेकर, अपना पसीना बहा कर उगाते हैं, अगर वह बाढ़ या सूखे से बर्बाद हो जाए तो उन किसानों का बैंक कर्ज तुरंत माफ होना चाहिए।

(1605/IND/RK)

यदि किसान के घर फसल नहीं आएगी, तो किसान बैंक का कर्ज कहां से उतारेगा? अगले साल बुआई के लिए बीज और खाद लेने के लिए किसान पैसा कहां से लाएगा? ऐसी स्थिति में सरकार को कानून बनाना चाहिए या ऐसी पालिसी बनानी चाहिए कि जहां सूखे या बाढ़ की वजह से किसानों का नुकसान होता है, वहां किसानों ने खेती के लिए जो कर्ज लिया है, वह माफ होना चाहिए।

महोदय, बाढ़ की स्थिति से खराब फसल का सर्वे होता है और इस संबंध में जो कानून बनाए गए हैं, किसानों को उनका पूरा लाभ नहीं मिलता है। राज्य सरकारें यह

कहती हैं कि हमने केंद्र सरकार को मदद के लिए प्रस्ताव भेजा है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा मदद भेजने में इतनी देर हो जाती है कि किसानों की दूसरी फसल की बुआई का समय उनके हाथों से निकल जाता है। हमारे जिले में अच्छी बरसात हो रही है। वहां बुआई का काम हो चुका है, लेकिन मैं बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट के लिए कृषि मंत्री जी से कहूंगा कि नेशनलाइज बैंकों ने किसानों को फसल के लिए जो कर्ज दिया है, वह कुल किसानों का 18 परसेंट भी नहीं है। अभी तक सिर्फ 18 परसेंट के करीब किसानों को ही कर्ज मिला है। कोई राष्ट्रीयकृत बैंक किसानों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं हैं। किसान महीनों से चक्कर काट रहे हैं। सरकार की तरफ से जो मदद किसानों को दी जाती है, वह ऑनलाइन एकाउंट खाते में दी जाती है। अभी प्रश्न काल में हमारे दूर संचार मंत्री जी ने भी कबूल किया है कि इस देश के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां इंटरनेट या ब्रॉडबैंड सुविधा अच्छी हालत में नहीं है। देहातों की बैंक शाखाओं में इंटरनेट सुविधा अच्छी नहीं है। ऑनलाइन जाने वाला पैसा भी समय पर किसानों के खातों में जमा नहीं होता है। किसानों को अर्जी भी ऑनलाइन देनी पड़ती है। चूंकि दो-दो, चार-चार दिन इंटरनेट बंद रहता है इस वजह से ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजने में काफी समय बरबाद हो जाता है। डिजिटल इंडिया या ऑनलाइन व्यवस्था करने से पहले देहातों में अच्छी इंटरनेट सुविधा हर किसान तक पहुंचनी चाहिए। बुलढाणा जिले में कुछ जगहें ऐसी हैं जो सूखे की चपेट में हैं और कई जगहें ऐसी हैं जहां ज्यादा बरसात होने से फसलों का नुकसान हो रहा है। ऐसी स्थिति में वहां कृषि विभाग के जो अधिकारी काम करते हैं, उनके सर्वेक्षण में भी बहुत फर्क आ जाता है कि एक ही जिले के दो तहसीलों में अलग-अलग स्थिति है। मेरे बुलढाणा जिले में सिंडखेडराजा, देआलगांव

राजा, लोनार आदि दो-चार तहसील में बहुत कम वर्षा है। जबकि जलगांव, संग्रामपुर, मोहताला, मेहकर आदि तहसीलों में बरसात ज्यादा होने से वहां की फसल खराब होने जा रही है। ऐसी स्थिति में हमारी पालिसी होनी चाहिए कि जैसे इंडिविजुअल किसानों के लिए फसल बीमा योजना बनाई हुई है कि किसी व्यक्ति का नुकसान होगा, तो उसकी भरपाई होगी। ऐसे ही बाढ़ में या ज्यादा बरसात से किसी भी किसान का नुकसान होता है, तो चाहे किसानों की संख्या कम हो, उस एरिया के किसानों को भी सरकारी मदद समय से मिलनी चाहिए।

महोदय, सूखे के समय सबसे ज्यादा किल्लत पीने के पानी की होती है। वहां टैंकरों से पानी दिया जाता है और पानी देने का कोई नियम नहीं है। चार-पांच हजार की संख्या वाले गांवों में दस हजार लीटर वाला केवल एक टैंकर भेज दिया जाता है। जब टैंकर वहां जाता है, तो वहां झगड़ा हो जाता है और कई गांवों में तो दंगा तक हो जाता है। इसके लिए भी कानून होना चाहिए कि यदि किसी गांव में पीने के पानी की किल्लत है, तो वहां की जनसंख्या के हिसाब से वहां कितने लीटर पानी देना है, यह सरकार को तय करना चाहिए। सरकार द्वारा कई बार किसानों के बोरवेल का अधिग्रहण किया जाता है, लेकिन दो-दो सालों तक किसानों को पैसा नहीं दिया जाता है और इस वजह से कभी-कभी किसान इसके लिए मना कर देते हैं। हम जो भी हम घोषणा करते हैं, उसका फायदा सही ढंग से किसानों तक पहुंचे, इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बाढ़ और सूखा, हमारे रोकने से रुकने वाले नहीं हैं। ये आपदाएं पहले भी आती थीं और भविष्य में भी आती रहेंगी लेकिन इनके लिए जो उपाय करने की जरूरत है, उसके लिए ठीक से पालिसी बनाने की जरूरत है। **(इति)**

*SHRI D.K. SURESH (BANGALORE RURAL):

*Laid on the Table

***श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग):** माननीय अध्यक्ष महोदया, आज दिनांक 25.07.2018 के दिन सभागृह में Under Rules 193 पर चर्चा में मैं अपना विचार लिखित स्वरूप में दे रहा हूं। कृपया स्वीकार करें।

अध्यक्ष महोदया, इस वर्ष में बरसात के मौसम में महाराष्ट्र के कोंकण प्रांत (रत्नागिरी और सिंधूदुर्ग जिले) में बहुत-सी बस्तियों में बड़ी मात्रा में बाढ़ आयी थी। इस वर्ष में बारिश ज्यादा होने की वजह से समुद्र तटीय क्षेत्र और नदी किनारे के गांव में बाढ़ की स्थिति बनी थी। इसके कारण नदी और समुद्र तटीय गांव की बस्तियों में पानी घुसने से भारी मात्रा में नुकसान हुआ। कई गाँवों का मुख्य शहरों से दस-पंद्रह दिनों तक संपर्क नहीं हो रहा था। मरीजों और छात्रों को इसका भारी नुकसान सहन करना पड़ा।

अध्यक्ष महोदया, मेरे क्षेत्र के यात्री महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधूदुर्ग जिले के समुद्र और नदी के पास बसे हुए बस्ती को हर वर्ष इस आपत्ति से गुजरना पड़ता है। हम लोक प्रतिनिधि और वहां के स्थानीय लोग वर्षों से मांग करते आ रहे हैं कि समुद्र तटीय बस्ती के पास संरक्षक दीवार एवं बांध बनाया जाए। हमारे कोंकण यानी रत्नागिरी सिंधूदुर्ग जिले में बहुत-सी नदियां हैं, जो पूरी तरह से मिट्टी एवं पत्थर से भर गयी हैं। इन नदियों से पत्थर, किचड़ एवं मिट्टी निकालने का काम होना चाहिए ताकि बरसात का पूरा पानी नदी में ही रह जाए। बालू (सैंड) निकालने का काम लगातार होता रहेगा, तो बाढ़ की स्थिति नहीं रहेगी।

---

*Laid on the table

अध्यक्ष महोदया, इस चर्चा में भाग लेते हुए मैं मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र के महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले और सिंधूदुर्ग जिले में समुद्र तटीय जो गाँव हैं, उन्हें संरक्षित करने की योजना शीघ्र बनाएं और लोगों को राहत देने का काम शासन की तरफ से करें।

धन्यवाद,

(इति)

***श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल) :** महोदय जी,193 पर मैं देश भर में सूखे से किसानों का जो हाल होता आया है, उस पर मैं अपनी बात रख रहा हूं।

पिछले चार सालों से देश के कई राज्यों में सूखा और ज्यादा बारिश से किसानों का भारी नुकसान हुआ है। इस वजह से ज्यादातर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। देश भर में खासकर महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ मराठवाड़ा का इलाका सूखे से ज्यादा प्रभावित है। कई बार ओले गिरने से किसानों की फसल का नुकसान हो जाता है। राज्य सरकारें किसानों को राहत देने के लिए मदद करती हैं, लेकिन यह मदद समय पर उन्हें नहीं मिल पाती है। केन्द्र सरकार द्वारा किसानों को अधिकतम मूल्य (निर्धारित रकम) देने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि किसानों के हुए नुकसान की भरपाई उन्हें मिल सके।

मैं केन्द्र सरकार से किसानों को समय पर मदद करने की मांग करता हूं। इसके साथ ही सरकार द्वारा किसानों का सूखा और भारी बारिस एवं ओले गिरने के कारण हो रहे नुकसान का भुगतान समय पर देने की मांग करते हुए आत्महत्याग्रस्त किसानों के परिवारों को मदद देने की भी मांग करता हूं।

---

*Laid on the table

*SHRIMATI PRATYUSHA RAJESHWARI SINGH (KANDHAMAL):

*Laid on the Table

*DR. P.K. BIJU (ALATHUR):

*Laid on the Table

* SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI):

*Laid on the Table

*SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN (VADAKARA):

---

*Laid on the Table

*SHRI ARKA KESHARI DEO (KALAHANDI): Respected Deputy Speaker, Sir, I rise to speak on flood and drought situation due to heavy rains in different parts of the country during the last couple of weeks, in the month of June and July.

Sir, I represent Kalahandi Parliamentary Constituency in the State of Odisha. Heavy rain in the last week causes flash flood in Kalampur, Junagarh, Jaipatna, Thuamul Rampur, Lanjigarh and Madanpur Rampur Blocks of my constituency. The river Hati overflooded and cut off the connectivity to thousands of villages of six blocks. Half of the Kalahandi district remained without electricity and power supply for four days. Many bridges have been collapsed, roads submerged and washed away, the standing kharif crop in the above said six blocks have been damaged. The people, cattle, sheep, goats and other domestic animals have suffered a lot. This flash flood brought heavy damage to houses, roads, crops, buildings of my constituency. This flood has been compared as the worst one in the current decade.

---

*Laid on the Table

I urge the Hon'ble Minister of Agriculture through you to send a Central team immediately to Odisha to assess the damages caused by this flood. Sir, farmers may kindly be given special assistance for the flood affected villages. Likewise, the Rural Development Department also after taking the damage assessment of different rural development roads may kindly release funds for the repair of the damaged road of the flood affected villages. As you know, Sir, my constituency is located in the western region of the State of Odisha and comparatively less developed than the coastal districts of the State.

Thank you, Sir, for allowing me to speak on the flood and drought situation in the country.

(ends.)

(1610/PS/VB)

1610 hours

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) (ANAKAPALLI): Hon. Deputy Speaker, Sir, I thank you for giving me an opportunity to participate in the debate under Rule 193 on 'Natural Calamities in the Country'.

माननीय सभापति (श्री आनन्द राव अडसुल): पाँच मिनट में अपनी बात पूरी करें।

श्री मुथमसेटी श्रीनिवास (अवंती) राव (अनाकापल्ली): सर, बहुत-से इश्यूज हैं।

माननीय सभापति: संख्या के अनुसार ही समय दिया जाता है।

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) (ANAKAPALLI): Hon. Deputy Speaker, Sir, regular occurrence of disasters, both natural and man-made, in coastal Andhra Pradesh in India has had a series of repercussions on the State's and country's economy, its developmental policies and political equilibrium and the daily life of millions of Indians. I just want to say that Andhra Pradesh is not only battered by every kind of natural disasters, that is, cyclones, floods, earthquakes and drought, but also by the A.P. Reorganisation Act. The coastal region suffers repeated cyclones and floods. Rivers caused havoc in the East and West Godavari and Krishna districts. Further, in 2014-15, Andhra Pradesh was hit by

'Hudhud' cyclone, which had destroyed the infrastructure, trees, telecommunication, houses and the scene was just like a war-torn area. At that time, the State had made a demand of Rs. 1000 crore to carry out relief and rehabilitation works. The hon. Prime Minister had also promised Rs.1000 crore relief for the same. But, I am sorry to say that the Central Government had given just Rs.650 crore.

Consequent upon the acceptance of the recommendations of the Ninth Finance Commission, a Calamity Relief Fund was constituted for each State with certain amount allocated to each State. Now, we have 15th Finance Commission. I do not know as to what the quantum of CRF is. It should be increased substantially to help the States affected by natural calamities.

We have to develop our capabilities in Seismology to be able to forecast such natural calamities so that we can take preventive measures to avert loss of lives.

Finally, I want to say a few things about the A.P. Reorganisation Act. If a cyclone or Hudhud cyclone occurs within six months, the State would become normal. But, with the bifurcation of the State, even after four years, the State is reeling under the financial crisis. As promised by the then hon. Prime Minister, Special Category

Status has not been given. The Centre gave a plea that the 14th Finance Commission has recommended Special Assistance Measure instead of SCS. Nowhere it has been mentioned that do not give SCS.

For constructing the capital city of Amravati, a lot of funds is required. But, the Centre is going back on its promises. Our hon. Chief Minister, Shri Nara Chandrababu Naidu is doing his best to construct a model capital city with whatever available resources. Even the creation of Railway Zone at Visakhapatnam is hanging in balance. The hon. Minister has given some hope in Rajya Sabha yesterday that they are going to do it very early. But, I am putting my fingers crossed. The youths of the State are eagerly waiting for the Railway Zone so that they can get employment opportunities.

Regarding Polavaram Project, 53 per cent of the work has been completed. Out of around Rs. 8660 crore, up till now Rs. 6,727 crore has been released to A.P. I request the Government to release the balance amount of Rs.1935 crore forthwith. Our hon. Chief Minister is making strenuous efforts to complete the project by 2019.

Sir, every year, Rayalaseema region is facing an extreme drought situation. But, with the efforts of our hon. Chief Minister, after

the linking of rivers – Godavari and Krishna, we are able to release water to Rayalaseema region. But, to ensure continuous water supply to this region in the future, the completion of Polavaram Project is important. Not only it is important for Andhra Pradesh, but also for Tamil Nadu and Karnataka, as they are fighting for Kaveri waters. If the Polavaram Project is completed, you can even release water to Tamil Nadu.

Our State is very peculiar. On the one hand, we have a series of cyclones every year. There are two to three cyclones every year.

(1615/RC/VB)

On the other side, we have Rayalaseema region which is the most drought affected area in the country. That is why, I would request the Union Government to consider our 18-19 requests which are there under AP Re-Organisation Act. For the last four years, we are eagerly waiting. It is not the request of my Party or of the Chief Minister of Andhra Pradesh. It is the request of the five and a half crore people of Andhra Pradesh. They are eagerly waiting for the Polavaram Project. It is a lifeline project of the nation. It is the pride of the nation. I would request the Government to complete the Polavaram Project without playing any politics.

Secondly, we had asked for Rs.40,000 crore to construct the capital city of Amravati. But they have given only Rs.1500 crore which is a very meagre amount.

We have seven backward districts in Andhra Pradesh. They have released only Rs.1050 crore but they have taken back Rs.350 crore. It is very unfortunate. Politics is not permanent. The State is permanent. The Centre is permanent. The people are permanent. The sentiments of the people are permanent. I would request the Union Government to release Rs.350 crore immediately.

Thirdly, Visakhapatinam Railway Zone has been a sentiment for three decades of North Coastal Andhra Pradesh. Every year, our students have to go to Bhubaneswar for examinations. They are facing a lot of problems. Eastern Zone is in Bhubaneswar. The other divisions are Vijayawada and Secunderabad. We have four divisions but we do not have zones.

When we ask for Special Category Status, the Union Government says that if we give Special Category Status to Andhra Pradesh, Bihar will also ask for that. If we give the Railway Zone to Andhra Pradesh, Odisha will object. So, is Andhra Pradesh not a part of this country? Andhra Pradesh has contributed substantially

to the development of this country. Hence I would request the Union Government to look towards Andhra Pradesh as a special case. It is the request of five and a half crore people of Andhra Pradesh.

(ends)

1617 hours

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Sir, I thank you very much for giving me this opportunity.

Every year at the same time when we have Monsoon Session, we always have a discussion under Rule 193 where we speak about floods and drought. We got Independence 70 years ago. We can assume the climatic changes which are happening, the amount of water which comes, rainfall which comes, etc. But even then we are still not able to train the rivers properly and give sufficient water to places where there is a severe drought.

Sir, Telangana does not have a coastal area and we are not facing a lot of floods every time. However, in 2015-16, 231 Mandals of Telangana were declared as drought affected areas. We had claimed Rs.2000 crore as damages for the crops but the Government has sanctioned only Rs.702.71 crore. But this year, we still have got time and by October we will assess where the waterfall has come and where the drought situation is there. However, we have to use flood water for irrigation purposes. If we use it in a proper way and give it to farmers, that would be the ultimate remedy.

Before the bifurcation of Andhra Pradesh, Telangana was often helpless due to drought-like situations in certain areas and flooding in other areas. Therefore, after achieving statehood of Telangana, as a result of continuous struggle and people's movement, our leader KCR identified development of irrigation sectors as one of the primary components for mitigating the adverse effects of frequent drought/floods and rescue the farming sector from constant distress.

(1620/SNB/GG)

Sir, this distress has primarily been caused by inefficient usage of available water resources in the country. Only 35 to 40 per cent of water is currently being used from the total available water which is roughly about 26,000 to 27,000 TMC of water. If we see the records, we will find out that we receive a total of 70,000 TMC of water in our country. Of this 65,500 TMC of water is in the form of rivers and rainfall and around 3,000 TMC of water is from rivers originating in Nepal and Bhutan and remaining water we receive from snowfall, the snow that melts and flows from the Himalayas. The problem here is that in a country with a population of around 130 crores where agriculture is the primary activity, I want to ask as to why water is not used effectively.

Sir, from the records available we understand that there are 40 crore acres of land under cultivation. The thumb rule is that one TMC of water irrigates 10,000 acres of land. For 40 crore acres of cultivable land available in the country, 40 TMC of water will be sufficient for irrigation. When we receive 70,000 TMC of water every year, why can we not give proper water to each and every State? Why can we not train the rivers? Why can we not have a proper irrigation system in the country? On one side of the Himalayas we have China and India is on the other side of it. In China, from the South to the North, up to 1,000 kilometres, they are taking water by laying a pipeline. But here we have fights between States for getting water. Some areas are flooded and some areas suffer from drought.

The Central Government should ensure judicious allocation of surplus water to the needy States. There should be no water wars between States, such as Karnataka and Tamil Nadu; Telangana and Andhra Pradesh; Haryana and Punjab and Odisha and Chhattisgarh. Our State also was deprived of water and rights to access water. Our part of the share was given away to Andhra Pradesh from Krishna and Godavari. Therefore, we decided to launch multiple major and

minor irrigation projects of which most have been completed in the last four years. I would be talking about these projects in detail.

HON. CHAIRPERSON (SHRI ANAND RAO ADSUL): Your time is over. We have to conclude the discussion by 5.30 p.m.

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Sir, I have taken only two minutes. Anyway, I will try and finish within a couple of minutes.

Sir, first I would like to talk about the amount of rainfall that we receive in the State of Telangana. As of 24th July, the State had received a normal rainfall of 310.01 mm with a deviation of only negative of 1 mm this monsoon. 21 districts have received normal rainfall, while four districts have received excess rainfall and six districts have received deficit rainfall. Hence the vison of our leader and the hon. Chief Minister of Telangana has to be commended. In English it is often said that `Mend the roof when the Sun is shining and prevention is better than cure. Following this saying, the Government of Telangana has undertaken irrigation projects in massive scale in order to protect the interest of the people of the State in the event of drought or unforeseen climatic changes. Our efforts have already shown results as in the last two to three years

the State has not witnessed any major floods in the region. Irrigation projects are basic requirements for preventing occurrence of floods.

(1625/RU/CS)

Historically speaking, the region of Telangana has a rich heritage of irrigation projects, right from the time of the Kakatiya dynasty of the early 10th century until the Nizam rule. Many ponds were constructed across the region. Nizam and Quli Qutub Shah implemented similar water conservation projects. Sadly enough, during the united Governance, around 75,000 ponds were destroyed. To construct a bright future, we have to nurture our culture. Under the able leadership of KCR, the Telangana State Government has been working on implementing irrigation projects throughout the State. Through our Mission Kakatiya, we are reviving 46,000 ponds and lakes in all the villages of Telangana. The enthusiasm is so much that the farmers themselves are digging up ponds and cleaning lakes. … (*Interruptions*)

Mission Kakatiya has now been converted into a people's movement. Since 2014, 17,860 tanks have been restored and repaired at a cost of Rs. 9000 crore approximately.

Let me put forth that before the bifurcation of the State, we had 27 lakh acres under cultivation which produced 1.2 crore tonnes of food grains and commercial crops. Due to our continuous efforts, we have brought 59 lakh acres under cultivation in Telangana producing 1.87 crore tonnes of foodgrains and commercial crops.

Sir, I will mention one last point which will be useful to you also. … (*Interruptions*) Sir, I may be allowed to speak for some more time.… (*Interruptions*)

Our commitment to farmers have not only been restricted to paper. The Rythu Bandhu (Kisaan ka Dost) Scheme takes farmers' welfare one step further. We are providing an input grant to our farmers of Rs. 8000 per acre per year. It will be Rs. 4000 during the kharif season and Rs. 4000 during the rabi season. This Direct Transfer Benefit will be provided to 58 lakh farmers in the State. With Rs. 12,000 crore allocated to this scheme in the Budget, *The Economist* magazine said that it will end inefficient subsidies.

Sir, Shri Kalikesh Singh Doe was complaining about insurance amount not being paid. हमने सेंट्रल गवर्नमेंट पर आघात नहीं किया है। We have taken a two-way approach towards the issues which farmers face in our State. While the activities mentioned earlier addresses

the causes of farmers distress, we have also launched a Life Insurance Scheme for all the farmers. The scheme provides for life cover up to 5 lakhs to all the farmers between 18 and 59 years of age. The insurance amount will be paid in a time bound manner within ten days of death. It is the State Government that will pay the premium of more than 50 lakh farmers to LIC. इसका मतलब है कि एल.आई.सी. का प्रीमियम सरकार ही पे करेगी और प्रत्येक किसान को पाँच लाख रुपये का बीमा मिलेगा। … (*Interruptions*)

In conclusion, the people of the State of Telangana have shown a way forward in the irrigation sector of India and there are several aspects where we need the support of the Central Government. … (*Interruptions*) We are here together to support our farmers all along and we understand the importance of agriculture. Without agriculture, there is no culture and without culture, there is no future. … (*Interruptions*)

(ends)

1629 hours

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA (ARAKU): Sir, I thank you for giving me an opportunity to present my views on this very important discussion under Rule 193 regarding the flood and drought situation in our country.

Today, drought and flood are common features and their co-existence poses a potential threat which cannot be eradicated but has to be managed.

Floods are recurrent phenomena in India. Due to different climatic and rainfall patterns in different regions, it has been our experience that in some parts of the country, people are suffering due to devastating floods and at the same time, in some other parts of the country, people are suffering from severe drought. Extreme weather events had been long predicted to be a fallout of climate change.

The impact of flood is quite huge. It accounts to loss of lives, livelihood of the people and destruction of basic infrastructural capacities such as sanitation and transportation leading to isolation and risk of spread of diseases. There is also risk of violence against vulnerable sections especially women. These floods also cause

destruction of ecology and biodiversity of an area that may take years and even decades to recuperate.

(1630/KSP/RV)

Sir, Andhra Pradesh has a long coast line and is often devastated with floods. Many of the districts are also drought hit and water management is a major issue affecting the lives of the people, mostly belonging to vulnerable sections of society.

Talking about the drought situation in Andhra Pradesh, our economy is mainly dependent on agriculture. Out of 76.2 lakh farmers, 86.29 per cent are small and marginal farmers. Uttar Andhra and Rayalaseema areas are drought hit. In the entire country the district which receives the lowest rainfall is Anantapur. This year they have categorised 121 mandals across the State as drought mandals and 3.94 lakh acres are declared as famine struck. The State Government has requested for a Central Assistance of Rs. 679.21 crore for the drought hit mandals, but the funds have not yet been released. So, I would like to know from the hon. Minister the status of this request and whether the Union Government will release this money within the stipulated time frame to support the affected mandals.

It is also not out of place to raise the issue of the Polavaram Project, which is a national project. It is a dream of every citizen of Andhra Pradesh. I wish and request the Union Government to ensure that the project is completed within the stipulated time duly addressing all the related issues of resettlement and rehabilitation.

Today, this drought situation has led to an acute crisis with farmer suicides and loan build-ups. Also, the people in rural areas are migrating to the nearby towns and cities for their livelihood. Even a farmer having 20 acres of land is not able to cultivate his land and, in this context, I wish to state that as many as four lakh farmers have migrated from Rayalaseema for their livelihood to nearby areas. Even in Uttar Andhra, the situation is no different. On the one side, there is severe drought and on the other side, there is fluoride issue, which is endangering the lives of millions of people. Drinking water is yet another major problem which is causing a threat to many lives. Many people are losing their lives due to consumption of contaminated water. Then, people are not able to make use of the Government schemes and they are migrating from their native places.

Drought mitigation involves a comprehensive plan that not only covers water availability, but its judicious use and reuse along with an overhaul of agricultural systems. I wish to state that adoption of micro irrigation techniques by farmers is the need of the day. However, such systems will need to be subsidised to be made competitive for the majority of farmers who are small and marginal farmers. Stringent application of water harvesting measures not only at the individual level, but at the community and village level too are required to be implemented. Watershed programme should be taken up on a war footing. Thirdly, waste water recycling facilities in urban and industrial centres should be allowed for non-drinking uses. Agricultural practices should focus on 'more crop per drop'. The Government should support this through *Krishi Vigyan Kendras*, Soil Health Card scheme and this scheme should be extended to all the Gram Panchayats across the country. In addition to this, agro-climatic condition should be made the basis for crop selection and it should be promoted. This can also be done by adjusting MSP by the Government.

Sir, I would like to conclude by saying that today the country faces the twin challenges of floods and droughts that recur every

year. Even when our country is poised to turn into a major power in the world, it has yet to shed its most basic problems. If we are not able to provide drinking water for the citizens of this country, we are not entitled to talk about big things because we are not able to address minor issues being faced by the people. This not only requires a policy based top-down approach, but a local government-based push. There is an urgent need to intensify efforts to support economic and social development of drought-prone areas. We need a multi-tiered strategy, combining economy-wide and sectoral policies with well targeted efforts at the micro level. Drought is a complex and a challenging natural phenomenon.

Hence, I request the Union Government, through you, Sir, to support the drought-prone areas in the country, support the State of Andhra Pradesh and thereby render justice to the citizens living in this country. Thank you.

(ends)

1634 बजे

श्रीमती वीणा देवी (मुंगेर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन, हमारे बिहार में यह हालत है कि वहां अभी तक बारिश भी नहीं हुई है। अभी भी वहां इतना सुखाड़ है कि वहां के किसान जो धान की खेती कर रहे हैं, वहां जमीन फटती जा रही है, वहां किसान अपने सिर पर हाथ देकर अपनी जमीन पर बैठे हुए हैं। वहां की मिट्टी इतनी सख्त है कि उसे हाथ से कुरेदने पर भी वह नहीं टूटती है। वहां किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। इसके बारे में हमने बहुत बार मंत्री जी को लेटर लिखा है, माननीय प्रधान मंत्री जी को लेटर लिखा है। अभी वहां किसान कर्ज लेकर अपनी खेती कर रहे हैं। चूंकि वहां बारिश नहीं हो रही है, भगवान की मार है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस पर ध्यान दें।

महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि वहां के जो किसान त्राहिमाम कर रहे हैं, उन पर ध्यान दें। हमारे मंत्री जी भी खुद बिहार से हैं और बिहार के हम सब 40 सांसद हैं। इसके लिए हम सब परेशान हैं। इसके विषय में हम सभी सांसद माननीय नितिन गडकरी जी से भी मिल कर आए हैं। राम कृपाल यादव जी, जो हमारे बिहार से मंत्री हैं, वे हमारे साथ जाकर उनसे मिले हैं। हम लोग प्रधान मंत्री जी से मिल चुके हैं। हम लोग इसकी चर्चा बहुत बार कर चुके हैं कि बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करना चाहिए।

(1635/MY/SRG)

सभापति महोदय, इससे पूरे बिहार में 11 करोड़ जनता प्रभावित हैं। हमारे टाल क्षेत्र में सात जिले आते हैं। इन सातों जिलों में जो खेती होती है, उससे पूरे देश को

अनाज मिलता है। बिहार में टाल क्षेत्र को 'दाल का कटोरा' माना जाता है। वहाँ के सातों जिले पूरी तरह से सूखा से प्रभावित हो गए हैं। हमारे मंत्री जी भी बिहार से हैं, इसलिए उनको ध्यान देना चाहिए। जो गरीब किसान कर्जा लेकर तथा अपनी जमीन बेचकर खेती कर रहा है, वह काफी परेशान है। अभी उनका क्या हाल होगा? हमारी सरकार को जल्दी निर्णय करना पड़ेगा और बिहार को सूखा क्षेत्र घोषित करना पड़ेगा। धन्यवाद।

(इति)

1636 बजे

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद): सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे गुजरात सहित देश के विभिन्न भागों में हाल में उत्पन्न बाढ़ और सूखे की स्थिति पर नियम 193 के तहत बोलने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है।

महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत गाँवों में बसा हुआ देश है। जो किसान है, जो कृषि है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है। अगर भारत की इकोनॉमी सबसे अधिक प्रभावित होती है तो वह कृषि से होती है। किसान को खेती के लिए भगवान पर भरोसा रखना पड़ता है। इस वर्ष कैसी बारिश पड़ेगी - अगर ज्यादा पड़ती है तो भी वह मारा जाता है और सूखा पड़ता है तो भी किसान ही मुश्किल में आता है। यह हमारी आज की स्थिति है।

महोदय देश के कई प्रदेशों में काफी वर्षा हुई है और उससे वहां बाढ़ आई है। इसकी वजह से अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वह फसल का हुआ है, खेत को हुआ है, किसान को हुआ है, गरीब परिवार के व्यक्ति को हुआ है, आज उनका घर पानी में डूब गया है। इस चर्चा में आपने मुझे बोलने के लिए जो समय दिया है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ।

महोदय, मैं श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी सरकार तथा कृषि मंत्री जी को हृदय से बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसे ही 18 तारीख को सदन शुरू हुआ, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में हमारी सरकार ने घोषणा की थी कि यह जो स्थिति है, इसको निपटाने के लिए सरकार हर संभव तरीके से आगे आएगी। अभी हमारे कई मित्रों ने कहा कि आज कई प्रदेशों को पूर्णत: इंसाफ नहीं मिल रहा है। मैं आपके सामने एक

बात कहना चाहता हूँ कि देश की आज़ादी के बाद जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, राज्यों का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें अगर किसी ने सबसे ज्यादा न्याय देने का काम किया है तो हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। हम किसी भी राज्य के बीच में भेद नहीं रखते हैं। अभी हमारे एक मित्र बोल रहे थे कि गुजरात तथा महाराष्ट्र को ज्यादा लाभ दिया जाता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति नहीं है।

जहाँ तक गुजरात की बात है, गुजरात में सौराष्ट्र हो या दक्षिण गुजरात का इलाका हो, वहाँ भारी वर्षा के कारण काफी लोग परेशानी में हैं, परंतु मैं गुजरात सरकार का अभिनंदन करना चाहता हूँ, गुजरात सरकार को वहाँ जो कार्य करना चाहिए, वह कार्य तुरंत ही चालू कर दिया गया है। गुजरात के 11 जिले में 789 गाँवों को नुकसान पहुँचा है। करीब एक लाख हेक्टयर जमीन को, खासकर कृषि जमीन और फसल को नुकसान पहुँचा है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने तुरंत वहाँ जाकर स्थिति का जायजा लिया है।

(1640/CP/KKD)

आपातकालीन अधिकारियों के साथ बैठक की है। बीस एनडीआरएफ की टुकड़ियों को वहां भेजा है, कैश वैन पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कहीं पानी नहीं था, तो वहां टैंकर के जरिए पानी पहुंचाया है। स्वास्थ्य सुविधाओं को वहां पहुंचाने का प्रयत्न किया है। मैं गुजरात सरकार का अभिनंदन करना चाहता हूं।

आज यहां सभी लोग एक बात कर रहे थे - वह है क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन की वजह से इस परिस्थिति का निर्माण हुआ है, तो हम आगे बढ़कर उससे

कैसे निपट सकें, इसके लिए भी हमें प्रयत्न करना चाहिए। मैं गुजरात सरकार का आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों और पूरे देश की जनता के साथ एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूं। बारिश के मौसम के पहले गुजरात सरकार ने सुजलाम् सुफलाम् जल संचय अभियान चालू किया था। उस अभियान में गुजरात सरकार ने 13 हजार तालाबों को उंडा करने का कार्य किया। गुजरात सरकार ने 11 हजार घनफुट पानी के संग्रह के लिए अलग-अलग प्रकार की व्यवस्था की। गुजरात में जो 5,500 किलोमीटर कैनाल का नेटवर्क है, उनकी सफाई का कार्य किया।

मैं अहमदाबाद से आता हूं। अहमदाबाद में करीब 25-26 किलोमीटर लंबी खारीकट कैनाल है। वहां बहुत गंदगी भरी थी। हजारों टन कचरा वहां से निकालकर उसे साफ करने का कार्य किया है। करीब 32 नदियों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया है। यह कार्य बारिश के मौसम के पहले किया गया। गुजरात में बारिश आने पर धरती के जलस्तर को बढ़ाने का कार्य होगा। गुजरात सरकार का यह जो कार्य है, मैं इसीलिए शेयर करना चाहता हूं कि सभी लोगों को मालूम हो कि एक राज्य कैसा कार्य कर सकता है, एक राज्य प्रिवेंटिव धारणा के साथ कैसे कार्य करता है। इस बात को अवगत कराने के लिए मैं यह बात कह रहा हूं।

मैंने एक टेक्निकल साइंटिफिक रिपोर्ट पढ़ी थी। मैंने उसका वीडियो भी देखा था। हमारे मंत्री जी यहां सदन में उपस्थित हैं। मैं सभी को यह कहना चाहता हूं कि मैंने ऐसी रिपोर्ट पढ़ी थी कि कहीं बादल फटता है, वहां ज्यादा बारिश होती है, कहीं सूखा पड़ता है, तो उन बादलों को हजारों किलोमीटर दूर, टेक्नोलाजी की सहायता से जहां

सूखा है, वहां खींच कर लाने की एक टेक्नोलाजी है। मैंने उसकी वीडियो भी देखी है। इसकी सहायता से दुबई में बारिश हुई थी। वहां बहुत तेजी से बारिश हुई थी। मैंने उसे वीडियो में देखा है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर ऐसी टेक्निक उपलब्ध है, मैं मंत्री जी से गुहार करता हूं कि क्यों न हम ऐसी टेक्निक जो साइंटिफिक है, वैज्ञानिक तौर पर जो है, ऐसी टेक्निक को लेकर जहां ज्यादा बादल हैं, उनको जहां कम वर्षा है वहां उन्हें खींचकर लाएं।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

(इति)

*PROF. SUGATA BOSE (JADAVPUR):

---

*Laid on the Table

* SHRI PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR):

*Laid on the Table

*SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE):

*Laid on the Table

***श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) :** महोदया, आज देश में कहीं बरसात ने कहर ढाह रखा है, वहीं अन्य स्थानों पर वर्षा ऋतु के होते हुए सूखे की स्थिति बनी हुई है। आज देश के अधिकांश राज्यों जिनमें केरल, ओडिशा, कर्नाटक, बिहार व महाराष्ट्र बाढ़ के कारण परेशान हैं। आज जीवन ठप्प पड़ा हुआ है। यद्यपि सरकारें अपनी कोशिशें करके इसके समाधान में लगी हुई हैं तथापि इस प्राकृतिक आपदा के कारण कई जानें जा चुकी हैं। पहाड़ी राज्यों में भी स्थिति ठीक नहीं है। हिमाचल प्रदेश में इस बार सूखे के कारण काफी नुकसान पहुंचा है। वहां के किसान अपनी खेती में समय से काम नहीं कर सके। फल उत्पादों को खासकर के सेब उत्पाद को कम बारिश के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि सेब की फसल पर प्रदेश की आर्थिकी पर सीधा-सीधा असर पड़ता है। इस बार सेब की कम पैदावार आंकी जा रही है। इसी तरह पिछले 10-12 दिनों से कुछ जिलों में अधिक वर्षा के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में पूरे के पूरे पहाड़ खिसक रहे हैं, जिसके कारण सड़कों पर आवाजाही अवरुद्ध हुई है तथा कई स्थानों पर बहुमूल्य जानें भी गई हैं।

हर वर्ष बादल फटने से खासकर के पहाड़ी राज्यों में जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, कश्मीर व उत्तरी पूर्व के राज्यों में भूस्खलन की घटनाओं से लोगों को अधिक नुकसान झेलना पड़ता है।

---

* Laid on the Table

मेरी सरकार से मांग है कि सूखे व बाढ़ की स्थिति के लिए ठोस नीति बनानी चाहिए और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भी इस प्रकार के इन्तजामात करने चाहिए, ताकि अधिक वर्षा के कारण नुकसान कम हो।

सूखे की स्थिति से निपटने के लिए नदियों का पानी आपस में जोड़कर विभाजन किया जा सकता है जिसके लिए नदियों को जोड़ने की प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए। हमें अपने देश की उचित जल नीति बनाने पर ठोस निर्णय लेना चाहिए। यह बात ठीक है कि हमारे सीमित साधन हैं, परन्तु कहीं तो शुरुआत करनी ही होगी। यदि छोटी-छोटी परियोजनाओं पर हम बल देंगे तो बाढ़ें भी रुक सकती हैं और वह इकट्ठा किया गया पानी सूखे की स्थिति में किसानों के खेतों में प्रयोग किया जा सकता है। सरकार ने हाल ही में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की है वह स्वागत योग्य है। हमें अवश्य ही इस योजना को अधिकाधिक ध्यान देकर किसानों के हित में बनाना चाहिए।

गत दिनों हिमाचल प्रदेश में गर्मी के समय गंभीर सूखे को झेलना पड़ा है। हमारी पीने व सिंचाई की कुल 9590 योजनाओं में से 1459 बन्द हो चुकी हैं जिसके कारण 5048 गावों को इसका नुकसान झेलना पड़ा। कुल जनसंख्या, लगभग 716390 इसी सूखे कारण प्रभावित हुई है और इसी तरह आजकल अधिक वर्षा के कारण भी हमारी पीने के पानी व सिंचाई की 536 योजनाओं को नुकसान पहुंचा है। देखा जाये तो सारा प्रदेश ही इस वर्षा के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

मेरा सरकार से निवेदन है कि पहाड़ी राज्यों के लिए अन्य राज्यों से हटकर इस प्रकार के प्राकृतिक प्रकोपों के लिए विशेष पैकेज की कोई व्यवस्था होनी चाहिए और जो प्रभावित लोगों को नुकसान होता है उसके मुआवजे अपेक्षाकृत बढ़ोत्तरी करने की आवश्यकता है। (इति)

*SHRI NALIN KUMAR KATEEL (DAKSHINA KANNADA):

*Laid on the Table

*SHRI RAMESHWAR TELI (DIBRUGARH): Hon'ble Madam Speaker, I thank you for giving me an opportunity to speak on flood problem. Assam has been suffering from the problems of flood for the past several decades. Lakhs of people are seriously affected by flood and erosion every year. The mighty river Brahmaputra and its tributaries create havoc. Apart from the houses and business establishments a number of roads, embankments and other infrastructures are severely damaged and crops and cattle worth several crores are destroyed in flood. Recurring floods over the years have damaged our agrarian economy putting a stumbling block in the development of our state. Annihilation of thousands of villages and cultivable land have brought untold miseries to our people. Erosion and flood have seriously affected the world famous river island Majuli.

I therefore, would like to request the central government to take appropriate measures to address the problem of flood and erosion in Assam. Only the effort of the Central Government would provide the much needed succour to this flood ravaged state. (ends)

---

*Laid on the Table

1643 बजे

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब): महोदय, आज अंडर रूल 193 बाढ़ पर चर्चा हो रही है। मैं समझता हूं कि हर वर्ष मानसून सैशन में वर्षा होती है। अपनी-अपनी कहानी सुनाकर हम चले जाते हैं और नतीजा वही रहता है। यह सच है कि कहीं बाढ़ है, तो कहीं सूखा है। बहुत से सदस्यों ने इस संबंध में अपनी बात रखी। बिहार से हमारी बहन, महिला सदस्य सूखे की बात सुना रही थीं। मुझे एक कहानी याद आ गई। हमारे पंजाब में कहते हैं कि किसी की दो बेटियां थीं। एक की किसान के बेटे से शादी हो गई, उसने मक्का बोया हुआ था। दूसरी की कुम्हार के बेटे से शादी हो गई, उसने मिट्टी के बर्तन बनाए हुए थे। पहलवान जी जैसे किसी व्यक्ति ने पूछा कि बाबा क्या हाल है? वह कहता है कि आज या तो टांड्या वाली नहीं है या भांड्या वाली नहीं है। इस देश में कहीं डूबा है, कहीं सूखा है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस गंभीर विषय पर चर्चा हो, क्योंकि इसका सीधा संबंध कृषि से है। नेचुरल कैलेमेटी का ज्यादा असर कृषि पर पड़ता है या पेंडू क्षेत्र पर पड़ता है। हमारे सामने चैलेंज हैं, जल संकट है, जल मैनेजमेंट पानी को संभालने का संकट है, उस पर विशेष तौर पर चर्चा होनी चाहिए। सबसे बड़ी चिंता है कि हमारे रिजर्वायर में पानी कम हो रहा है।

(1645/NK/RCP)

भाखड़ा डैम में पानी कम हो रहा है, पोंग डैम में पानी कम हो रहा है, जल स्तर नीचे जा रहा है। हमारी धरती का पानी नीचे जा रहा है। साठ परसेंट बारिश का पानी खराब हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। यह हमारे और सभी के लिए चिंता की बात है। इस पर गंभीरता से चर्चा करके इसका उपाय सोचना चाहिए। आज चर्चा हो रही है

कि हमारे सामने क्या मुश्किलें हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कम्पनशेसन की राशि 3500 रुपये प्रति एकड़ बहुत पुरानी है जबकि फसल बुआई के समय दस हजार रुपये प्रति एकड़ खर्च हो जाता है, कम से कम दस हजार रुपये से ज्यादा प्रति एकड़ होना चाहिए। पन्द्रह सौ रुपये बादल साहब सरकार ने बढ़ाए थे, यह बहुत कम है। नार्म्स ऐसे हैं, जो फुलफिल नहीं होते, ये पन्द्रह दिन में रिपोर्ट मांगते हैं। जब बाढ़ आई होती है, रिपोर्ट नहीं दी जाती। ये कहते हैं कि रिपोर्ट टाइम पर नहीं आई, उनको सहायता नहीं मिलती, नार्म्स भी ठीक करने हैं। जो हिल स्टेट के नीचे स्टेट हैं, उनको स्पेशल पैकेज देना चाहिए। मेरी कंस्टीट्यूएंसी आनंदपुर साहिब हिल स्टेट के नीचे आता है, पंजाब भी नीचे आती है। हिमाचल प्रदेश ने समाह नदी को चैनलाइज किया और इसे पंजाब की सरहद पर छोड़ दिया। वहां सरकार बदल गई, जब धूमल साहब की सरकार थी, तब उन्होंने चैनलाइज किया था। वीरभद्र सिंह की सरकार आई, उन्होंने बंद कर दिया। हिमाचल प्रदेश से छोड़ा हुआ पानी पंजाब के हिस्से में आ जाता है, जिससे हमारे यहां बाढ़ आ जाती है। इससे बहुत नुकसान होता है। ऐसे बहुत सारे इंटर-स्टेट इश्यूज हैं। पंजाब में संगरूर डिस्ट्रिक्ट में घग्घर दरिया है। वहां 137 करोड़ रुपये की लागत से फर्स्ट फेज को चैनलाइज किया, जब दूसरा फेज शुरू करने लगे तो सीडब्ल्यूसी ने बंद करा दिया। पंजाब के हिस्से में पानी रुक जाता है क्योंकि हरियाणा में चैनलाइज नहीं करने दिया। इंटर-स्टेट डिस्पयूट चाहे समाह नदी हो या घग्घर दरिया को चैनलाइज करने का हो, एक-दो इश्यूज हैं। मैं इसका उपाय बताना चाहता हूं। चैक डैम बहुत जरूरी है। रेल मंत्री जी ने मैट्रो गुड्स ट्रेन के लिए कहा है कि जापान से एक लाख दस हजार करोड़ रुपये 0.1 % ब्याज पर मिल सकता है। जब

इतना पैसा बिना ब्याज के मिल सकता है तो चैक डैम के लिए लें। इससे हमारे देश की मुश्किलें ही खत्म हो सकती हैं। रावी नदी का पानी पाकिस्तान को जा रहा है। पंजाब और हरियाणा में लड़ाई हो रही है और हमारा पानी पाकिस्तान को जा रहा है। चेक डैम या डैम हैं, चेक डैम को डिसेन्टरिंग करने के लिए कोई उपाय नहीं है। उसे माइनिंग वाले रोक देते हैं, फॉरेस्ट वाले रोक देते हैं। इसलिए माइनिंग और फॉरेस्ट कृषि क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। कम से कम वाटर रिर्सोसेज मंत्रालय में फ्री होना चाहिए, माइनिंग वालों को डिसेन्टरिंग के लिए नहीं रोकना चाहिए।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के लिए बधाई देना चाहता हूं। पहले एक ब्लॉक को इकाई माना जाता था, अब इन्होंने गांव को इकाई बना दिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन एक गांव को इकाई नहीं बनाया जा सकता, यह सच है। आप भी गांव से आते हैं। गांव के एक हिस्से में नुकसान हो जाता है और दूसरा हिस्सा बच जाता है। ये कहते हैं कि सारे गांव का परसेंटेज लेना है। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में एक फार्मर को इकाई बनाना चाहिए नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं होता। हमने आज तक का रिकार्ड देखा, आप महाराष्ट्र का भी जानते हैं। पंजाब में इस स्कीम को लागू ही नहीं किया, हरियाणा का हमने देखा है। जो कंपनियां हैं वे पैसा कमा रही हैं। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के लिए कोई निगम बनाया जाए, कॉरपोरेशन बनाई जाए। जो कॉरपोरेशन का प्रोफिट होगा, एक रिवाइज्ड स्कीम लाने जा रहे हैं, जो उसका प्रोफिट होगा, एमएसपी का गैप और एक्चुअल प्राइस का गैप होगा, उस पैसे को वहां यूज किया जा सकता है। गांवों की सड़कों के लिए यूज किया जा सकता है। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना को इफेक्टिव तौर पर लाने की जरूरत है ताकि

किसानों को कुदरती आपदा से बचाया जा सके। आज देश और देश की सरकार को सबसे ज्यादा पानी के संकट को संभालने और जल संकट को हल करने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए।

(इति)

(1650/SK/SMN)

1650 बजे

श्री मधुकरराव यशवंतराव कुकडे (भंडारा-गोंदिया): महोदय, मैं नियम 193 के अंतर्गत चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। भंडारा गोंदिया जिले में गोसीखुर्द परियोजना जिसका नाम इंदिरा सागर प्रोजेक्ट है, 1986 में शुरु की गई थी। मैं चुनाव जीता हूं। अभी मध्यावधि चुनाव 28 मई को हुए, हमारा दुर्भाग्य है, यहां के 22 गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। पहली बार परियोजना को पूरा न किए जाने के कारण सरकार से नाराज़ होकर लोगों ने बहिष्कार किया। उनको सुविधा नहीं मिली, उन गांवों में किसानों को सिंचाई का पैकेज भी नहीं मिला, यहां प्लाटों का आबंटन नहीं किया गया, उनको जो सुविधाएं चाहिए थीं, सरकार द्वारा न देने की वजह से 22 गांव के लोगों ने आजादी के बाद पहली बार चुनाव का बहिष्कार किया है, यह निंदनीय बात है।

महोदय, आजादी को 70 साल हो गए हैं, लेकिन कभी भी यहां के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया था। गोसीखुर्द योजना जो इंदिरा गांधी जी के नाम पर है, 1986 में शुरु हुई थी, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है। इससे खेती का नुकसान हो रहा है, लेकिन इस तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस योजना को जल्द से जल्द पूरा करें। अब हम जवानी से बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इस बार यहां के लोगों, किसानों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। यहां फसल खत्म हो गई है, यहां किसानों के पास खेती नाम की कोई चीज नहीं है। इन लोगों के पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। इन 22

गांव के लोगों के लिए, युवकों के लिए सरकार काम की शुरुआत करे ताकि ये भविष्य में चुनाव का बहिष्कार न करें।

महोदय इसी साल बावनथड़ी परियोजना के कारण 12 गांव के लोगों ने बहिष्कार किया था। उनको भी खेती के लिए पानी चाहिए। बावनथड़ी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में पानी न मिलने के कारण खेती सूख रही है। यही कारण है कि वहां के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया। आजादी के बाद अगर ऐसा होता है तो यह देश के हित में नहीं है। उनकी इतनी ही डिमांड है कि बावनथड़ी परियोजना के तहत पानी कैनाल के माध्यम से चांदपुर जिले से छोड़ा जाए। इससे इलैक्ट्रिसिटी की बचत होगी और इन गांवों में किसानों को पानी मिल सकेगा। सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इन 12 गांव के किसानों के हित में काम करे।

1652 बजे (माननीय उपाध्यक्ष <u>पीठासीन हुए</u>)

यहां वेनगंगा नदी का पानी शुद्ध है। नागपुर का गंदा पानी मिलने के कारण हमारे यहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। यहां कई बीमारियां फैल रही हैं। नागपुर जिले का गंदा पानी वेनगंगा में आने के कारण भंडारा के जिला मुख्यालय और 32 गांव के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। यह पानी जानवर तक नहीं पी सकते हैं। यहां पानी का अथाह प्रवाह है, लेकिन यह पानी नहीं पी सकते हैं। इस पानी से बीमारियां हो रही हैं। अल्सर, अपेंडिक्स, पीलिया आदि बीमारियां हो रही हैं। अगर यहां शुद्ध पानी आ जाए तो भंडारा के लोगों को पीने का पानी मिल सकता है। इस तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आजादी के 70 साल बाद भी अगर किसी व्यक्ति को शुद्ध पानी नहीं मिलता है तो यह देश में गुलामी का द्योतक है।

वेनगंगा नदी से रात भर रेत निकाली जाती है, कोई अधिकारी इसे नहीं रोकता है। भंडारा जिले में बावनथड़ी में से रेत निकाली जाती है, इस कारण बोरवैल का पानी नीचे चला गया है, किसानों को पानी मिलने में तकलीफ हो रही है। भंडारा जिले में तिरोड़ा और कुछ अन्य तालुका प्रभावित हो रहे हैं। यहां सूखा पड़ रहा है। यहां अथाह पानी होने के बावजूद और सरकार की तरफ से नियोजन न होने से भंडारा जिले में पानी की कमी हो रही है। इस तरफ केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए।

वन विभाग के नियम के अनुसार भंडारा जिले में कई परियोजनाएं रुकी हुई हैं, इसे पूरा नहीं कर सकते हैं। यहां जंगल पैदा हुए हैं, यह भंडारा गोंदिया जिले के लोगों की गलती नहीं है। परियोजना के अंतर्गत 13 तालाब बन चुके थे, लेकिन कैनाल नहीं निकाली गई। इन तालाबों को 1984 में पूरा किया गया था। वन विभाग के नियम के अनुसार कैनाल नहीं निकलने से किसानों को पानी मिलना बंद हो गया है।

(1655/RPS/MMN)

सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि पूरे भंडारा-गोंदिया जिले में पैडी की फसल होती है और पैडी को पानी की आवश्यकता होती है। अगर वहां पानी की सिंचाई व्यवस्था न हो और डैम न बनाए जाएं तो हमारे किसानों का अहित हो जाएगा। वेनगंगा नदी के पास में, रोहा और मुंडरी गांव के अंदर सरकार को बैराज बनाने चाहिए, जिससे तुमसर तालुका, मोआड़ी तालुका और बालाघाट जिले के लोगों को पानी की उपलब्धता होगी। वेनगंगा नदी बालाघाट जिले और भंडारा जिले के लिए जीवनदायी योजना है। दोनों जिलों के किसानों को उसके पानी से फायदा मिलता है, इसलिए

सरकार को भंडारा-गोंदिया जिले की जितनी भी परियोजनाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए काम करना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, उनको सिंचाई की सुविधा ही नहीं हैं, जैसे रोंघा गांव है। जिन आदिवासी गांवों की जमीन ली गई है, वे कम दाम में ली गई हैं। उनकी जमीन कम दाम में लिए जाने के कारण, वहां के किसान सरकार के खिलाफ हैं और उनका विकास नहीं हो रहा है। जब बावातड़ी योजना बन रही थी, तब हमने डिमाण्ड की थी, तब कहा गया था कि उन लोगों के लिए नौकरी का प्रावधान किया जाएगा, हम उनके जीवन-उद्धार के लिए काम करेंगे, लेकिन सरकार ऐसा कोई काम नहीं कर रही है। इसलिए लोगों के मन में हमारे बारे में असंतोष का निर्माण हुआ है, जनप्रतिनिधियों का वहां घूमना बन्द हुआ है। जिन गांवों के लोगों ने बहिष्कार किया था, उनकी क्या डिमाण्ड थी? उनकी डिमाण्ड इतनी ही थी कि उनको वह मुआवजा मिल जाए, जो सरकार ने घोषित किया था। 80 हजार रुपये प्रति परिवार देने की बात हुई थी, लेकिन वह अभी तक नहीं दिया गया है। हर परिवार को मकान के लिए जमीन दी जानी चाहिए। परिवार अर्थात पति, पत्नी और बच्चा। जिनकी शादी हो गई है, उनको अलग जमीन देनी चाहिए। उन लोगों को खेती का मूल्य बहुत कम मिला है। वर्ष 2014 के पहले मूल्य कम थे और वर्ष 2014 के बाद मूल्य बढ़ चुके हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उनकी जमीनों का उचित मूल्य दिया जाए। आज दो लाख रुपये में एक एकड़ जमीन नहीं मिलती है। आज किसान भूमिहीन हो गए हैं। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो हमारा भंडारा-गोंदिया जिला, जो नक्सल प्रभावित है, वहां और नक्सलवादी पैदा होंगे और जिले का विकास रुक जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र की कई योजनाएं हैं, उनके लिए हमारा नियोजन न होने से हम कठिन संकट में पड़े हुए हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप पूरे नियोजन पर ध्यान दें और लोकल लेवल पर प्लान करें। केन्द्र सरकार भंडारा जिले को आर्थिक सहायता प्रदान करने में सहकार करे।

HON. DEPUTY SPEAKER: Please conclude.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): Sir, it is his maiden speech.

HON. DEPUTY SPEAKER: Maiden speech means how long will he speak? Is one hour all right?

श्री मधुकरराव यशवंतराव कुकडे (भंडारा-गोंदिया): मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि धांपेवाड़ा-1 का काम चालू हुआ है, लेकिन टप्पा-2 योजना, अभी तक आर्थिक मदद न मिलने से और फाइनेंशियल क्राइसिस होने की वजह से, धांपेवाड़ा परियोजना हम शुरू नहीं कर सके हैं। अगर धांपेवाड़ा परियोजना शुरू कर दी जाए तो भंडारा-गोंदिया जिले के सभी किसानों को पानी मिलेगा और वहां के किसान कभी आत्महत्या नहीं करेंगे। हमारे क्षेत्र में आत्महत्या होने के मूल कारण हैं - धान का उचित मूल्य न मिलना, उनको पानी न मिलना। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि टप्पा-2 योजना और धांपेवाड़ा योजना को आर्थिक सहायता मिले और गुढरी योजना जो वर्ष 1984 से चल रही है, उसे पूरा करने में आप सहकार करें।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं।

(इति)

HON. DEPUTY SPEAKER: He has finished his maiden speech now.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): We all have to appreciate the maiden speech.

* SHRIMATI POONAMBEN MAADAM (JAMNAGAR):

*Laid on the Table

* SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMARAJANAGAR):

---

*Laid on the Table

* SHRIMATI V. SATHYABAMA (TIRUPPUR):

---

*Laid on the Table

1659 hours

SHRI PRATAP SIMHA (MYSORE): Thank you Deputy Speaker, Sir, for giving me the opportunity to speak on a very important subject.

When the entire South Karnataka is reeling under flood and heavy rains, I am grateful to you because I wanted you to be on the Chair when I speak about this subject.

HON. DEPUTY SPEAKER: Very good.

SHRI PRATAP SIMHA (MYSORE): It is because the people of Tamil Nadu and the actors of Tamil Nadu should be grateful to the people of my constituency, Coorg where Cauvery takes her birth. The main tributaries of Cauvery are Harangi, Kabini, Hemavati and Lakshmana Tirtha. This time because of heavy rains, all the four dams are full. Sir, you are getting more than 50,000 cusecs of water every day.

HON. DEPUTY SPEAKER: Otherwise, you would not release a single drop. If it is not full, you would not release even a single drop.

SHRI PRATAP SIMHA (MYSORE): Even the Mettur dam is full. The people of Tamil Nadu should be grateful to my people.

HON. DEPUTY SPEAKER: It is not to them but it is to the Heaven, God, Varuna Bhagavan. Varuna Bhagavan is coming with you now.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): It is all because of the BJP Government that the God is also happy today.

(1700/VR/ASA)

HON. DEPUTY SPEAKER: It is because of Ananthkumar that God *Varuna* has given a lot of water to your State.

… (*Interruptions*)

SHRI PRATAP SIMHA (MYSORE): Sir, I am also grateful to Shri Ananthkumar ji. He has given me an opportunity to participate in this important debate.

Sir, I have a little daughter who goes to first standard. Every day when she comes back in the evening, she hums the rhyme – “Rain, rain, go away, come again another day. Rain, rain, go away, little Jony wants to play.” It is because of her syllabus that she hums these rhymes in her school also. But the people of Coorg never hum these rhymes because there are no rains. When it rains in Coorg, it rains heavily. When it rains in Coorg, it washes away the roads. When it rains in Coorg, it takes away the important crops of coffee and pepper. Sir, almost 30 per cent of the total coffee produced in Karnataka is produced in Coorg. Similarly, 15 per cent of the total pepper produced in Karnataka is produced only in Coorg. This time because of heavy rains, the entire road network is damaged. Even the national highways are not motorable.

Sir, we were expecting a good relief package from the State Government. But we did not get it. I am really hopeful that Modi ji's Government will certainly pay heed to our demands and help us because Modi ji's Government has a track record of helping all the States when it is necessary.

Sir, I will read out some of the headlines, which appeared in the newspapers in the last two months, just to apprise the House with the situation prevailing in Coorg in Karnataka. 'Catchment Areas of Cauvery Receiving Good Rains' published on May, 28. On 29 May, the entire Mangalore city was flooded because of heavy rains. On May 30, the headline of a newspaper was '3 Dead, 100 Rescued after Record Rainfall in Karnataka'. Then, 'Rain Causes Heavy Damages to Paddy and Seedling in Kodagu' appeared in one newspaper. 'Flood Alert in Catchment Areas' and 'More Rain Likely in Cauvery Area' are some other headlines. Moreover, Sir, power supply is completely cut off in Coorg and in other parts of Karnataka.

Sir, a few hon. Members like Shri Venugopal, Shri Karunakaran and Shri Kalyan Banerjee were pointing fingers at the Central Government. Hon. Member, Shri Venugopal was folding his hands before the Government requesting them to give a special package to

his State Kerala. Sir, Venugopal ji is in charge, the General Secretary of All India Congress Committee of Karnataka for last two years. His party is in rule in Karnataka for the last five years. Now, even after getting rejected by the people of Karnataka, they have come back to power. *…(Interruptions)… (Not recorded)*

What did they do in the last five years? … (*Interruptions*) What did they do for my constituency, Kodagu? … (*Interruptions*) Did they ever give even a small package to Coorg? … (*Interruptions*) When the BJP Government was in power in Karnataka, they sanctioned about Rs.1800 crore work projects to Coorg. … (*Interruptions*) But under the five years of Congress rule, we got only Rs.300 crore and that too only 50 per cent of the money was released. It is only because of a non-functional Congress Government in the State that Coorg is suffering. … (*Interruptions*)

Sir, it is not a political speech. The entire Coorg, South Kanara, North Kanara, Chikmagalur, Sakleshpur and other districts are reeling under heavy rains. It is only in Belgaum district that 978 houses have got damaged, 22 cattles have died and 11 human beings have lost their lives. In Bidar also, 168 houses have been

damaged and 8 persons have died. The numbers that I am reading are only of a few districts.

(1705/SAN/RAJ)

In Chamarajanagar, which is being represented by Shri Dhruvanarayana, 157 houses have been damaged and two deaths have taken place. In Dakshin Kannada, 957 houses have been damaged and nine deaths have taken place. In Dharwad, 737 houses have been damaged and six deaths have taken place. In Gadag, 505 houses have been damaged and six deaths have taken place. In Madikeri, 200 houses have been damaged and one death has taken place. In Koppal, 1,239 houses have been damaged and three deaths have taken place. In Mysuru, 313 houses have been damaged and three deaths have taken place. A total of 9,163 houses have been damaged and 130 deaths have taken place. The total number of cattle deaths is 727. Yet an amount of Rs. 187 crore has been lying with respective District Commissioner Offices. It is because of the non-functional Government in Karnataka which is being supported, and actively involved in, by Congress.

The *… (Not recorded)* is saying 'Everyday, I am *… (Not recorded)* … (*Interruptions*) He is *… (Not recorded)* only to stay in power and the *… (Not recorded)* him to extract more power and more Cabinet berths. … (*Interruptions*) This is the actual state of Karnataka. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: *… (Not recorded)* and that kind of words will not go on record.

… (*Interruptions*)

SHRI PRATAP SIMHA (MYSORE): Sir, now I come to the assistance given by the Central Government under Modiji. … (*Interruptions*)

Sir, I will come to that point. … (*Interruptions*) When 3,000 farmers committed suicide under *… (Not recorded)*, where was Shri Venugopal hiding? … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Do not put the names on record.

… (*Interruptions*)

SHRI PRATAP SIMHA (MYSORE): Why did he not go to the Chief Minister and apprise him? Here, he comes and shouts at the Central Government. … (*Interruptions*)

Sir, I tell you the exact figures. Under the ten years of UPA Government from 2004 to 2014, they gave Rs. 3,579.86 crore under NDRC and Rs. 1,063.47 crore under SDRF. The total money given in four years was Rs. 4,822 crore. Under four years of Modiji's rule, the Central Government gave Rs. 5,122 crore under NDRF and Rs. 799.99 crore under SDRF. The total amount given is Rs. 5,922 crore, which is almost Rs. 6,000 crore, in four years. They had given Rs. 4,500 crore in ten years of rule, and these people are coming and preaching us.

The person, who spoke a lot about the Central Government and the discrimination, Shri Venugopal, is not in the House. In his absence, or in his presence in the Parliament's Central Hall, I am telling this.

HON. DEPUTY SPEAKER: Please conclude.

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Sir, he speaks rarely. He is a young Member and speaking very well. Our Party has time. Please give him time from our Party's time. … (*Interruptions*)

SHRI PRATAP SIMHA (MYSORE): Sir, I had encountered all these representatives during the all-party meeting on Cauvery River. Every time, they would come and demand that they want this much of water from the Cauvery.

When Coorg is reeling under heavy rains, they do not raise their voices. This is the saddest part of Members of Parliament and some of the representatives. For the last four years, I have been demanding a special package for Coorg from the Karnataka State Government. I requested the Chief Minister to include the special package in the annual Budget, but he did not pay heed to it.

I also requested the Chief Minister to visit Coorg during Cauvery Tula Sankramana. Due to heavy rains, we have suffered the losses. We have suffered the damages. We suffered crop losses of coffee, pepper, cardamom and areca nut. Yet, we go and offer puja to Cauvery Mata and Lord Igguthappa, but the Chief Minister of Karnataka did not come. This time, I also request the Chief Minister of Tamil Nadu to come for Cauvery Tula Sankramana. I also request the Members of the Congress Party, at least, this time – I had requested the previous Chief Minister – to visit. This time, I am again requesting you, through this House, to

visit and pay respect to Cauvery Mata, who gives everything to Karnataka.

(1710/RBN/IND)

Half of Karnataka's total population is fed by river Cauvery. Should we not be grateful to river Cauvery? Instead of pointing fingers at the Central Government, I request the Members of the Congress to ask their Chief Minister to come with a delegation to the Centre. Our Ananth Kumar ji is here. He has taken care of the needs and concerns of the Karnataka State. When the coal block was cancelled by the Supreme Court, it was Shri Ananth Kumar who was instrumental in getting the coal block which is situated in Maharashtra. When we came to power at the Centre, the total length of national highways in Karnataka was 6,000 kms. Under four years of Shri Narendra Modi's rule, now the total length of national highways is 13,500 kms. This shows the love and affection that Modi ji has got for the people of Karnataka.

I request the Karnataka Chief Minister, through our Congress Members, to come with a delegation. We are there to help you. We will certainly help you. We will stand by the people of Karnataka.

Finally, I would request the Minister to bring some changes in the NDRF guidelines. If a house is completely damaged or gets collapsed because of heavy rains, the maximum amount one can give for a family is Rs. 1 lakh only. With Rs. 1 lakh you cannot build a house or re-construct a house. You will have to bring changes in the NDRF norms and Calamity Relief Fund norms. That is the small request I have. It will help the people at large across the nation.

Thank you for giving me this opportunity to speak in this House. This is the second time I got the opportunity to speak in the last four years. I am also thankful to our leader Shri Ananth Kumar. Thank you Sir.

(ends)

1713 बजे

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : महोदय, गुजरात के कच्छ के लिए सौराष्ट्र में सरदार सरोवर और नर्मदा नदी की बात है और इस परियोजना पर 22 हजार करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं और इसके परिणाम के बारे में सरकार को पता है। गुजरात के बारे में हमने आपको एक लाइन बताई है। कच्छ की स्थिति को सुधारने के लिए 22 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए। हरिद्वार और ऋषिकेश की स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं। अभी तक 22 साधु आत्महत्या कर चुके हैं और वहां की नदियों की स्थिति आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नदियों की क्या स्थिति है। नदियों को जोड़ने की क्या स्थिति है और जोहड़ जोड़ने की क्या स्थिति है? मैं गृह मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि यही सही दिशा है, सही वक्त है कि कर्तव्य और प्राथमिकता को तय करना होगा। आज पहली प्राथमिकता और कर्तव्य पानी है, लेकिन पूरा विश्व 'प' से परमाणु और 'प' से पानी के लिए विश्व युद्ध की स्थिति में पहुंच चुका है और इसी दो 'प' तक सिमट चुका है। पूरी दुनिया में 71 प्रतिशत पानी बचा हुआ है, जिसमें से केवल एक प्रतिशत पानी खेती, कपड़ा और पीने योग्य है। पानी पर गंभीरता क्यों नहीं दिखाई जाती है? कृषि मंत्री जी बिहार से हैं और उन्हें मंत्री बने पांचवां साल चल रहा है। इस साल आपकी उम्र 72 साल हो गई है, शायद 75 साल की उम्र में अगला चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसका पता नहीं है। …(व्यवधान) मेरा आग्रह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा नदियां बिहार में हैं – गंगा, कोसी, गंडक, कमला, महानंदा, बलान आदि लेकिन 17 नदियों से जोड़ने वाली बात अभी नहीं हो पाई है। मैं भी उस समय मंच पर था, जब नीतीश कुमार जी ने फरक्का बैराज को खत्म करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब तक

फरक्का बैराज को खत्म नहीं करेंगे, तब तक उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी रहेगी।

(1715/vb/ak)

आप याद कीजिए, श्री नीतीश कुमार जी ने एक और बात आपसे कही थी कि कोसी बैराज़ का चौड़ीकरण करना होगा अन्यथा इसके दुष्परिणाम होंगे। कोसी एक विशाल नदी है। इसके कारण उत्तरी बिहार का तीन-चौथाई हिस्सा बाढ़ की चपेट में रहता है। नेपाल की स्थिति सबसे बुरी होती है। 70 वर्षों में मात्र 25 से 30 प्रतिशत पैसे ही ठेकेदारों, माफियाओं और नेताओं ने वहाँ पर खर्च किये। वहाँ जितनी कम्पनियाँ आयीं, वे 80 प्रतिशत पैसे अपने घर लेकर चली गईं। हम चाहते हैं कि इसकी जाँच की जाए। वहाँ जो भी मंत्री रहे हैं, इसकी जाँच हो।

माननीय कृषि मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी, मैं आपका ध्यान महानन्दा बेसिन की ओर दिलाना चाहूँगा। यह बेसिन सबसे ज्यादा बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति पैदा करता है, जिसके कारण किशनगंज, अररिया, सुपौल और कटिहार प्रभावित होते हैं। एक लम्बी लड़ाई के बाद भी आज तक हम लोग महानन्दा बेसिन के लिए कुछ नहीं कर सके हैं।

बिहार का लगभग आधा क्षेत्र टाल और दियरा के इलाके हैं। श्री नीतीश कुमार जी ने माननीय प्रधान मंत्री जी से आग्रह किया था कि बिहार के टाल और दियरा इलाके के किसानों और मजदूरों की स्थिति बदतर है। हम लोगों ने इस संबंध में आपसे कई बार चर्चा की। आपको आश्चर्य होगा, वर्ष 1987-88 में 19.5 प्रतिशत जंगल थे, लेकिन आज मात्र आठ प्रतिशत ही जंगल बचे हैं।

पूंजीपतियों, माफियाओं और उद्योगपतियों की मिलीभगत से आज पूरे देश में वन क्षेत्र की स्थिति बुरी है। आदिवासियों के जीवन के साथ ही जल और जंगल को सुरक्षित और संरक्षित रखा जाता था। जब उनसे जल और जंगल छीन लिये गये, तो ये कैसे बचेंगे? आदिवासियों की दुर्लभ प्रजातियाँ प्रतिदिन विलुप्त होती जा रही हैं। आने वाले 25 वर्षों में मात्र 10 प्रतिशत आदिवासी प्रजातियाँ ही नदियों के किनारे बचेंगी। विश्व के विभिन्न देशों में इनकी जनसंख्या 17-18 हजार के आसपास है।

हम लोग प्रत्येक वर्ष बाढ़ और सुखाड़ के विषय पर इस सदन में चर्चा करते हैं। बिहार के 18 जिले सुखाड़ से प्रभावित हैं। आप अनुदान और किसान बीमा योजना की बात करते हैं, लेकिन यह योजना निजी कम्पनियों को ज्यादा लाभ दे रही हैं। किसानों को कहाँ से लाभ दिये जा रहे हैं? हिन्दुस्तान में अब किसान बचे ही कितने हैं?

आपसे मेरा आग्रह तीन-चार मुद्दों के संबंध में है। पहला, कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। जब हमारे प्रधान मंत्री जी क्रांतिकारी निर्णय लेते हैं, तो वे एक निर्णय कृषि को उद्योग का दर्जा देने के संबंध में भी लें। दूसरा, बंटाईदारों को भी किसानों की श्रेणी में जोड़ा जाए अन्यथा बंटाईदार दिहाड़ी मजदूर मिट जाएंगे। तीसरा, नदियों को जोड़ने के साथ ही, नहरों और बोरिंग पर सबसे अधिक खर्च करने की आवश्यकता है। बिहार में बोरिंग नगण्य है। इसके कारण सिंचाई की स्थिति बहुत ही खराब है।

बिहार और उत्तर प्रदेश, ये दोनों राज्य नेपाल से सटे हैं। नेपाल से आने वाली नदियाँ हमारी जिन्दगियों को नासूर बनाती हैं। पहले ये वरदान साबित होती थीं। मैं आग्रह करूँगा कि प्रधान मंत्री जी की जो क्रांतिकारी योजनाएँ हैं, प्राथमिकता के आधार पर किसानों को उनके लाभ मिलें। इसके साथ ही, बिहार के लिए स्पेशल पैकेज दिया

जाए। विशेष राज्य के दर्जे के बारे में मैं नहीं कहूँगा। लेकिन, कोसी, सीमांचल और मगध के क्षेत्रों के लिए स्पेशल पैकेज के रूप में राशि प्रदान करें। भोजपुर के वे इलाके, जो उत्तर प्रदेश से सटे हैं, उनकी सहायता के लिए श्री नीतीश कुमार जी ने एक कमेटी बनाई है तथा इस संबंध में केन्द्र सरकार को पत्र भेजा है।

सभी नदियों से गाद निकालना आवश्यक है। नेताओं, माफियाओं और अपराधियों के द्वारा 70 वर्षों में खर्च होने वाली राशि हड़प ली गई। इस दिशा में कोई काम न होने के कारण नदियाँ ऊँची हो गईं और गाँव नीचे चले गये। यह बाढ़ का सबसे बड़ा कारण है। मैं बिहार को तत्काल सूखाग्रस्त घोषित करने की माँग करता हूँ।

(इति)

* SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA (TUMKUR):

---

*Laid on the Table

* SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR):

---

*Laid on the Table

*SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA (NIZAMABAD): Respected Sir, in the last four years of my tenure as a Member of Parliament, I have seen this very same discussion happening in every Session of Parliament.

Unfortunately, not many steps have been taken by the Union government to arrest recurring floods in various states, nor any major steps to prevent drought prone conditions and save people from distress.

I believe Sir, if we can look at India as a single unit instead of looking at various states & boundaries and limitations, we can win over both flood & drought.

Hon'ble Sir, to prevent recurring floods in various states, I would like to make a suggestion. In our country, we are blessed with great rivers like Brahamaputra, Ganga, Godavari, Krishna, Cauvery etc. If we add all the water available to be utilised, a sad reality comes to our notice.

---

*Laid on the Table

Out of the total available water, 75,000 TMC of water is going waste into the oceans and seas. If we can calculate and design a Water Network of India, understand which rivers have excess water, then we can plan to redirect this excess water to the drought prone areas.

If this simple technique, can be adopted to distribute the water across the country in a uniform manner, we can make sure, we give water to the last acre in our country.

Regarding drought condition, I would like to put forward a suggestion Sir. Drought prone areas basically are a result of inaccessible geography sometimes due to very low rainfall.

When inaccessible geography leads to drought Sir, I am proud to state that our state of Telangana stood victorious over drought by adopting two methods. Reviving the aquifers, however small they are in a systematic manner will change the drought scenario to a great extent.

This we have successfully achieved in Telangana under a flagship program called “Mission Kakatiya”. For their programme, in the last 4 years Telangana Government has invested 10,000 crores

and revived 43,000 tanks. Bringing surface water from the nearest river, by means of well designed major and minor irrigation projects.

In Telangana in the last 4 years we have allocated and spent 25,000 crores for major and minor irrigation projects.

This gave a great result Sir, and many villages of Telangana which never saw water for irrigation in the last 60 years are today rejoicing. We are very proud and happy of our Telangana Government’s achievement.

In case of low rainfall, drought can be conquered by taking up long term measures Sir.

In Telangana Sir, our Government has taken up a huge program called “Haritha Haram”. Under this programme we designed to plant 230 crore sapplings in 5 years, starting from 2014-2019. We have given dedicated budget for this programme of 1000 crores, and have synergised with NREGS programme. This, Sir, I would proudly like to state, is the “third largest human effort” in the world to face drought.

I am confident, Sir, Telangana one day will get good quality rainfall every year and our farmers will benefit from the efforts of our Government of Telangana.

Lastly Sir, I would like to state that with a systematic approach, dedicated resources, synergy between centre and states, India can win over both flood and drought and lead the world in the field of Agriculture.

(ends)

***श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर):**

---

* Laid on the Table

* SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA):

---

*Laid on the Table

(1720/PC/SR)

1720 बजे

डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही गंभीर विषय - बाढ़ और सुखाड़ पर प्रतिवर्ष चर्चा होती है। हम इस विभीषिका से जूझते रहते हैं। इसमें जन और धन की भी काफी क्षति होती है। चूंकि मेरे पास समय का अभाव है, इसलिए मैं संक्षिप्त में सिर्फ दो-तीन सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहूंगा।

पहली बात यह है कि देश में पॉलिथिन का प्रयोग किसी भी तरीके से हो, उसे रोका जाए। इससे आज गांव की मिट्टी बर्बाद हो रही है। यह शहर का जहर अब गांव में भी पहुंच गया है। गांव में प्लास्टिक प्लेट, प्लास्टिक ग्लास जैसी प्लास्टिक की चीज़ों का धुआंधार प्रयोग हो रहा है। इसके दो दुष्परिणाम हैं। एक तो हम वॉटर परकोलेशन सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। दूसरा, लोगों को जो पेड़-पौधों से लगाव था और लोग जो पत्ते की प्लेट्स बनाते थे, आज उस इंडस्ट्री का संपूर्ण रूप से लोप हो चुका है।

जंगलों के संरक्षण में जो आदिवासी लोग लगे थे, जिनको पहले लाखों में रोजगार मिलता था, आज प्लास्टिक उद्योग के जन्म से वहां सब से बड़ा संकट पैदा हुआ है। वहां अब पत्ते की प्लेट्स बनना करीब-करीब बंद हो गया है। यदि हम इस दिशा में पहले करेंगे, तो इससे गांव, खेत-खलिहान मजबूत होंगे। मैं इस विषय के दूसरे पक्ष के बारे में कहना चाहूंगा। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। आजकल नहरों के पेट को बांधना, एक नया फैशन बन गया है। बड़े स्केल पर उसका कांक्रिटाइज़ेशन हो रहा है। जो बेड कांक्रिटाइज़ हो रहा है, उसका नतीजा यह है कि जिस नहर के किनारे पहले 25-30 फीट वॉटर लेवल था, आज वहां वाटर लेवल 200

फीट पर चला गया है। पता नहीं किस चिंतन के तहत आज नहरों को कांक्रिटाइज़ किया जा रहा है। इसमें पैसे का जो खर्चा हो रहा है, वह भी बर्बादी है। इससे वॉटर परकोलेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। इस पर सरकार को चिंतन करना चाहिए।

एक तरफ हम रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पर करोड़ों, अरबों रुपये खर्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ अवैज्ञानिक तरीके से हम नहरों के पेट को बांध रहे हैं। इस प्रकार वॉटर लेवल से वॉटर परकोलेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। यहां पर केरल और बिहार के बारे में चर्चा हुई कि ये राज्य बाढ़ के कारण बेकार हो रहे हैं। खासकर बिहार के 18 जिले सुखाड़ से प्रभावित हैं, जैसे जहानाबाद, गया, नवादा, औरंगाबाद, आदि।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): सर, ये 36 जिले हैं।

डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद): वहां 36 जिले प्रभावित हैं। लखीसराय, मुंगेर और बांका का सारा इलाका भीषण सुखाड़ की चपेट में है। आज वहां खेती की बात तो छोड़ दीजिए, बीजड़ा समाप्त हो गया।

माननीय उपाध्यक्ष: अब आप कन्क्लूड कीजिए।

डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद): मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। आज हमारे सामने पेयजल का संकट है। हमारे सामने एक गंभीर आपदा की स्थिति आ गई है। जो पहाड़ी इलाका है, वहां 200-250 और कहीं-कहीं 400 फीट पर भी पानी नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज किसानों और उनके खेत-खलिहानों को मजबूत करने की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर माननीय प्रधान मंत्री जी ने एम.एस.पी. लागू किया है। इससे किसान बचने लगा है, लेकिन वह स्वस्थ नहीं हो सकता है। गांव, खेत-खलिहान तब तक स्वस्थ नहीं होंगे, जब तक स्वामीनाथन के सी-2 फॉर्मूले से

व्हीट और पैडी का दाम लगभग तीन हजार रुपये तक तय नहीं किया जाएगा। इसलिए, आप सी-2 फॉर्मूले को लागू कर के गांव और खेत-खलिहान को मजबूत करें।

अन्य चीज़ों में भी लूट हो रही है। मनरेगा में खुली लूट हो रही है। इसके लिए सरकार ने कई प्रकार के प्रबंधन भी किए, लेकिन इसके बावजूद सिस्टम में टैम्परिंग हो जा रही है। बिचौलिए खा रहे हैं। यहां तक की हम खरीद के लिए जो दुकान खोलते हैं, वह भी जब किसान अपना सामान बेच लेता है, तब खुलती है। इस तरह पूरे सिस्टम की टैम्परिंग हो रही है। इसलिए, इसमें हम किसान को सीधे कैसे लाएं, इस बारे में सरकार को सोचना होगा। तेलंगाना अभी नवसृजित राज्य है। वहां किसानों के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है। हमें इसे मॉडल के रूप में लेना चाहिए। धन्यवाद।

(इति)

माननीय उपाध्यक्ष : श्री गोपाल शेट्टी।

(1725/GG/UB)

1725 बजे

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): उपाध्यक्ष महोदय, नियम-193 के अंतर्गत बाढ़ से प्रभावित समस्या का समाधान ढूंढने के लिए जो डिस्कशन हो रहा है, उस पर मैं अपनी बातों को रखने का प्रयास करूंगा। उपाध्यक्ष जी, मैं बहुत ही संक्षेप में अपने मुद्दे रखना चाहूंगा। देश में हर साल आने वाली बाढ़ से बहुत से राज्यों के लोग प्रभावित होते हैं। महाराष्ट्र में कुछ जिले बड़ी मात्रा में बाढ़ से प्रभावित हैं और इस कारण से 123 लोगों की मृत्यु हो गई है। उनके प्रति मैं सहानुभूति व्यक्त करता हूँ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेन्द्र फडनवीस जी जगह-जगह जन सेवा के माध्यम से तालाबों को खोदते हुए पानी बचाने का भी काम करते हैं, जिससे किसानों को आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर लाभ पहुंचेगा। मैं मनता हूँ कि जितना पानी यहां बचाएंगे, उतना समुंदर में कम जाएगा और उससे लोगों को थोड़ी राहत पहुंचेगी।

महोदय, मैं सीधे मुंबई शहर की अगर बात करूं तो मुंबई शहर एक अन-प्लान्ड सिटी है। पहले शहर बसा और उसके बाद डेवल्पमेंट प्लान आया। सन् 1967 में पहला प्लान आया, उसके बाद सन् 1991 में आया, उसके बाद सन् 2013 में आया और अब सन् 2018 में फाइनल डीपी हो रही है। लेकिन सन् 1967 में जो रोड, 44 फीट, 60 फीट और 90 फीट के बताए गए थे, ये सारे रोड अभी तक भी डेवल्प नहीं हुए है और रोड के डेवल्पमेंट फुल विड्थ में न होने की वजह से हम स्टार्म वॉटर ड्रेन नहीं बना पाए हैं और इससे मुंबई शहर के लोगों को हर साल परेशानी झेलनी पड़ती है।

उपाध्यक्ष महोदय, सन् 2005 में मुंबई में बड़े पैमाने पर बाढ़ आई, चितले समिति की नियुक्ति हुई, अरबों-खरबों रुपये नाले की दीवार, माने रिटेनिंग वॉल बनाने में लगाया गया। यह एक अच्छा काम हुआ है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। लेकिन हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, कमिश्नर, मुंबई शहर के महापौर होते हैं, उन्होंने नाला डीपनिंग के बारे में कभी कुछ सोचा नहीं है। इससे पानी का फ्लो जितने बड़े पैमाने पर होना चाहिए, उतना वह होता नहीं है, जिससे एक बड़ी परेशानी मुंबई शहर के लोगों को झेलनी पड़ती है। महोदया, पिछले सौ सालों में नाला वाइडनिंग या नदी वाइडनिंग का तो कोई प्रोगाम देश में हुआ ही नहीं है, इसीलिए मुंबई शहर और महाराष्ट्र में भी नहीं हुआ है, जिससे मुंबई शहर का भी वही हाल है। लेकिन मैं मानता हूँ कि ड्रेज़िंग भी नहीं होता है। नदी-नालों का तो होता नहीं है, लेकिन जो बड़े-बड़े समुद्र होते हैं, उसकी भी ड्रेज़निंग, जैसे गोराईखाड़ी है या वरसोवा बीच है, उन सारे बीचों की भी नहीं होती है। ड्रेज़िंग का हर साल बजट में प्रावधान होता है, लेकिन काम नहीं होता है। उसकी वजह से भी शहर का जितना पानी समुद्र में जाना चाहिए, उतना जाता नहीं है। हर साल नालों में से सिर्फ कचरा निकालने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकिन वह भी लीपापोती ही होती है। हर साल दो महीने पहले काम शुरू करते हैं, सारे राजनैतिक दलों के लोग विज़िट करते हैं, वर्तमान पत्र में छप कर आता है, 80 प्रतिशत से शुरू होते हैं और 90 प्रतिशत तक जा कर रुक जाते हैं। शत प्रतिशत नालों की सफाई हुई है, इसके बारे में कभी भी कमिश्नर कुछ कहते नहीं हैं, क्योंकि वे आईएएस ऑफिसर्स होने की वजह से बहुत ही चातुर्य से काम करते हैं। यह मुंबई शहर की स्थिति है।

महोदय, अगर इन सारी समस्याओं से हमें निपटारा पाना है, छुटकारा पाना है तो मैं मानता हूँ कि देश के प्रधान मंत्री ने जैसे स्वच्छ भारत अभियान का नारा दे कर देश के सारे लोगों को इसमें जोड़ दिया, वैसे ही इन सारे कामों में भी हमको देश के सारे लोगों को जोड़ना पड़ेगा। मैन्युअली हमको काम करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद करना पड़ेगा। महोदय, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में प्लानिंग करने में बहुत सारा समय निकल जाता हैं, टेंडर में अंडरस्टैंडिंग जो होती है और स्टैंडिंग कमेटी में जो होता है, उससे बड़ी परेशानी होती है, इसलिए सारे कामों को बंद कर के आने वाले पांच सालों में पूरे देश में यह कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद कर, सब मैन्युअली काम करेंगे तो यह सारा काम बहुत कम पैसों में होगा और बहुत अच्छा काम होगा, यह मेरा मानना है।

महोदय, मैं अंतिम दो मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मुंबई शहर की जो रोड वाइडनिंग है, मैंने नितिन गडकरी जी को चिट्ठी भी लिखी है, हालांकि यह उनके विभाग के अंतर्गत आता नहीं हैं, क्योंकि वे नैशनल हाईवे का काम करते हैं। लेकिन मुंबई शहर से उनका बहुत बड़ा लगाव है। जब वे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे, तब उन्होंने 67 फ्लाइओवर और ब्रिजेस बना कर एक बहुत बड़ी उपलब्धि कमाई थी। पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी वे बहुत फेमस हो गए हैं और उसी माध्यम से वे इन दिनों काम कर रहे हैं। मुंबई शहर का नागरिक होने के नाते बहुत लंबे समय तक मैंने उनके साथ काम किया है। मैं चाहता हूँ कि नितिन गडकरी जी का जो अनुभव है, और उनके पास अधिकारियों के साथ जो संपर्क है, उसका मुंबई शहर के लोगों को लाभ मिले। मैंने उनको एक चिट्टी लिख कर कहा है कि महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री, मुंबई शहर के मेयर और कमिश्नर, इन सारे लोगों की एक बैठक उनको बुलानी चाहिए और इस

समस्या का समाधान निकालना चाहिए। मुंबई शहर एक जग-प्रसिद्ध शहर होने की वजह से वहां जो भी गतिविधियां होती हैं, पूरी दुनिया में इसका मैसेज पहुंच जाता है। इसलिए मुंबई शहर को जल्द गति से एकदम ठीक-ठाक करने की आवश्यकता है। आवश्यकता पड़ेगी तो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मुंबई महा-नगरपालिका को पैसा भी देना चाहिए। आने वाले पांच सालों में मुंबई में जो 44 फीट तक के रोड हैं, उन सारे रोड्स को अगर हम कंक्रीट का बनाते हैं तो इसका लाभ मुंबई को होगा और यह वाइडनिंग का काम वार फुटिंग पर करना चाहिए। इस मामले में नियम बदले गए हैं। अब हम बिल्डरों को फोर टाइम एफएसआई भी दे रहे हैं। अगर बिल्डर नहीं करते हैं तो सरकार को कोई और नया तरीका ढूंढ कर स्वयं अपने आप कर के सारे सड़कों को 44, 60 और 90 फीट का करना चाहिए। साथ ही स्टॉर्म वॉटर ड्रेन अगर हम प्लान करते हैं तो मुंबई शहर में 50 प्रतिशत रिलीफ लोगों को मिलेगा।

(1730//KMR/CS)

महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बार फिर नितिन गडकरी जी से विनती करना चाहूँगा कि अगर वे बहुत ही जल्दी एक ज्वाइंट मीटिंग लें तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आने वाले पाँच साल में मुम्बई शहर के लोगों को एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने 15 साल मुम्बई महानगर पालिका में काम किया है।

महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका अभिनन्दन करता हूँ और आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

(इति)

***श्री राम कुमार शर्मा (सीतामढ़ी):** माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे नियम 193 के अधीन बाढ़ और सूखे की स्थिति पर बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। भारत के पास जहां दुनिया की आबादी का 16 प्रतिशत से ज्यादा अबादी है, वहीं दुनिया के जल संसाधनों का लगभग 4 प्रतिशत और दुनिया के भू-भाग का 2.45 प्रतिशत इसके पास है। यहां तक कि देश में उपलब्ध ताजा जल संसाधनों के वितरण के मामले में भी क्षेत्र और समय (देश के विभिन्न भागों के बीच और एक साल में अलग-अलग समय में) के स्तर पर भिन्नता है।

महोदय, मैं बिहार के सीतामढ़ी जिले से आता हूं और यह उत्तर बिहार का वह क्षेत्र है, जो हर वर्ष बाढ़ की विभीषिका झेलता है। इस बार उत्तर बिहार में बाढ़ ने बहुत अधिक तबाही मचाई थी। कुछ दिनों तक तो सभी का ध्यान इसकी तरफ गया। हेलिकॉप्टर इत्यादि से दौरे भी हुए जैसा अक्सर होता है, फिर अगली बाढ़ तक इसे भूला दिया जाता है। भूल नहीं पाते हैं वे लाखों लोग जो बाढ़ में अपना सब कुछ खो बैठते हैं। इन्हें अपना जीवन फिर लगभग शून्य से शुरू करना पड़ता है।

इस बाढ़ ने उत्तर बिहार को कुछ अभिशप्त इलाके की तरह छोड़ दिया। सभी जगह बाढ़ से निपटने की अव्यवस्था की चर्चा हुई। अव्यवस्था के कई कारण भी गिनाए गए हैं, जिनमें वहां की असहाय गरीबी आदि है, लेकिन बहुत कम लोगों को इस बात

---

* Laid on the table.

का अंदाज होगा कि उत्तर बिहार एक बहुत ही संपन्न क्षेत्र रहा है। इस प्रदेश में मुजफ्फरपुर की लीचियां, पूसा ढोली की ईख, दरभंगा का शाहबसंत धान, शकरकंद, आम, चीनिया केला कौन भूल सकता है। परन्तु हर वर्ष आने वाली बाढ़ ने इन सबको काफी क्षति पहुंचाई है।

बाढ़ आने पर सबसे पहला दोष तो हम नेपाल को देते हैं। नेपाल एक छोटा सा देश है। बाढ़ के लिए हम कब तक उसे दोषी ठहराते रहेंगे? कहा जाता है कि नेपाल ने पानी छोड़ा, इसलिए उत्तर बिहार बह गया। परंतु आज आवश्यकता है कि हम ऐसे सुरक्षात्मक कदम उठाए जिनमें बाढ़ के प्रवाह को अवशोषित करने और विनियमित करने के लिए भंडारण बांधों का निर्माण, जल प्लावन को रोकने के लिए तटबंधों का निर्माण आदि जैसे संरचनात्मक उपाय शामिल हैं। साथ ही जहां कहीं भी जटिल जल निकासी कारणों से तटबंधों का निर्माण संभव नहीं हो तो वहां गांवों को ऊपर स्तर तक उठाने और उन्हें पास के सड़कों से जोड़ने के लिए योजनाओं को भी सक्रियता से क्रियान्वित किया जाए।

(इति)

1730 hours

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Mr. Deputy Speaker, Sir, thank you for giving me opportunity to participate in the discussion under Rule 193 on recent flood and drought situation in various parts of the country.

Sir, first of all, I convey my sincere thanks to hon. Home Minister, Shri Raj Nath Singh-ji, for acceding to our request and sending his MoS Shri Kiren Rijiju-ji to Kerala to visit the flood-affected areas. Shri Kiren Rijiju-ji came to my District Alleppey and also to Kuttanad in my Constituency. He was eye witness to the situation prevailing in Kuttanad, Alleppey and other areas. I convey my sincere thanks to Shri Kiren Rijiju-ji who visited the flood-affected areas and interacted with the affected families and saw for himself the situation throughout Kerala and specifically in Kuttanad.

Sir, the present monsoon is unprecedented and such a monsoon never occurred in the past in Kerala, especially in Kuttanad in Alleppey District. More than 500 relief camps are working in Kuttanad now. About 1,50,800 inmates are living in those relief camps. There are more than 25,000 inmates in relief camps In Upper Kuttanad also. The relief camps are facing severe shortages. There

is no sufficient food, water, medicines, gas for preparation of food, vegetables, coconut oil, etc. The State Government is providing maximum support but we need more. In the past, there used to be about 25 or 50 relief camps. This time the number of relief camps in Kuttanad itself is about 500 and there are relief camps in Upper Kuttanad also.

Electricity, water supply, ration shops, everything is affected by the heavy floods in Kuttanad. Temples and churches there have not opened over the last one week because there is water inside and outside the temples and churches. This is the pathetic situation there in Kuttanad.

I do not need to explain the speciality of Kuttanad. Everybody knows that Kuttanad is a backwaters area lying below the sea level. The entire water from the rains falling on Western Ghats flows into Kuttanad. Even if there is no rain in Kuttanad, if it rains in Western Ghats, that water comes into Kuttanad and it adversely affects the lives in Kuttanad area.

Sir, 90 per cent of the Houses in the area are fully damaged. Ninety per cent of the houses remained under water for periods between one week to two weeks. Therefore, even after water

receded from the houses, the houseowners cannot go back because the houses are rendered unfit for living as they stayed under water for such long periods. The situation is that these houses can collapse any time. This is a very dangerous situation.

(1735/GM-RV)

School buildings, anganwadis, libraries, Government offices and everything else is affected in Kuttanad. Supply of milk and newspaper and telephone connectivity are totally cut off in Kuttanad for last one week. Mobile connectivity is also not available there. Cars, bikes, scooters and cycles have been all washed away. Cattle don't have shelters. There are thousands of cattle in Kuttanad. Every house has some cattle.

HON. DEPUTY SPEAKER: Tell me what is the relief you want for your area?

… (*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): My constituency is severely affected. Hon. Member, why are you interfering? There are 10 dead bodies in the mortuary because they could not bury or cremate them. Hindus wanted to cremate their dead bodies and Christians wanted to bury theirs but the condition is not workable for

that. This is the situation we are facing in Kuttanad. I am not going into the details. Schoolchildren lost their school uniforms, textbooks etc. Schools and colleges are closed for last two weeks because of heavy rains. The road connectivity is also broken. The Kuttanad-Alleppey-Changanassery Road that is the main road connecting Kuttanad and Alleppey to other areas has also collapsed and transportation is suspended. Majority of the people are in isolated areas; they are in different islands. The outer bund of 90 per cent of the *padasegaran* or paddy fields was broken; paddy fields were washed out and crores and crores of rupees invested by farmers in paddy fields have also been washed out.

The UPA-I Government announced the Kuttanad package for solving the problem of farmers of Kuttanad. The UPA-I Government appointed Dr. M.S. Swaminathan, who is a well-known agriculture scientist and who himself was born in Kuttanad, to study the case and he submitted a report to the UPA-I Government. The UPA-I Government approved and accepted the Kuttanad package without any correction. The UPA-II Government gave permission for implementation of the Kuttanad package. The Government of Kerala is the implementing agency. Ministry of Water Resources and

Ministry of Agriculture are giving funds from the Government of India. The first phase of the Kuttanad package is already over. But the second phase has not been taken up because of shortage of fund. My dear colleague Shri N.K. Premachandran was the Minister of Water Resources in Kerala at that time. Dr. M.S. Swaminathan prepared a detailed report on the problem of farmers of Kuttanad and submitted it to the Government of India. Based on that report, the second phase of the Kuttanad package needs to be implemented immediately. Hon. Minister of Agriculture is here. The hon. Minister of Water Resources is not here, but he must be aware of the Kuttanad package. The second phase of the Kuttanad package is for protection of farmers' interest because the outer bunds of the *padasegaran* is very weak and poor.

(1740/RSG/MY)

Whenever there is a heavy rain in Kuttanad, the entire outer bund will be broken. So, we want to strengthen the outer bunds of the paddy fields. The Alappuzha-Changanacherry canal's second phase, the Thanneermukham barrage, and the Thottapalli spillway are the components related to the Kuttanad area. These three components should be completed immediately. The Ministries of

Agriculture and Water Resources should come forward and take up this work immediately. The Agriculture Ministry under the RKVY and the Water Resources Ministry under the Flood Management Scheme should give sufficient funds. They can sanction the funds.

HON. DEPUTY SPEAKER: You have taken ten minutes. Please wind up now.

… (*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Wherever the outer bunds are strengthened, wherever the *kayal pedasegaran* was strengthened, flood has not affected; but wherever the *pedasegaran* has not been strengthened and wherever the outer bund is not strengthened, they are badly affected. Therefore, I would like to request the hon. Agriculture Ministry and also like to request the hon. Water Resources Minister to have a meeting with the stakeholders concerned and sort out this problem and allot Rs. 1,000 crore for restoring the *pedasegaran* outer bund. … (*Interruptions*)

I am concluding. I will not take much time. I am always completing my speeches within the time but this is about my constituency which has been very badly affected. Everybody knows Kuttanad is a backwater area. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: You have already taken 12 minutes. Many hon. Members are there to speak.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Let him complete, Sir. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: I have already given him 12 minutes. How can I give more time?

You please wind up quickly.

… (*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): There is another report on the Programme for Preventing Flood Situation in Kuttanad. Unfortunately, that plan was also pending with the Ministry. … (*Interruptions*)The Government allotted funds for an initial expenditure of only Rs. 80 crore. That is a very small amount. … (*Interruptions*) At least Rs. 250 crore has to be sanctioned for initial relief work. I also request that Kuttanad may be declared as a Special Agricultural Zone. … (*Interruptions*)

(ends)

1743 बजे

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार): उपाध्यक्ष महोदय, देश में सूखे तथा बाढ़ की जो स्थिति है, उसकी चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे रूल 193 के माध्यम से मौका दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' के ऊपर केन्द्र सरकार द्वारा एक रिपोर्ट बनाई गई थी। उस रिपोर्ट के अंदर एक बड़ी गंभीर चीज सामने आई कि केन्द्र सरकार मानती है कि वर्ष 2025 तक हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के अंदर इरिगेशन के लिए ग्राउंड वाटर की लगभग समाप्ति हो जाएगी। बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि वर्ष 2016-17 के अंदर इसी सदन में माननीय वित्त मंत्री जी ने जब बजट पेश किया तब 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' के लिए दस हजार करोड़ रुपये रखे। सब ने इसके लिए बधाई दी थी कि सरकार कहीं न कहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना पूरा करेगी, चाहे वह इंटरलिंकेजेज़ ऑफ रिवर की बात हो। सरकार उसके ऊपर कदम उठा रही है। मगर जब बजट को रिवाइज़ किया गया तो रिविज़न के बाद वर्ष 2016-17 के अंदर फसल सिंचाई योजना के लिए मात्र 5,182 करोड़ रुपये रखे गये। इसका मतलब है कि लगभग 48 परसेंट की कटौती की गई।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जरुरत है कि हम पानी को इस देश की नेशनल प्रोपर्टी बनाने का काम करें। हम थोड़े दिन पहले देख रहे थे कि तमिलनाडु तथा कर्नाटक के बीच पानी का विवाद था कि उन्हें पर्याप्त पानी नहीं दिया जा रहा है। इस सेशन में यह चीज़ सामने आ रही है और यह लड़ाई है कि पानी ज्यादा दिया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, यही हालात हरियाणा के अंदर भी है। आज से डेढ़ साल पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सतलुज-यमुना लिंक का 40 साल पुराना फैसला दिया और केन्द्र सरकार को डायरेक्ट किया कि अगर पैरा मिलिट्री फोर्सेज़ की जरुरत पड़े तो उसे लगाओ, मगर सतलुज-यमुना लिंक का निर्माण किया जाए। परंतु आज तक केन्द्र सरकार, हरियाणा सरकार तथा पंजाब सरकार ने एक बार भी हमारे पानी के अधिकार के लिए कोई भी कदम उठाने का काम नहीं किया है।

(1745/CP/RK)

उपाध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा की जो रिक्वायरमेंट हैं, वह लगभग 36 मिलियन एकड़ फीट पानी की है, लेकिन आज हरियाणा को मात्र 14 मिलियन एकड़ फीट पानी दिया जाता है। उसके बाद केन्द्र की सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा दिल्ली की प्यास मिटाने के लिए एडीशनल पानी देता है। मैं आपके माध्यम से जरूर सरकार से पूछना चाहूंगा कि सरकार हरियाणा के किसान की, हरियाणा के आम जनजीवन की पानी की जो किल्लत है, उसे पूरा करने के लिए आने वाले भविष्य में क्या कदम उठाएगी? क्या सरकार सतलज-यमुना लिंक का जो निर्माण है, उसे पूरा करवाने का काम करेगी? आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर यही निर्णय आया है कि पानी का बंटवारा बाद में देखा जाएगा, लेकिन उस नहर का निर्माण तुरन्त प्रभाव से किया जाए। आंकड़े यह भी बताते हैं, जो इस सदन में दिए गए कि 2015 के अंदर 37 परसेंट मानसून हरियाणा प्रदेश में कम हुआ, 2016 के अंदर 27 प्रतिशत कम हुआ, जो नार्थ-ईस्ट मानसून आता है, वह तो लगभग 80 प्रतिशत कम है, 2017 के

अंदर 26 परसेंट बारिश कम हुई। दिन-प्रतिदिन जो मानसून का डिक्लाइन है, उससे कहीं न कहीं हमारे एग्रीकल्चर ग्रोथ के ऊपर भी फर्क पड़ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, बरवाड़ा लिंक जो भाखड़ा का एक हिस्सा है, उसका पानी का जो शेयर हमारे पास आना चाहिए था, वह 1,750 क्यूसिक होना चाहिए। उसकी रेजिंग हुई, 1,400 क्यूसिक पानी आया। लगभग 325 क्यूसिक पानी जो हमें एडीशनल मिलना था, राजस्थान की सरकार ने एक पत्र पंजाब को लिखकर उसकी रेजिंग रोक दी। आज वह डिसप्यूट सॉल्व हुआ, तो पंजाब की सरकार ने उस डिसप्यूट को आज तक कंप्लीट नहीं होने दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से और केन्द्र सरकार से यह मांग करता हूं कि जल्द से जल्द बीएमएल, बरवाड़ा लिंक का जो विवाद है, उसे सार्ट आउट कराकर कराया जाए। हमारे मात्र चार जिले हैं, जिनको भाखड़ा का पानी मिलता है, उसके 325 क्यूसिक पानी को जल्द से जल्द हमारे बीच में पहुंचाने का काम करें।

केन्द्र की सरकार ने पिछले बजट में 15 सौ करोड़ रुपये रेणुका डैम के लिए रखे थे। सबने इस सदन में तालियां बजाई थीं कि यमुना के अंदर अब पानी की स्टोरेज की कैपेसिटी बनाई जाएगी, मगर आज तक डेढ़ साल में एक कदम भी रेणुका डैम के निर्माण के लिए केन्द्र की सरकार ने नहीं उठाया। अगर सरकार चाहती है कि पानी को बचाया जाए, जो मानसून का पानी वेस्ट होता है, उसे हम पहाड़ों में स्टोर करें, तो सबसे जरूरी है कि यमुना के जो टाप हिल्स हैं, उसके अंदर रेणुका, कसाव और लखवाड़ डैम का निर्माण तुरंत प्रभाव से कराया जाए। जब ये तीन डैम बनेंगे, तो कहीं

न कहीं जो हरियाणा वाटर डेफिसिट है, उसको वाटर सरप्लस बनाने में केन्द्र सरकार की तरफ से हमें मदद मिलने का काम होगा।

आज किसान की हालत की बात करते हैं। पानी की कटौती के कारण यह हालत है कि हमारे 40 गाँव के किसानों को पीने के पानी के लिए भी राजस्थान के अंदर से 1,500-1,800 रुपये प्रति टैंकर के हिसाब से दाम चुकाकर अपनी प्यास मिटानी पड़ती है। आज केंद्र सरकार ड्राउट की बात कर रही है तो उसे आम जनजीवन के पीने के पानी की व्यवस्था बनाने का भी काम करना चाहिए।

महोदय, अगर यही हालत रही, तो 40 गाँव तो केवल आदमपुर-नलवा के अंदर हैं, 12 गाँव नारनौंद के अंदर हैं और इसके साथ-साथ उचाना के अंदर भी 7 ऐसे गाँव हैं, जहाँ आज पानी की किल्लत है। मेरे लोक सभा क्षेत्र में लगभग 80 ऐसे गाँव हैं, जहाँ ग्राउंड वाटर का लेवल इतना इनक्रीज हो चुका है कि वहाँ पर सेम आ चुकी है। आज कहीं न कहीं सरकार को ऑल्टरनेटिव देखना चाहिए, चाहे वहाँ पम्पिंग सेट बनाए जाएं, चाहे ड्रेन्स बनाई जाएं, यह सुविधा उन लोगों तक सिंचाई योजना के माध्यम से पहुँचानी पड़ेगी, जिससे किसान अपनी खेती को प्रॉपर तरीके से समृद्ध तौर पर आगे ले जाने का काम करेगा। मैं दोबारा जरूर इस बात को बोलना चाहूँगा कि हमारी फ्यूचर जनरेशंस को बचाने के लिए, पानी की किल्लत को पूरा करने के लिए आज यह कड़ा फैसला केन्द्र सरकार को लेना पड़ेगा कि पानी को आज नेशनल प्रॉपर्टी बनाया जाये। स्टेट्स आज डिस्प्यूट्स में जा सकते हैं। चाहे सिंगापुर हो, चाहे आस्ट्रेलिया हो या यू.एस. हो, पानी आज वहाँ पर नेशनल प्रॉपर्टी है। वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि पानी का स्टेट शेयर कितना होगा। …(व्यवधान) हमारे एरिया में पानी की किल्लत

होती है और कई एरियाज में बाढ़ आती है।...(व्यवधान) अगर पानी को नेशनल प्रापर्टी बनायेंगे, तो इसका बहुत लाभ होगा। ...(व्यवधान) आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

(इति)

*DR. PRABHAS KUMAR SINGH (BARGARH): I may kindly be allowed to lay a few lines on the discussion under rule 193 on the recent flood and drought situation in the country.

I would like to draw the attention of Hon'ble Minister for Ganga Rejuvenation and Water Resources to intervene in the Mahanadi Water Dispute between Odisha and Chhatisgarh due to multiple construction of dams in the upper Mahanadi valley in Chhatisgarh and inappropriate water control by the water station, flood situation is created in the downstream of Mahanadi in Odisha. Recently, due to heavy rain in Odisha, a large number of area including paddy field is inundated resulting in crop damage. Therefore, adequate compensation should be given to the farmers of Odisha. Construction of the dam should be stopped.

I would like to request the Minister to provide adequate funds to correct the damage by flood and drought in Odisha as demanded by Government of Odisha.

---

*Laid on the Table

I support Shri Kalikesh Kumar Singh Deo who spoke from our party.

Thanking you, Sir.

(ends)

***श्री भैंरो प्रसाद मिश्र (बांदा) :** माननीय अध्यक्ष जी, आज सदन में जो नियम 193 के तहत बाढ़ एवं सूखा पर चर्चा हो रही है वह बहुत ही जरूरी विषय है, जिस पर आज गम्भीर विचार-विमर्श हो रहा है। मान्यवर, हम चर्चा तो कई बार सदन में इस विषय पर करते हैं, लेकिन इस विषय पर कार्य योजना प्रभावी लागू करने का कार्य नहीं होता है। मैं आशा करता हूँ कि आज जो सदन में इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और महत्वपूर्ण सुझाव आये हैं उनको यथाशीघ्र लागू करने का कार्य किया जायेगा। आज देश के बड़े भाग में कम बारिश के कारण सूखे के हालात हैं। वहीं कुछ भागों में अतिवृष्टि से नुकसान हो रहा है। इन विषम प्राकृतिक विषमताओं के लिए वैज्ञानिकों को लगाकर इसका स्थाई उपाय करने की जरूरत है। मेरे बुन्देलखण्ड सहित उत्तर प्रदेश के करीब 30 जिलों में कम बारिश से विशेष सूखे के हालात हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र चित्रकूट एवं बांदा एवं पड़ोस के जनपद महोबा में बहुत ही हालात खराब हैं। अधिकतर खेत खाली पड़े हैं। खरीफ की फसलों की बुआई नहीं हुई है। कहीं-कहीं जिन्होंने बुआई कर दी थी उनकी फसलें उगी नहीं है। जो उग आई थी वह सूख गई हैं। बुन्देलखण्ड में अक्सर सूखा पड़ता है। केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार ने इस ओर ध्यान तो दिया है, लेकिन अभी वह कार्य योजनायें नीचे तक लागू नहीं हो पायी हैं। यहाँ जानवरों की अन्नाप्रथा गम्भीर समस्या थी, अब और भी जानवरों को चारे की समस्या से विकराल रूप धारण करेगी।

---

* Laid on the Table

अस्तु मेरा केन्द्र एवं प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र चित्रकूट एवं बांदा व महोबा सहित सभी जिलों में पर्याप्त राहत के उपाय किये जायें एवं यहाँ पर कृत्रिम वर्षा कराने की व्यवस्था की जाये और किसानों को राहत अनुदान यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाये।

(इति)

*Laid on the Table

(1750/NK/PS)

श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी (बस्ती): उपाध्यक्ष महोदय, आपने बाढ़ और सुखे जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज देश में किसी क्षेत्र में बाढ़ आई है और किसी क्षेत्र में सूखा। मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के बस्ती जिले से सांसद हूं। प्रति वर्ष नेपाल की पहाड़ियों से पानी छोड़ा जाता है, जो गोंडा और फैजाबाद से होते हुए बस्ती में घाघरा नदी में आता है। इससे हर साल सैकड़ों गांव प्रभावित होते हैं। इससे जानमाल का नुकसान होता है। कृषि योग्य भूमि और जहां फसल है, उसका भी नुकसान होता है। इस साल भी सैकड़ों गांव ऐसे हैं, जहां फसलों का नुकसान हुआ है। लोग मजबूर होकर बांध पर रहने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय तक जितनी बरसात होनी चाहिए थी उससे 46 प्रतिशत कम बरसात हई है। बस्ती सहित पूर्वांचल के सभी जिलों में सूखे के हालात हैं, उसके कारण धान की रोपाई अभी तक नहीं हो पा रही है, जितनी होनी चाहिए। किसान भी मजबूर है, वह सोच रहा है कि अगर बरसात नहीं होगी तो धान की रोपाई करने से नुकसान होगा।

आज लोक सभा में इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। इसका निश्चित रूप से समाधान निकलना चाहिए। देश के पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बाढ़ और सूखा से निपटने के लिए एक योजना बनाई थी। नदी को आपस में जोड़ा जाए, जिससे जहां पानी की कमी है, वहां पानी पहुंचाया जाए, जहां ज्यादा पानी है उस पानी को सूखे वाले इलाके में पहुंचाया जाए। मुझे लगता है कि यह योजना देश के हित में है, किसानों के हित में है, इस योजना को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके पहले जब भी केन्द्र सरकार से राज्यों ने मांग की, मेरे पास एक आंकड़ा है, कांग्रेस सरकार ने पिछले

पांच वर्षों में राज्य आपदा कोष में 33,580 करोड़ राज्यों को दिया था, लेकिन हमारी सरकार को लगा कि यह पैसा बहुत कम है। मोदी जी की सरकार आने के बाद राज्यों की डिमांड को बढ़ा कर 61, 219 करोड़ रुपये आबंटित किया। मोदी जी की सरकार आने के बाद किसानों और मजदूरों के हित में तमाम योजनाएं बनाईं। अभी चौटाला जी चर्चा कर रहे थे कि प्रधान मंत्री सिंचाई योजना हमारे प्रधान मंत्री जी ने शुरू की है। उसमें हजारों करोड़ों रुपये की व्यवस्था सरकार ने की है। उसी प्रकार से जब किसानों का फसल नुकसान होता था, पहले अगर पचास प्रतिशत नुकसान होता था तब मुआवजा मिलता था, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद माननीय प्रधान मंत्री जी ने व्यवस्था की कि 33 प्रतिशत भी नुकसान होने पर मुआवजा देंगे और डेढ़ गुना मुआवजा देंगे। किसानों को खुशहाल बनाने के लिए और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए, किसानों का कोई नुकसान न हो इस दिशा में सरकार ने प्रयास किया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में बाढ़ से निपटने के लिए एक स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए। भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा हर वर्ष बस्ती जिले में घाघरा नदी पर बांध की मरम्मत और बाढ़ से निपटने के लिए सैंकड़ों करोड़ रुपये दिए जाते हैं।

मैंने इसके पहले भी लोक सभा में सुझाव दिया था, अगर बांध को स्थायी बना दिया जाए तो जो पैसे का अपव्यय होता है, वह बंद हो जाएगा और बाढ़ से निजात भी मिल जाएगा। भारत सरकार ने बस्ती जिले में यूपी-28 योजना चालू की है, उसमें हर वर्ष 25-50 करोड़ रुपये भारत सरकार देती है। अगर उस पैसे को एकत्रित करके

स्थायी बांध बना दें तो जो बस्ती और संत कबीर नगर में बाढ़ आती है, जो अम्बेडकर नगर में बाढ़ आती है, उससे निजात मिलेगी। इस दिशा में सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। यही निवेदन करते हुए और आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

(इति)

1754 hours (Hon. Speaker *in the Chair*)

1754 hours

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you, Madam Speaker, for giving me this opportunity to intervene in this debate.

Madam Speaker, the recent floods have adversely affected 91 districts in 12 Indian States. Around 511 people have died and around 176 people are injured due to the floods. The worst affected State by this flood in this country is Kerala. Comrade Shri P. Karunakaran, Shri K.C. Venugopal and Shri Kodikunnil Suresh have already narrated the incidents of the devastating effects which have been caused due to the floods in the State of Kerala.

(1755/RC/SK)

I fully support the observations and recommendations made by my learned friends from the State of Kerala. I fully support their demands also.

Madam, you may kindly see that more than one lakh people have been flood affected. Alappuzha, Kottayam, Pathanamthitta, Ernakulam, Thrissur and my district, Kollam are the worst affected districts during the recent floods. The death toll comes to more than

1.18 lakh people. There are 606 relief camps in the State of Kerala. I would not go into the details. Just now, my learned friend, Shri Kodikunnil Suresh has narrated the incidents of devastating effect in Kuttanad, the rice bowl of the State of Kerala. Ninety per cent of kharif crop in Kuttanad has also been totally adversely affected. Only Rs.80 crore have been granted as central assistance.

Madam, I would like to make one more suggestion regarding sea erosion. Shri K.C. Venugopal has also cited that. The entire coastal State of Kerala is adversely affected and the sea wall is totally dismantled. So my suggestion to the hon. Minister and the Government is that sea wall construction should also be incorporated as a mitigating measure under the National Disaster Management. That should also be incorporated for giving relief.

Madam, other than flood, I would like to say that some concreate political decision has to come out of this discussion. Otherwise, there is no meaning in having this discussion. I would like to state some suggestions and some reports also. Kindly spare me some time so that I can enlighten the Government as well as this House regarding the latest figures.

According to the National Disaster Management Authority report, India is highly vulnerable to floods. Out of the total geographical area of 329 million hectares, more than 40 million hectares are found to be flood-prone.

Madam, you may kindly see over 1600 people die every year due to floods and it affects 32 million people. More than 92000 cattles are lost every year. Seven million hectares of land is affected every year. Average damage cost per year is Rs.5600 crore.

The flood-prone States include Assam, West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Kerala, Gujarat, Uttar Pradesh, Haryana and Punjab. You may kindly see another very important point which I would like to make. India accounts for one-fifth of the global deaths due to floods. A very interesting study has been done by the World Bank which says that climate change will lower the standard of living of nearly half of Indian population by 2050. The worst affected States would be Chhattisgarh and Madhya Pradesh.

I would like to draw the attention of the hon. Minister to another very important figure. In between 1953 to 2017, *i.e.*, 64 years 1,07,487 people died due to floods. This is the report of the Central Water Commission. Damage to houses, crops and public utilities

was reported to be worth Rs. 3,65,860 crore during these 64 years because of floods. It means three per cent of India's current GDP has been lost during these 64 years. This is the scenario of flood situation in India.

Now what are the main reasons for flood? They are – high intensity of rainfall in short duration, poor and inadequate drainage capacity in our country, unplanned reservoir regulation, failure of flood control structures, and loss of wetlands, lakes, reservoirs and other water bodies.

The basic and the scientific reason for the flood is nothing but climate change. As regards climate change, India is one of the world's most vulnerable regions. It has increased the frequency of downpours as well as the gaps between rainy days during the monsoon season. The temperatures have been rising across South Asia region and are projected to continue increasing for the next several decades. This temperature increase will result in increased frequency of downpour resulting in frequent flooding. That is what is happening in our country also.

Madam, the question is as to how to address this question. My first suggestion is that we should have a long term approach. What

is the long term approach? Uncontrolled exploitation of natural resources, ignoring the ecology and environment in the name of development are the main reasons for the climate change.

(1800/SNB/RPS)

Madam Speaker, everybody is concerned about the GDP and economic growth. Ignoring the ecological and environmental aspects we are mainly concentrating on the GDP and economic growth and that is the reason why this climate change is happening. So, the issue of climate change has to be addressed effectively. This House had, on an earlier occasion, discussed the subject of Sustainable Development Goals and I would like to suggest to you to allow a separate discussion on the subject `Climate Change' so that we can discuss this in detail.

माननीय अध्यक्ष : आप एक मिनट रुकिए।

अभी छः बज गए हैं। अगर आप सभी सहमत हों तो सदन का समय एक घण्टा बढ़ा देते हैं, मगर एक घण्टा बढ़ाने पर आप लोग देख लेना कि अगर दो-तीन मिनट बोलकर अपनी बात समाप्त करेंगे तो वह रिप्लाई के लिए ठीक रहेगा।

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Is it including the reply?

HON. SPEAKER: Yes. But we will see that later.

आप सभी लोग समय का ध्यान रखें क्योंकि अच्छा-खासा डिसकशन हो चुका है।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I would like to suggest a few other measures. First is conservation of wetland and paddy conservation. Since we have Acts on Forest Conservation, Wildlife Protection, Environment Protection, that is the reason these ecological components are protected to an extent. My suggestion is a National Wetland Conservation Act should be enacted by this Parliament to protect the wetlands.

My second point is about desilting of dams. If one examines this issue, one would find that capacity of most of the water reservoirs has come down. On an average, 20 per cent of the capacity of the reservoirs have declined because of siltation. Let there be a national programme on de-silting of reservoirs so the sand for construction can be used; capacity of reservoirs will be augmented and we can declare a moratorium on sand mining of rivers for a period of ten years so that the rivers can be protected. The rivers are dying because of sand mining and waste dumping.

Madam, the next question is how to mitigate the damage. In order to mitigate the damage my suggestion is that we have to equip

the National Disaster Management Authority and also the State Disaster Management Authority to handle the situation. I would like to suggest that a long-term contingency national plan has to be drafted so as to address the flood situation. That has to be formulated at the earliest by the National Disaster Management Authority.

The compensation given is very meagre. The Government may consider all these suggestions and I would like to request the Central Government to give a special financial package to the State of Kerala to meet the present crisis.

With these words, I conclude.

Thank you.

(ends)

(FOR REST OF THE PROCEEDINGS,
PLEASE SEE THE SUPPLEMENT.)